वार्षिक रिपोर्ट
1971-72

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अप्रैल 1973 ● चैत्र 1895

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 1973

प्रकाशन विभाग में, श्री म. च. वर्मा, सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-16 द्वारा प्रकाशित और राकेश प्रेस, अजीज गंज, दिल्ली-6 में मुद्रित ।

विषय-सूची

परिषद् तथा इसके कार्यकलाप ... 1

1971-72 के महत्वपूर्ण कार्य ... 7

परिशिष्ट

1. परिषद् तथा उसकी समितियों के सदस्यगण ... 25
2. 1971-72 में हुई परिषद् और उसकी समितियों की बैठकों की कार्यवाहियों का सारांश ... 37
3. वर्ष 1971-72 के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की लेखा विवरणी ... 41
4. कैम्पसों का विकास ... 42
5. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान पुस्तकालय ... 44
6. पाठ्यक्रम विकास ... 46
7. राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना ... 58
8. राष्ट्रीय एकीकरण परियोजना ... 61
9. जनसंख्या शिक्षा ... 64
10. ग्रामीण प्रतिभा खोज योजना ... 66
11. परीक्षा सुधार ... 67
12. यूनेस्को रजत जयंती समारोह ... 69
13. व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को अनुदान ... 70
14. अनुसंधान अध्ययन, अन्वेषण और सर्वेक्षण ... 71
15. अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायातानुदान (जी० ए० आर० पी०) ... 88
16. प्रशिक्षण कार्यक्रम ... 92
17. विस्तार और क्षेत्र सेवाएँ ... 100
18. राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के साथ सहयोग ... 114
19. शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के साथ सहयोग ... 124
20. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ... 128
21. प्रकाशन ... 137

परिषद् तथा इसके कार्यकलाप

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की, जो एन० सी० ई० आर० टी० के नाम से प्रसिद्ध है, एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापना 1860 के सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन सितम्बर 1961 में की गयी थी। स्थापना हो जाने पर, परिषद् ने केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (1947), केन्द्रीय पाठ्य-पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो (1954), केन्द्रीय शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्ग-दर्शन ब्यूरो (1954), अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (1955), माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय (1955-1959), राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा संस्थान (1959), राष्ट्रीय समाज शिक्षा केन्द्र (1956), तथा राष्ट्रीय श्रव्य दृश्य शिक्षा संस्थान (1959), अपने हाथ में ले लिए। भारत सरकार द्वारा इन सभी संगठनों का गठन स्कूली शिक्षा की प्रगति के लिए सुविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि से किया गया था। इन संगठनों को हाथ में लेने के बाद, परिषद् ने अपने कार्यकलापों का पुनर्गठन किया ताकि यह प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

2. परिषद् का वित्त-पोषण पूर्णतया भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस समय, यह शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के शैक्षणिक पक्ष के रूप में कार्य कर रही है और यह स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय की नीतियों तथा मुख्य कार्य-क्रमों के तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में उनकी सहायता करती है। मोटे तौर पर परिषद् के कार्य ये हैं :—

(क) स्कूली शिक्षा से संबंधित अध्ययन, जाँच तथा सर्वेक्षण करना।

(ख) सेवा-पूर्व और सेवा कालीन प्रशिक्षण का आयोजन करना, खासतौर से उच्च स्तर पर।

(ग) विस्तार सेवाओं का आयोजन करना।

(घ) सुधरी हुई शैक्षिक तकनीकों तथा क्रियाओं का स्कूलों में प्रसार करना।

तथा

(ङ) स्कूली शिक्षा से संबद्ध सभी मामलों पर विचारों तथा सूचना के विकास-गृह के रूप में कार्य करना।

3. इस प्रकार के कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकने के लिए, परिषद् राज्यों के शिक्षा विभागों और विश्वविद्यालयों तथा स्कूली शिक्षा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए देश में स्थापित आम तौर पर सभी संस्थाओं के साथ निकट सहयोग से कार्य करती है। इसके अलावा, परिषद्, विश्व भर में इसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ निकट संपर्क रखती है। परिषद् द्वारा किए गए कार्यों के निष्कर्ष से जनता को अवगत कराने के लिए यह पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा साहित्य का प्रकाशन करती है।

4. परिषद् ने प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों और अनुसंधान कार्यकलापों को करने और उनको बढ़ाने के लिए अनेक संस्थाओं का गठन किया। परिषद् अपने क्षेत्र सलाहकारों के कार्यालयों की मार्फत सभी राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क रखती है।

परिषद् का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है।

5. दिल्ली में, परिषद् का राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है। इस संस्थान का मुख्य संबंध अनुसंधान, अल्पावधि प्रशिक्षण आदि से है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अनेक विभाग हैं, जैसे पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग, पाठ्यपुस्तक विभाग, अध्यापक शिक्षा विभाग, सामजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग, शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा आधार विभाग, विज्ञान शिक्षा विभाग, अध्यापन साधन विभाग, आधार सामग्री प्रक्रिया तथा शैक्षिक सर्वेक्षण एकक, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान पुस्तकालय, प्रलेखीय तथा सूचना सेवाएँ। प्रत्येक विभाग का संबंध उसी को सौंपी गयी परियोजनाओं से है। इसके अलावा परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कुछ आधारभूत कार्य भी किया जाता है। कुल मिला कर, जो अधिकांश जाँच पड़तालें की जाती हैं, वे व्यावहारिक किस्म की होती हैं और तात्कालिक उपयोगिता की दृष्टि से उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है।

6. केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली में बी० एड०, एम० एड०, तथा पी-एच० डी० पाठ्यक्रमों का प्रबंध है। उसका संचालन दिल्ली विश्वविद्यालय के संघटक कालेज के रूप में परिषद् द्वारा किया जाता है। इसको शीघ्र ही दिल्ली विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किए जाने की संभावना है।

7. परिषद् अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर में चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों का संचालन करती है। ये संस्थाएँ स्थानीय कालेज हैं जिनमें व्यापक प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा निर्वास सुविधाएँ हैं। वे चार-वर्षीय विषय वस्तु एवं शिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन करते हैं जिन्हें पूरा करने पर विज्ञान में बी० एससी०, बी० एड० तथा भाषाओं में बी० ए०, बी०एड० उपाधियाँ मिलती हैं। ये पाठ्यक्रम विश्व के कुछ अन्य देशों में प्रयुक्त विचारों को आत्मसात करते हुए तैयार किए

गए हैं। अनेक देशों में आमतौर पर यह विश्वास किया जाता है कि शिक्षा को इंजीनियरी, औषधि-विज्ञान जैसे व्यावसायिक विषय के रूप में माना जाना चाहिए और छात्रों को इन विषयों में और शिक्षण में साथ-साथ प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय कालेजों में चलाए जा रहे चार-वर्षीय पाठ्यक्रम इसी अवधारण को कार्यान्वित करने के लिए हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय कालेज एक-वर्षीय बी० एड० पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। ऐसे एक-वर्षीय पाठ्यक्रमों में विशेष महत्व के वे पाठ्यक्रम हैं जो विज्ञान, कृषि, वाणिज्य तथा भाषा से संबंधित हैं। प्रशिक्षण पा रहे छात्रों को हर मुमकिन सीमा तक, कार्य अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि स्कूलों में अध्यापक बनने पर वे उसका प्रसार स्कूलों में कर सकें। अजमेर, भोपाल और भुवनेश्वर स्थित तीन क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में एम० एड० पाठ्यक्रमों का प्रबंध है जबकि उनमें से दो (अजमेर और भुवनेश्वर) शिक्षा में पीएच० डी० तक की सुविधाएँ प्रदान करते हैं। ये क्षेत्रीय कालेज मुख्यतया अपने संबंधित क्षेत्रों में स्थित स्कूल शिक्षकों तथा शिक्षक प्रशिक्षकों के कार्य अनुभव के लिए सेवा कालीन शिक्षा पाठ्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। क्षेत्रीय कालेजों का इस ढंग से विकास किया जा रहा है कि वे देश के चारों क्षेत्रों के लिए आदर्श अथवा विशिष्ट केन्द्रों के रूप में कार्य करें। वे संबंधित क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ तथा राज्य के शिक्षा विभागों के साथ निकट सहयोग से कार्य करते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कालेज के लिए एक प्रबंध-समिति है जिसका अध्यक्ष उस विश्वविद्यालय का कुलपति होता है जिससे वह संस्था संबद्ध है। यह प्रबंध-समिति कालेज के सीधे हित के मामलों पर कार्यकारी समिति को सलाह देती है।

8. परिषद् का एक प्रकाशन एकक (विभाग) है जो परिषद् के विभिन्न संघटक एककों द्वारा तैयार की गई शैक्षिक सामग्री को प्रकाशित करता है। शैक्षिक सामग्री निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों में विभक्त है :—

(क) पाठ्यपुस्तकें और अध्यापक दर्शिकाएँ

(ख) पूरक पठन सामग्री

(ग) वार्षिक पुस्तकें (इयर बुक्स)

(घ) अनुसंधान अध्ययन तथा प्रबंध

(ङ) अनुदेश सामग्री

(च) विवरणिकाएँ और पुस्तिकाएँ

(छ) शैक्षिक पत्र-पत्रिकाएँ

(ज) विदेशी पुस्तकों के पुनर्मुद्रित संस्करण, आदि।

9. केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा संविभाग के मंत्री परिषद् की महासमिति के अध्यक्ष हैं। राज्यों के तथा विधानांगों वाले संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शिक्षा मंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद परिषद् के सदस्य होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, शिक्षा तथा समाज सेवा मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव, चार विश्वविद्यालयों के कुलपति (एक हर क्षेत्र से), भारत सरकार के 12 नामजद व्यक्ति जिनमें से चार अध्यापक होते हैं और कार्यकारी समिति के सभी सदस्य परिषद् के अन्य सदस्य हैं। इस प्रकार के गठन से उच्चतम स्तर पर और पारस्परिक सहमति से नीति विषयक निर्णय लेना संभव हो जाता है। इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने परिषद् से राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड के रूप में कार्य करने का निवेदन किया है।

10. परिषद् का प्रशासन एक कार्यकारी समिति करती है जिसमें शिक्षा और समाज सेवा के केन्द्रीय मंत्री अध्यक्ष और शिक्षा और समाज सेवा के राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होते है। केन्द्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में शिक्षा का एक उप-मंत्री भी इसका सदस्य होता है। परिषद् के निदेशक और संयुक्त निदेशक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, केन्द्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का एक-एक प्रतिनिधि, दो अध्यापक, परिषद् के संकायों के तीन सदस्य और दो जाने माने शिक्षाविद परिषद् की कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य हैं। यह कार्यकारी समिति परिषद् के कार्यों से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेती है। शैक्षणिक मामलों पर निर्णय लेने में कार्यकारी समिति की सहायता के लिए एक कार्यक्रम सलाहकार समिति है जो परिषद् के कार्यक्रमों की जाँच करती है और उन्हें चालू करती है। इस समिति में परिषद् की संकाय के अलावा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागों और राज्य शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि होते हैं। एक वित्त समिति वित्तीय प्रभाव वाले सभी मामलों पर कार्यकारी समिति को सलाह देती है जबकि प्रशासनिक समिति प्रशासनिक मामलों में सहायता करती है।

11. इसके अलावा, कार्यकारी समिति आमतौर पर स्थायी समिति की नियुक्ति करती है, जो विभिन्न विशिष्ट प्रश्नों पर विचार करती है और जिनमें परिषद् के प्रतिनिधि और भारत के विभिन्न विभागों के इस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। इस प्रकार विज्ञान में अध्ययन समूहों से संबंधित समस्याओं, देश में विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए यूनेस्को-यूनीसेफ-सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित समस्याओं, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना आदि को पहले तो जाने-माने विशेषज्ञों के स्तर पर सुलझाया जाता है फिर विज्ञान सलाहकार समिति उन पर विचार करती है। इसी प्रकार परिषद् की पुस्तकों के प्रकाशन से संबंधित समस्याओं पर पहले प्रकाशन सलाहकार समिति विचार करती है और भवन निर्माण संबंधी समस्याओं आदि पर निर्माण तथा कार्य समिति विचार करती है।

12. शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय कई समितियों अथवा बोर्डों की नियुक्ति करता है। ऐसे बोर्डों में आमतौर पर परिषद् का प्रतिनिधित्व होता है। और जहाँ भी आवश्यक होता है, ऐसे बोर्डों और समितियों को उनके प्रति दिन के कार्य में सहयोग देने के अलावा, परिषद् अपेक्षित विशेषज्ञ सलाह देती है। इस प्रकार परिषद् केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोर्ड आदि के साथ निकट सहकारिता में कार्य करती है। एक ओर शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय व उसकी समितियाँ और दूसरी ओर परिषद्, इनके बीच का संबंध इतना अविरत और निकट का है कि इस संबंध को अथवा अलग इकाई के रूप में परिषद् जिस विशिष्ट ढंग से कार्य करती है, उसे स्पष्ट शब्दों में परिभाषित करना असंभव सा है। इस प्रकार का घनिष्ठ संबंध परिषद् के प्रभावी कार्य संचालन में सहायक सिद्ध होता है और असाधारण सीमा तक इसके काम में, विशेषकर इसके कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में सहायता करता है।

13. परिषद् ने भारत भर में स्कूल शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा पर पहले ही पूर्ण महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसने विभिन्न किस्मों में आदर्श स्कूल पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिन्होंने देश में ही नहीं प्रत्युत बाहर भी शिक्षाविदों का ध्यान आकृष्ट किया है। इसने राज्य शिक्षा बोर्डों की परीक्षा पद्धतियों में सुधार करने में सहायता की है। इसने यूनेस्को-यूनीसेफ की सहायता से विज्ञान-अध्यापन की पर्याप्त सामग्री का विकास किया है। अब तक लगभग 550 अध्यापक प्रशिक्षण कालिजों को प्रयोगशाला उपकरण और लगभग 1100 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को विज्ञान किट दिये जा चुके हैं। इसके अलावा, यूनेस्को-यूनीसेफ पाइलट परियोजना के अंतर्गत प्रकाशित विज्ञान पुस्तकों का कई प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

14. परिषद् राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना के अंतर्गत विज्ञान क्षेत्र में प्रतिभाशील छात्रों के चयन के लिए एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन करती है। यह योजना अत्यंत लोकप्रिय हुई है और इससे निर्धन परिवारों के भी छात्रों को शिक्षा में उच्चतम स्तर तक अर्थात पीएच० डी० तक अविच्छिन्न और वित्तीय चिन्ता से मुक्त रह कर अपना अध्ययन करने का अवसर मिला है। इस योजना के लिए परीक्षाएँ अब संघ की सभी भाषाओं में हो रही हैं और समूची कार्य विधि को निरंतर समीक्षाधीन रखा जाता है ताकि सुधार किए जा सकें।

15. परिषद् ने विभिन्न संगठनों द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों का विभिन्न दृष्टिकोणों से मूल्यांकन किया है और लगातार मूल्यांकन कर रही है। अनेक राज्य संगठनों से परिषद् को इस आशय की प्रार्थनाएँ प्राप्त होती रहती हैं कि इन पुस्तकों की पांडुलिपियों का मूल्यांकन किया जाए। पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन कर्त्ताओं के मार्गदर्शन के लिए परिषद् ने विभिन्न स्कूल विषयों की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण और मूल्यांकन पर विवरणिकाएँ तैयार की हैं।

16. अनुसंधान परियोजनाओं को सहायतार्थ अनुदान देने की परिषद् की योजना से बहुत से विश्वविद्यालय विभाग, अध्यापक प्रशिक्षण कालेज, अनुसंधान संस्थाएँ आदि महत्वपूर्ण अनुसंधान के कार्य में रत हो गई हैं । इन अनुसंधानों के कुछ परिणामों का स्कूल शिक्षा पर पहले ही जोरदार प्रभाव पड़ चुका है । परिषद् शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधानों को प्रकाशित करने में व्यक्तियों को वित्तीय रूप से सहायता भी देती है। इसके अलावा राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर के व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को स्कूल-शिक्षा में सुधार के लिए परिषद् अनुदान देती है। यह स्कूल अध्यापकों को कक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएँ करने में बढ़ावा देती है। उदीयमान युवा अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं की सहायता करने के लिए परिषद् 300 रुपये तथा 500 रुपये के मूल्य की क्रमशः अवर तथा प्रवर मासिक वृत्तियाँ प्रदान करती है और उनके व्यावसायिक अभिवर्द्धन के लिए सुविधाएँ प्रदान करती है।

17. परिषद् ने अपने क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के माध्यम से अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहुलता कम करने की एक विशेष परियोजना बनाई है । इस योजना में शिक्षकों को बी० एड० करने में सहायता देने के लिए अवकाश एवं पत्राचार अध्यापन उपलब्ध कराया जाता है।

18. परिषद् के कार्य की एक सामान्य विशिष्टता, स्कूल अध्यापकों और अध्यापक प्रशिक्षकों को विकास की सुविधाएँ और अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रीष्म कालीन संस्थानों का आयोजन करना है । इनमें से विज्ञान के ग्रीष्म कालीन संस्थानों का बड़ा महत्व है । इसके अतिरिक्त, अपने कार्य को सार्थक बनाने के लिए परिषद् देश में फैले हुए प्राथमिक तथा माध्यमिक विस्तार सेवा केन्द्रों का शैक्षणिक मार्गदर्शन भी करती है । इसके अलावा, परिषद् भारत के सभी भागों से लिए गए शिक्षा कर्मचारियों तथा अध्यापकों एवं अल्प विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिए विचार गोष्ठियों और कार्यक्रमों का संचालन करती है। परिषद् में नियोजित विशेषज्ञों के लिए भारत के अनेक राज्यों एवं राज्य शिक्षा बोर्डों सहित स्कूल शिक्षा में रुचि रखने वाले बहुत से संगठनों से निरंतर तथा अनंत माँग आती रहती है।

19. राष्ट्रीय संपूर्णता और भारत की मौलिक एकता का विचार बच्चों के मस्तिष्क में भरने के लिए, परिषद् मूल्यवान साहित्य का प्रकाशन करती है और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए अंतरराज्यीय शिविरों का आयोजन करती है। परिषद् द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री आदि ने स्कूलों का विशेष ध्यान आकृष्ट किया है। परिषद् ने हाल ही में जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया है।

20. उपरोक्त विवरण परिषद् में हो रहे विभिन्न कार्यकलापों तथा उसके व्यवस्थित और प्रशासित कार्यों का विस्तृत चित्रांकन करता है।

1971-72 के महत्वपूर्ण कार्य

1. परिचय

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने, जिसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय के बहुत से अधीनस्थ कार्यालयों के विलयन से एक स्वायत्त संगठन के रूप में 1961 में की गई थी अपने अस्तित्व के दस वर्ष 1971 में पूरे कर लिए। इस दशक में परिषद् ने प्रगति की, किंतु उसके कार्यों की आलोचना भी हुई। परिषद् के कार्यों की समीक्षा और उसके भविष्य के विकास हेतु सिफारिशें करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई थी। एक और समिति ने भर्ती की कार्यविधियों और नीतियों की जाँच की। इन समितियों के निष्कर्ष ही परिषद् के कार्यों में सुधार करने के मूल तत्व हैं। हाल के वर्षों में परिषद का व्यय अधिक हुआ बताया गया है।

इस अनुभाग में परिषद् द्वारा वर्ष 1971-72 में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला गया है और उसने अपनी समस्याओं को किस प्रकार सुलझाया है इसका उल्लेख किया गया है।

2. व्यय

1969-70 में लगभग 316 लाख रुपये और 1970-71 में लगभग 344 लाख रुपये के सामान्य अनुदान की माँग के विरुद्ध परिषद् ने 1971-72 में अपना कार्य चलाने के लिए केवल 274 लाख रुपये के सामान्य अनुदान की माँग की। हाल के वर्षों में सम्भवतः यह सबसे कम अनुदान की माँग है। इस अनुदान में लगभग 27 लाख रुपये राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देने के लिए, लगभग 16 लाख रुपये ग्रीष्म संस्थानों को चलाने के लिए जिनको पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग चलाता था और लगभग 10 लाख रुपये 1972-73 में छपाई के लिए पहले से कागज खरीदने के वास्ते है। इसके अलावा 10 लाख रुपए की राशि सरकारी और दूसरे संगठनों से पाठ्यपुस्तकें बेचने के संबंध में प्राप्त होनी है। इस प्रकार वर्ष 1971-72 का मूलधन और राजस्व का कुल अनुदान व्यय लगभग 211 लाख रुपये आता है। इसमें से 9 लाख रुपये केन्द्रीय शिक्षा संस्थान पर, 84 लाख रुपये अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और मैसूर के चार

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों पर और 56 लाख रुपये दिल्ली के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान पर व्यय किए गए। विशेष कर अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण और उपकरण पर अनावर्ती व्यय लगभग 16 लाख रुपये था। शेष 46 लाख रुपये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रधान कार्यालय और देश के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय सलाहकारों के कार्यालयों पर, जो राज्यों और परिषद् के बीच संपर्क बनाए रखने का कार्य करते हैं, व्यय किए गए। सरकारी विभागों का लेखा ब्यौरा महालेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है और उन पर किया गया व्यय विभागों के व्यय खाते में नहीं दिखाया जाता है। भवनों का निर्माण और उनका अनुरक्षण लोक-निर्माण विभाग द्वारा होता है और यह व्यय सरकारी विभागों के व्यय खातों में नहीं दिखाया जाता है। परन्तु इन दोनों मदों का व्यय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रधान कार्यालय के खाते में दिखाया जाता है। यह बात ध्यान में रखने की है कि परिषद् में 2000 से अधिक कर्मचारी हैं जिनका व्यक्तिगत लेखा आदि स्वयं परिषद् को ही रखना पड़ता है। परिषद् के बहुत से भवन हैं और उनके अनुरक्षण कार्य के लिए लोक-निर्माण विभाग इसी प्रकार के दूसरे सरकारी विभागों के खातों में डाले गए खर्चे से कहीं अधिक परिषद् से वसूल करता है। इसी प्रकार लेखापरीक्षा के लिए भी परिषद् को शुल्क देना पड़ता है। क्योंकि परिषद् एक स्वायत्त संगठन है इसलिए इसे नगरपालिका निगम को ऊँची दर से कर देना पड़ता है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परिषद् के प्रधान कार्यालय का व्यय अधिक नहीं है।

वर्ष 1971-72 में हुए व्यय में महत्वपूर्ण कमी लाई गई। यह कमी लगातार किए गए ऐसे उपायों द्वारा ही संभव हो सकी थी जिस से न तो कार्य स्तर पर प्रभाव पड़ा और न ही उपयोगी कार्यक्रमों की संख्या में कमी हुई। पत्राचार-एवं-ग्रीष्म स्कूल के एक वर्षीय पाठ्यक्रम के छात्रों की छात्रवृत्तियाँ समाप्त कर दी गईं। शिक्षा महाविद्यालय के नामांकित विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या सीमित कर भर्ती की लगभग 50 प्रतिशत कर दी गई। सेमिनार, वर्कशाप, सम्मेलन और दूसरे कार्यक्रमों को, जिनको वास्तविक तैयारियों और साध्यों के आधार पर आयोजित करना न्यायोचित नहीं समझा गया समाप्त कर दिया गया। इस संबंध में यह बताना उचित है कि 1969-70 में सेमिनारों और वर्कशापों पर किए गए 6·15 लाख रुपये के व्यय को घटा कर 1971-72 में 3·34 लाख रुपये कर दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के दैनिक भत्ते के भुगतान का युक्तिकरण कर दिया गया। परिषद् के मुद्रण कार्यक्रम में सुधार किया गया। जहाँ भी तुरंत वितरण या बिक्री की संभावना नहीं थी, ऐसी पुस्तकों की मुद्रणसंख्या में भारी कमी कर दी गई। बहुत से मामलों में सेमिनार, वर्कशाप और सम्मेलन आदि की रिपोर्टों को केवल व्यय घटाने के हेतु मिम्यूग्राफ कर लिया गया और इस प्रकार मिम्यूग्राफ सुविधाओं के उपयोग के लिए यथोचित काम भी उपलब्ध कर लिया गया।

1971-72 वर्ष में परिषद् की प्राप्तियों तथा भुगतान स्थिति का अधिक विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3 में दिया गया है।

3. स्टाफ

किसी भी संस्था में वहाँ के सारे कर्मचारी वर्ग के सक्रिय और इच्छित सहयोग से सदैव उपयोगी कार्य किया जा सकता है। इस संबंध में सामान्य फिलॉसफी, जिससे अच्छे नतीजे निकल सकते हैं, यह है कि कर्मचारियों को उनके सामाजिक उत्तरदायित्वों का ज्ञान कराते हुए अपने आप व्यक्तिगत रूप से कार्य करने का बढ़ावा दिया जाए। स्टाफ हमेशा से यह शिकायत करता आ रहा था और समीक्षा समिति ने भी इस बात पर जोर दिया था कि परिषद् जैसी संस्था को अनिश्चित समय तक बिना विनियम के कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए विनियमों का मसौदा तैयार किया गया और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर लिया गया। इनकी घोषणा कर दी गई है और 12-5-71 से इनको लागू कर दिया गया है। यह विनियम परिषद् में भर्ती, व्यय और उसके विभिन्न अधिकारियों के अधिकार-प्रयोग से संबंधित आवश्यक कार्यविधि के न्यूनतम मानकों को बताते हैं। परिषद् में सैकड़ों कर्मचारी कई वर्षों से प्रतिदिन की मजदूरी पर कार्य कर रहे थे। सामाजिक न्याय का तकाजा था कि असमानता की यह स्थिति समाप्त की जाय। इस समस्या पर काफी विस्तार में विचार किया गया। क्योंकि प्रतिदिन मजदूरी पर कार्य कर रहे बहुत से कर्मचारी ऐसी परियोजनाओं पर कार्य कर रहे थे जिनकी अवधि फिलहाल बहुत सीमित थी इसलिए परिषद् ने विशेष परियोजना संस्थापन की स्थापना का फैसला किया जिसके अंतर्गत परिषद् में प्रतिदिन मजदूरी पर कार्य कर रहे सभी कर्मचारी कार्य कर सकें। इन कर्मचारियों को अब परिषद् में नियमित रूप से कार्य कर रहे कर्मचारियों की तरह छुट्टी, मकान-किराया, शहर प्रतिपूरक भत्ता और वेतन सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मिलेगा। इसने परिषद् के कर्मचारियों का काफी कुछ असंतोष दूर कर दिया है।

वर्ष 1967 से व्यावहारिक रूप से नियमित भर्ती बंद हो जाने को ध्यान में रखते हुए बहुत सी नियुक्तियाँ एड हॉक आधार पर की जा रही थीं। ऐसी नियुक्तियाँ अधिकतर शैक्षणिक वर्ष के अंत में समाप्त कर दी जाती थीं। इससे एक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती थी और शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा स्तर को क्षति पहुँचती थी। इसके अलावा कर्मचारियों की भर्ती और समाप्ति की कार्य पद्धति न्यायपूर्ण नहीं थी। इसके अतिरिक्त एड हॉक नियुक्तियों का कुछ महीनों से अधिक चालू रहना निश्चित रूप से अनियमित था। इसलिए परिषद् ने यह फैसला किया कि बहुत आवश्यक पदों को विज्ञापित करके दो वर्ष के शर्तनामे के आधार पर नियुक्तियाँ कर ली जाएँ। इस कार्यवाही से परिषद् को विश्वास था कि दो वर्षों में परिषद् का संरचनात्मक ढाँचा और भर्ती की कार्यप्रणाली उचित रूप से विकसित हो जाएगी।

सारे कर्मचारी वर्गों के लिए संवेदनात्मक बात भर्ती के नियमों का न होना है। भर्ती के नियम बना लिए गए हैं और सारे कर्मचारी संगठनों और स्थापना-अनुभागों में घुमा दिए गए हैं। इन से संबंधित हर व्यक्ति के विचार प्राप्त कर लिए गए हैं। ये सब समालोचनाएँ और नियमों का संशोधित मसौदा कार्यकारी समिति के विचाराधीन है। इस मामले में भारत सरकार से परामर्श कर के इन नियमों को अंतिम रूप देने की संभावना है।

4. कार्यक्रम

परिषद् में होने वाले कार्यक्रमों की संख्या बहुत है। इनमें से कुछ समाप्त कर दिए गए हैं। कुछ ऐसे कार्यक्रमों को जिनसे तुरंत उपयोगी नतीजे निकलने की संभावना नहीं थी इसलिए चालू रखा गया क्योंकि उन पर पहले काफी धन व्यय किया जा चुका था और होने वाला अतिरिक्त व्यय कम था। परंतु सामान्य रूप से परिषद् के कार्यक्रमों को शासी निकाय के सुझावों के आधार पर पुनर्गठित करने का हर संभव प्रयत्न किया गया। परिषद् के मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिए अनुसार है।

(क) **पाठ्यक्रम-विकास** : स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम-विकास माता-पिता, छात्रों, शिक्षकों और राज्य सरकारों की रुचि का एक विशेष कार्यक्रम है। किसी पाठ्यक्रम का यांत्रिक रूप से गठन करने से शिक्षा का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। प्राथमिक, माध्यमिक और सैकेंड्री स्कूल स्तरों के लिए शिक्षा-कार्यक्रम उदार दृष्टिकोण और राष्ट्रीय नीति पर आधारित होना चाहिए। इस संबंध में भारत सरकार का राष्ट्रीय नीति-संकल्प है जिसमें शिक्षा के 10+2+3 ढाँचे की शिफारिश की गई है। अंतिम तीन वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षा के बराबर हैं। स्कूल शिक्षा के हर स्तर पर कार्य-अनुभव अनिवार्य होना चाहिए। स्कूलों की या उनकी देखभाल करने वाले शिक्षाविभाग की दक्षता में विभिन्नताएँ हो सकती हैं परन्तु कोई वास्तविक योजना बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना है।

समस्त योजना के आधार पर समय का विभाजन करते हुए कई निश्चित विषयों को स्कूल पाठ्यक्रम में स्थान देना होगा। हर विषय में पाठ्यक्रम-विकास उन उद्देश्यों पर आधारित होगा जिनकी पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम बना है। इस प्रकार सर्वप्रथम अनुदेश का उपयोग छात्रों में युक्ति की क्षमता का विकास करना है। इसके उपरान्त अनुदेश का उपयोग छात्रों में निर्णय लेने और उन पर अमल करने की क्षमता का विकास करने के लिए होगा। अंत में अनुदेश का उपयोग छात्रों को एक ऐसे निश्चित ज्ञान और कार्यविधि से युक्त करना है जिसको अपना कर वे किसी समय ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त और भी अति आवश्यक बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली तो उचित मूल्यों और अभिवृत्तियों से संबंधित है और दूसरी का संबंध देश और उसके सारे साधनों की उचित सराहना से

है। यहाँ पर यह बात भी जान लेने की है कि उचित मूल्यों और अभिवृत्तियों का विकास केवल पाठ्यक्रम द्वारा ही नहीं किया जा सकता है वरन् पाठ्यक्रम के आधार पर उचित रूप से लिखी गई पाठ्यपुस्तक के द्वारा हो सकता है।

पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक का महत्व समाप्त हो जाता है यदि अध्यापकों को पाठ्यक्रम विकसित करने के उद्देश्यों की सराहना और आने वाली पीढ़ी में उचित मूल्यों और अभिवृत्तियों के निर्माण से संबंधित उचित प्रशिक्षण न दिया जाए। इसी लिए शिक्षक के लिए अनुदेश पाठ्यक्रम-विकास का एक मुख्य अंग है। इसके दो रूप हैं। पहला रूप तो संपूर्ण शिक्षक दर्शिका या शिक्षक हस्तपुस्तिका है। यह हस्त-पुस्तिका शिक्षक को विस्तार में बताएगी कि उसको अपना कार्य किस प्रकार करना है, कहाँ पर प्रयोगशाला सुविधाओं का और कहाँ पर फिल्म, चार्ट्स और स्लाइडों आदि का उपयोग करना है। इसके अलावा शिक्षक का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि वह अपने शिक्षण को बच्चों के उस वातावरण के अनुकूल बनाए जिसमें वे पलते हैं और इस प्रकार उनमें उचित मूल्यों और अभिवृत्तियों का विकास करे। यह उस समय तक संभव नहीं हो सकता है जब तक कि शिक्षक के लिए उचित सेवाकालीन शिक्षा कार्य-क्रम न हो। इस प्रकार शिक्षक दर्शिकाएँ और सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम पाठ्यक्रम-विकास के मुख्य अंग बन गए हैं। परन्तु एक उपयोगी पाठ्यक्रम, एक उपयोगी पाठ्य-पुस्तक, एक उपयोगी शिक्षक दर्शिका और एक उपयोगी सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम का कोई प्रभाव नहीं होगा यदि मूल्यांकन की कार्यविधियाँ और परीक्षाएँ दोषपूर्ण हैं। वास्तव में स्कूल शिक्षा क्षेत्र की प्रगति में मुख्य बाधा वर्तमान परीक्षा कार्यक्रम हैं जो रट्टा लगाने को बढ़ावा देते हैं और शिक्षा के बुनियादी उद्देश्यों को नष्ट करते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम विकसित करते समय ऐसे लोगों को भी शामिल करना चाहिए जो परीक्षा-सुधार-योजना बनाने से संबंधित हैं। यदि एक ऐसी योजना पाँच प्रश्नों वाले दो घंटे के प्रश्न-पत्र का विचार करती है तो ये पाँच प्रश्न ऐसे पाँच एककों के समान होंगे जिनमें प्रत्येक एकक में बहुत से विचार पूर्ण और बहुत अच्छे निर्मित प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न-भंडारों की तैयारी उचित पाठ्यक्रम-विकास के लिए बहुत आव-श्यक है। प्रश्न-भंडार छात्रों को अध्ययन की पद्धति की सराहना करना और उनका किस प्रकार मूल्यांकन किया जाना है, सिखाते हैं। जहाँ तक शिक्षकों का संबंध है वे तो प्रत्येक एकक के लिए एक प्रश्न चुन कर एक प्रश्न-पत्र सरलता से तैयार कर सकते हैं जो सुगठित और बहुत विचारपूर्ण होगा। इसके अलावा प्रश्न-भंडार का पूरे वर्ष लगातार मूल्यांकन करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए प्रश्न-भंडार की तैयारी के विरुद्ध किया गया कोई भी प्रयत्न पाठ्यक्रम-विकास के मूल उद्देश्यों को नष्ट कर देगा।

पाठ्यक्रम-विकास के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो पाठ्यक्रम को काट छाँट कर बनाने और उसके उपरांत पाठ्यपुस्तक लिखने या प्रश्न-भंडार तैयार करने का कार्य करेंगे। यह उचित ढंग से देश में उपलब्ध इस क्षेत्र के उत्तम बुद्धि-जीवियों द्वारा किया जाता है। परिणामस्वरूप विद्या के हर क्षेत्र के लिए विशेषज्ञों

की नामिकाएँ बनाना, पाठ्यपुस्तक के मसौदों और प्रश्न-भंडारों पर उनकी सलाह लेना और ऐसे विशेषज्ञों को लगातार कार्य में सम्मिलित रखना उचित विकास के लिए पहली शर्त है। इन विस्तृत दिशाओं के आधार पर इस प्रश्न की जाँच करके परिषद् ने विभिन्न विषयों पर उपयुक्त नामिकाएँ बना दी हैं। परिषद् के कर्मचारियों, विशेष आमन्त्रित व्यक्तियों, शिक्षकों और छात्रों के सहयोग से और नामिकाओं के परामर्श से ऐसी आशा की जाती है कि स्कूलों के उपयोग के लिए ऊँचे स्तर की सामग्री उपलब्ध की जा सकेगी। इन दिशाओं के आधार पर एक श्रेष्ठ योजना निर्माणाधीन है जिसके आधार पर परिषद् की कुछ स्थापनाओं के पुनर्गठन की संभावना है। वर्ष 1971-72 में इस क्षेत्र में परिषद् द्वारा किये गये कार्य का विवरण परिशिष्ट 6 में दिया गया है।

(ख) **स्कूल-विज्ञान-परियोजना :** भारत सरकार की यूनेस्को-यूनीसेफ सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत परिषद् ने प्राथमिक, माध्यमिक और सेकेंड्री स्कूलों में प्रयोग करने के लिए विज्ञान की प्रत्येक शाखा पर साधारण और सस्ते प्रयोगशाला उपकरण विकसित किए हैं और कर रही है। इन उपकरणों को स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए लिखी गई पुस्तकों और तैयार किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर विकसित किया जा रहा है। बहुत से राज्यों ने इस सामग्री का प्रयोग करते हुए अग्रगामी परियोजना आरंभ कर दी है। उन्होंने पाठ्यपुस्तकों और शिक्षक-दर्शिकाओं का अनुवाद कर लिया है और उनको छाप लिया है। इस परियोजना के दूसरे चरण में सारे प्राथमिक स्कूलों में लगभग 5 प्रतिशत को और सारे माध्यमिक स्कूलों में से लगभग 30 प्रतिशत को स्कूल-विज्ञान-उपकरण दिए जाएँगे।

इस परियोजना का एक मुख्य दोष सामने आया है। वह यह है कि जब तक शिक्षकों को, जिन्हें कि पढ़ाना है, उचित प्रशिक्षण न दिया जाए, उपकरणों और पुस्तकों से कोई लाभ नहीं होगा। इतने सारे शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य राज्य के केवल एक या दो संस्थानों द्वारा नहीं हो सकता। ऐसी सुविधाओं को हर जगह प्रदान करने के लिए सारे शिक्षकों को प्रशिक्षण देना होगा। इस उद्देश्य से क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जहाँ राज्य के सारे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राथमिक और सैकेंड्री शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार के सारे प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और शिक्षा महाविद्यालयों को आवश्यक उपकरणों और छोटे पुस्तकालय से युक्त करने का प्रस्ताव है। इसलिए यदि इन संस्थानों के शिक्षक प्रशिक्षकों को क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में उचित प्रशिक्षण दे दिया जाए और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्याय का एक विशेषज्ञ इन संस्थानों का दौरा करे तो शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा विज्ञान में सेवाकालीन शिक्षा का कार्यक्रम उचित ढंग से आरंभ कराया जा सकता है। स्कूलों के समूहों से शिक्षक ऐसे संस्थानों में बुलाए जा सकते हैं और प्रशिक्षित करके वापस भेजे जा सकते हैं। यदि शिक्षकों को 30 या 40 के समूहों में बुलाया

जाए तो तदनुरूप संस्थाओं को चार सप्ताह के लिए, जब तक प्रशिक्षण दिया जाता है, बंद किया जा सकता है । इन दिशाओं पर विस्तार से विचार करके चारों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में विज्ञान में शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने की एक परियोजना तैयार कर ली गई है । जब यह परियोजना चालू हो जाएगी तो सारे शिक्षकों के लिए विज्ञान में सेवाकालीन शिक्षा का अखिल भारतीय आधार बनेगी । भारत सरकार और यूनीसेफ इस परियोजना के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए सहमत हो गए हैं ।

(ग) **राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना :** परिषद् ने वर्ष 1963 में विज्ञान में प्रतिभाशाली किशोरों को चुनने और उनको विज्ञान में आगे शिक्षा देने के अभिप्राय से यह योजना चालू की थी । प्रारंभ ही में यह पता चला कि छात्रवृत्तियों के लिए उत्तीर्ण हुए छात्रों में से बहुत से छात्र देश के प्रमुख नगरों के हैं । इसलिए ऐसा सोचा गया कि छात्रों को चुनने के लिए की गई परीक्षाओं का देश में प्रचलित सारी प्रादेशिक भाषाओं में आयोजन करने से इस दोष को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है । इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज की परीक्षाओं का आयोजन अब सभी प्रादेशिक भाषाओं में हो रहा है । हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाला छात्र गाँव का रहने वाला है । इस बात पर विचार हो रहा है कि परीक्षाओं के आयोजन में सूचना के स्थान पर बौद्धिक क्षमता पर अधिक महत्व दिया जाए ।

वर्ष 1971-72 में राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियाँ प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या निम्नलिखित है :—

बी० एस सी०	
प्रथम वर्ष	219
द्वितीय वर्ष	226
तृतीय वर्ष	242
एम० एस सी०	
प्रथम वर्ष	124
द्वितीय वर्ष	161
पीएच० डी०	93
जोड़	1065

इन आँकड़ों के अध्ययन से पता चला है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले सभी छात्र इसको स्वीकार नहीं करते हैं । इसका एक कारण तो यह था कि उनमें से कुछ

ने इंजीनियरी या डाक्टरी में जाना पसंद किया और विज्ञान विषय छोड़ दिया। यह अपनी-अपनी रुचि की बात है। इसका दूसरा कारण यह था कि छात्रवृत्ति की राशि इतनी पर्याप्त नहीं थी कि विद्यालय के छात्र का उसमें पूरी तरह से निर्वाह हो सके। इस दोष को तेजस्वी छात्रों को राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति के साथ-साथ दूसरी छात्रवृत्तियाँ और वित्तीय सहायता स्वीकार करने की अनुमति देकर सुधार लिया गया है। बहुत से छात्रों ने छात्रवृत्ति के लगातार मिलने में कठिनाई का अनुभव किया। इसमें कुछ हद तक सुधार कर लिया गया है और उन संस्थाओं को, जहाँ छात्र दाखिला लेते हैं, आधे वर्ष छात्रवृत्ति की कुल राशि पेशगी में भेज दी जाती है। परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त सभी संस्थाओं से ऐसे छात्रों से पहले फीस न लेने का अनुरोध करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ताकि कुछ प्रारंभिक मुसीबतें दूर की जा सकें।

बहुत से छात्र बी० एससी० में उत्तीर्ण होने के बाद छात्रवृत्ति छोड़ देते हैं। ऐसा देखा गया है कि इनमें से कुछ विदेश जाना पसंद करते हैं। इसी प्रकार बहुत से छात्र एम० एससी० में उत्तीर्ण होने के बाद पीएच० डी० नहीं करते बल्कि विशेष अनुसंधान के लिए विदेश जाना पसंद करते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार भारत से बाहर की संस्थाओं को राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति प्राप्त करने की मान्यता नहीं दी जा सकती है इसीलिए इस नियम में अब कुछ नियंत्रित संशोधन कर दिया गया है कि वह छात्र जो अपनी शिक्षा आगे जारी रखना चाहता है उसकी छात्रवृत्ति की कुल राशि भारत के उसके किसी बैंकखाते में जमा करादी जाएगी यदि मान्यता प्राप्त संस्था से उसकी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है।

कुछ छात्रों को पीएच० डी० में दाखिला मिलने में कठिनाई हुई। इसका एक कारण यह था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा भेजे गए छात्र अपने साथ आकस्मिक अनुदान की कुल राशि उन संस्थाओं के लिए लाते थे जहाँ वे अध्ययन करते थे। इससे ऐसी संस्थाओं को उपभोग करने योग्य वस्तुओं पर व्यय करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज द्वारा चुने गये छात्रों को केवल छात्रवृत्ति दी जाती थी और संस्थाएँ जिनमें वे दाखिला लेते थे उनको कोई भी आकस्मिक अनुदान नहीं मिलता था। इस दोष को अब सुधार लिया गया है।

मूल्यांकन के लिए अपनाई गई कार्य विधियों का निकट से अध्ययन किया जा रहा है ताकि मूल्यांकन योजना में आगे आने वाली अनिश्चितताओं को कम किया जा सके। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज के छात्रों के लाभ के लिए विभिन्न स्तर पर ग्रीष्मकालीन स्कूल चालू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए सोचा जा रहा है। वर्ष 1974 में इस योजना को अखिल भारतीय रूप से चालू हुए पूरे दस वर्ष हो जाएँगे। इसलिए स्टाफ द्वारा सारी परियोजना का वर्तमान सुविधाओं सहित लगातार निरीक्षण, सलाह-मशवरा, और मार्गदर्शन का हर दृष्टिकोण से मूल्यांकन निरीक्षणाधीन है।

1971-72 में इस योजना के कार्यान्वयन का प्रतिवेदन परिशिष्ट 7 में दिया गया है ।

(घ) **शिक्षकों का व्यावसायिक विकास :** स्कूल-शिक्षा का विकास मुख्यत: शिक्षकों पर निर्भर है । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का मुख्यत: संबंध शिक्षकों में उल्लास व उत्साह उत्पन्न करने की समस्या से रहा है । ऐसा विभिन्न विस्तार सेवा केन्द्रों द्वारा किया जाता है । इनमें से जिन पर प्रतिवेदन वर्ष में विशेष ध्यान दिया गया और कठिनाइयों के बावजूद जिनका विस्तार होने की संभावना है वर्णन के योग्य है । इनमें से पहला संगोष्ठी-पठन कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम में प्रत्येक शिक्षक को उसके द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किए गए अनोखे प्रयोगों या शिक्षण के लिए अपनाई गई बेहतर तकनीकों के संबंध में लिखने की अनुमति है । शिक्षक का निबंध पहले विस्तार केन्द्र पर पढ़ा जाता है उसके बाद राज्य के सब से अच्छे लिखे निबंध चुने जाते हैं । इनका मूल्यांकन किया जाता है । और संगोष्ठी-पठन कार्यक्रम में लिखे सब से अच्छे अखिल भारतीय निबंध को पुरस्कार दिया जाता है । अच्छे निबंधों को छपाया जाता है और दूर-दूर वितरित किया जाता है । इसने बहुत से अच्छे शिक्षकों में फैले असंतोष के बावजूद, अपने कार्य में रुचि लेने के लिए उत्साह दिलाया है ।

प्रयोगी परियोजनाएँ दूसरी योजना है । इस योजना में प्रत्येक शिक्षक जिसके पास शिक्षण की तकनीक सुधारने के लिए अनोखे विचार हैं अपनी परियोजना भेज सकता है । यदि वह उपयोगी प्रतीत होती है तो शिक्षक को सहायतार्थ आगे कार्य करने के लिए थोड़ा अनुदान दिया जाता है । सम्पूर्ण भारत से बहुत से शिक्षकों ने इस योजना से लाभ उठाने का प्रयत्न किया है और इसके अच्छे परिणाम निकले हैं ।

इन दोनों योजनाओं पर हर दृष्टिकोण से विचार करने पर ऐसा अनुभव हुआ है कि इनकी कार्य-गति को बढ़ाया जाए। इसीलिए इन योजनाओं का केन्द्रीकरण किया जा रहा है । क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के प्रिंसिपलों को इन योजनाओं की ठीक से घोषणा करने और अपने नियंत्रित क्षेत्र के सारे शिक्षकों के आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही करने का अधिकार दिया जा रहा है । क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में विषय विशेषज्ञ और शिक्षा विशेषज्ञ हैं जो संबंधित राज्य की विभिन्न भाषाओं से भली भाँति परिचित हैं । ऐसा अनुभव किया जाता है कि इन सुविधाओं से क्षेत्रीय महाविद्यालय अपने-अपने क्षेत्रों में इन योजनाओं की कार्य-गति को बढ़ा सकेंगे ।

चाहे कोई व्यक्ति फौज में कार्य करता हो या नागरिक नौकरी में, उसकी कार्यक्षमता के स्तर को ऊँचा बनाए रखने के लिए समय-समय पर उसके ज्ञान और अनुभव को उल्लासकारक बनाना बहुत आवश्यक है । यह बात शिक्षकों पर भी लागू होती है । इसी लिए शिक्षकों के लिए कई सेवाकालीन कार्यक्रम प्रधान

कार्यालय या क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा चालू किए गए हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम जो नए हैं वे काफी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इनमें से एक कार्यक्रम के अंतर्गत सेकेंड्री शिक्षकों को ग्रुप में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में बुलाकर बागबानी में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह उन सेकेंड्री स्कूलों में जहाँ वे पढ़ाते हैं, बागबानी को कार्य-अनुभव के रूप में प्रारंभ कर सकें। दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिकी के शिक्षकों को ग्रुप में बुलाया जाता है और उन्हें वर्कशाप के उपकरणों और इंजीनियरी सामग्री के प्रयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके उपरांत उनसे एक ऐसी परियोजना तैयार करवाई जाती है जो उनके स्कूलों के लिए उपयोगी हो। इन्हीं शिक्षकों को ग्रीष्मकाल में फिर उनके चार या पाँच छात्रों सहित बुलाया जाता है। शिक्षकों से छात्रों को फिर उसी प्रकार प्रशिक्षण दिलाया जाता है और उनसे परियोजना का कार्य पूरा कराया जाता है। इसमें क्षेत्रीय महाविद्यालय का स्टाफ शिक्षकों की देख-रेख व सहायता करता है। यह योजना बड़े सुचारू ढंग से चल रही है और अब सेकेंड्री स्कूल स्तर पर भौतिकी-प्रयोगों के स्थान पर परियोजना-कार्य को प्रारम्भ करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

सारे विश्व में ऐसा सोचा जा रहा है कि अध्यापक शिक्षा की प्रत्येक योजना में विषय और अध्यापन-विज्ञान को समाकलित कर लेना चाहिए। इसमें अध्यापक-प्रशिक्षण की अवधि तो नहीं बढ़ेगी परन्तु उसके द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषय के साथ-साथ अध्यापक अध्यापन-विज्ञान भी सीखेगा। यह प्रयास कई कारणों से अच्छा समझा गया है। पहला कारण तो यह है कि पढ़ाने के पेशे को कुशाग्र बुद्धि वाले नहीं अपनाते हैं और इसलिए अध्यापकों को काफी समय तक शिक्षा का उपदेश देना पड़ता है। इस प्रकार अध्यापक-शिक्षा भी इंजीनियरी और डाक्टरी आदि की तरह व्यावसायिक शिक्षा समझी जाने लगी है। ऐसा सोचने का दूसरा कारण यह है कि अध्यापक को कम से कम दो विषय पढ़ाने पड़ते हैं। उनमें से एक कार्य-अनुभव हो सकता है। कार्य-अनुभव के विषयों को प्रौढ़ों में सफलता पूर्वक प्रारम्भ नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह कार्य प्रभावी रूप से कई वर्षों में ही पूरा हो सकता है। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम छात्रों को मास्टर डिग्री और अनुसंधान की ओर ले जाने की दृष्टि से बनाया जाता है जबकि अध्यापक के लिए पाठ्यक्रम उसको भविष्य में करने वाले कार्यों की दृष्टि से बनाया जाता है। सेकेंड्री स्तर पर स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाना है उसके प्रसंग में अध्यापन-विज्ञान से कहीं अधिक विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। इन्हीं कारणों से समाकलित पाठ्यक्रम अधिक पसंद किए जाते हैं। आर्ट्स या साइंस कालेज और शिक्षा कालेजों में उपलब्ध सुविधाओं का समाकलित पाठ्यक्रम के लिए उपयोग करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। यह अब विदित हो गया है कि एक वर्षीय बी० एड० कोर्स से अच्छी सेकेंड्री अध्यापक शिक्षा का मतलब नहीं हो सकता यदि अखिल भारतीय आधार पर कोई समाकलित पाठ्यक्रम संभव नहीं हो सकता तो दूसरा उपाय केवल यही है कि विस्तार में सेवाकालीन शिक्षा और पाठ्यक्रम के लिए प्लान और कार्यक्रम बनाए जाएँ।

दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में परिषद् का विशेष ध्यान प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों और शिक्षा महाविद्यालयों को चलाने वाले अध्यापक प्रशिक्षकों और व्यावसायिक व्यक्तियों की ओर रहा है। ऐसे अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के सेवाकालीन कार्यक्रमों को तैयार किया गया और लगातार उन पर अमल किया जा रहा है। इनमें से कुछ कार्यक्रम विषय-सामग्री को बढ़ाने के संबंध में और कुछ संशोधित तकनीकों को प्रचारित करने के संबंध में हैं। कुछ कार्यक्रमों में विचार और ज्ञान बढ़ाने और अनुदेश-औद्योगिकी, जिसका सारे विश्व में महत्व बढ़ रहा है, के प्रयोग की समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया है।

वर्ष 1971-72 में परिषद् द्वारा सेकेंडरी स्कूल अध्यापकों के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण और विभिन्न वर्गों के शैक्षिक कार्यकर्त्ताओं के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए किए गए कार्यकलापों का विवरण परिशिष्ट 16 में दिया गया है। प्रतिवेदन वर्ष में शैक्षिक विस्तार के क्षेत्र में किए गए कार्य का विवरण परिशिष्ट 17 में दिया गया है।

(ङ) **कार्य-अनुभव** : आने वाले कल के समाज के लिए बच्चे को तैयार करने के वास्ते यह बहुत आवश्यक है कि उसको हाथ और मस्तिष्क दोनों से कार्य करने के महत्व का आभास कराया जाए। बच्चे को इस बात का ज्ञान कराना भी आवश्यक है कि बिक्री के लिए बनाई किसी भी चीज का स्तर होना चाहिए। इसके लिए दक्षता और पुनरुत्पादन के दृष्टिकोण से प्रयोग करने की क्षमता होना भी आवश्यक है। इसके अलावा कृत्रिम प्रौद्योगिक समाज में बिक्री वाली वस्तुओं और उनकी कीमतों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। केवल इसी तरीके से जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपने योगदान का मूल्य धन में आँकना सीखता है। इसीलिए विश्व के बहुत से देशों में कार्य-अनुभव की शिक्षा स्कूल शिक्षा के सारे स्तरों का एक आवश्यक अंग बन गई है। वास्तव में उत्तीर्ण होने में कार्य-अनुभव का उतना ही श्रेय है जितना कि गणित, विज्ञान या भाषा का। शिक्षा आयोग (1964-66) ने स्कूल स्तर पर कार्य-अनुभव प्रारम्भ करने की सिफारिश की थी। परिषद् इस समस्या पर विशेष रूप से सजग है और वह इस क्षेत्र में कृषि में कार्य-अनुभव के विशेष महत्व पर सोच-विचार कर रही है क्योंकि हमारे बहुत से स्कूल देहातों में हैं। एक क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षकों के कई दलों को कृषि में कार्य-अनुभव का प्रशिक्षण दिया गया। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के निदर्शन स्कूलों की हर कक्षा में कार्य अनुभव प्रारम्भ करने के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। जब यह योजना मानक आधार पर चालू हो जाएगी, जिसके चालू होने में अधिक समय नहीं लगेगा, उस समय किसी राज्य के विशेषज्ञ परिषद् के निदर्शन स्कूलों का दौरा कर सकते हैं और कार्य-अनुभव का प्रयोग देखकर अपनी राय स्वयं बना सकते हैं।

(च) **शिक्षा में वर्तमान समस्याएँ :** स्कूल स्तर पर शिक्षा की बहुत सी समस्याएँ हैं जिनको हल करना बहुत कठिन है । बहुत से मामलों में विश्व के दूसरे देशों में प्रचलित व्यवहारों की पृष्ठभूमि का, और ऐसी परियोजनाओं पर किए जाने वाले व्यय की जानकारी होना आवश्यक है । इनका हल निकालने से पहले यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र से संबंधित सभी लोगों को शिक्षित कर दिया जाए । इसीलिए परिषद् देश के वर्तमान हित की विभिन्न समस्याओं पर 'शिक्षा में वर्तमान समस्याएँ' नामक पुस्तकों की एक नई शृंखला प्रकाशित कर रही है ।

शिक्षा के क्षेत्र में औद्योगिकी का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है । ऐसा अनुभव किया गया है कि टेप रिकार्डों, भाषा प्रयोगशालाओं और दूसरे श्रव्य दृश्य सहायक साधनों के प्रयोग से भाषा-प्रशिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है और भाषा-शिक्षण के समय को भी कम किया जा सकता है । परिषद् ने इन समस्याओं की जाँच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की है और आवश्यक देशी उपकरणों को विकसित करने का कार्य भार मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को दे दिया गया है, जो जल्दी ही नमूने तैयार कर लेंगे । साथ ही साथ चरम-उपकरणों को तैयार करने पर विचार किया जा रहा है । मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा उपकरणों का उत्पादन प्रारम्भ होते ही इस परियोजना को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है । अध्यापकों की शिक्षा के लिए सूक्ष्म-शिक्षण विशेष महत्वपूर्ण है । अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह वास्तविक कक्षा-स्थिति को देखे जहाँ अध्यापक पढ़ा रहा हो और कक्षा में हुए सवालों-जवाबों का निरीक्षण करे । यह सब भली प्रकार से कक्षा-स्थिति को विडियो टेप पर रिकार्ड करके और उसका पुनर्उपयोग करके किया जा सकता है ।

कुछ मामलों में यह आवश्यक है कि बच्चे को उसकी अपनी ही गति से किसी विशेष समस्या और उसके हल को अपने आप समझने दिया जाए । इसके लिए अनुदेश कार्यक्रम बहुत उपयुक्त हैं । अनुदेश कार्यक्रम में निहित विचारों का स्कूलों में, विशेषतया प्राथमिक स्कूलों में, उपयोग किए जाने पर विचार हो रहा है ।

इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि बहुत सस्ते कम्प्यूटरों, जिन्हें "मिनी-कम्प्यूटर" कहते हैं, के सीमित प्रयोग से किसी भी इच्छित सूचना के संचयन और पुनरुत्पादन में सहायता मिल सकती है । इसीलिए स्कूल और कालेज में इन सस्ते कम्प्यूटरों का अनुदेश-कार्यक्रमों में किस प्रकार प्रयोग किया जाए, यह भी विचाराधीन है ।

5. राज्यों के साथ संबंध

गत कुछ वर्षों से परिषद् द्वारा दी गई सुविधाओं से बहुत से राज्य लाभ उठा रहे हैं । असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मैसूर, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों ने अपने कार्मिकों को प्रश्न-पत्र के गठन में प्रशिक्षण देने और

परीक्षा-कार्यक्रमों में सुधार करने में परिषद् से सहायता ली है ।

बिहार तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों ने उनके लिए तैयार पाठ्यपुस्तकों की पांडुलिपियों की समीक्षा में परिषद् की सहायता ली है ताकि इन पुस्तकों को प्रकाशित करने से पूर्व उपयुक्त निर्णय किए जा सकें ।

आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मैसूर, राजस्थान और केरल राज्यों ने सामाजिक अध्ययन और भाषा आदि की पुस्तकें तैयार करने में परिषद् की सहायता ली है । बहुत से राज्यों ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकों को ग्रहण या अनुकूलित कर लिया है ।

राज्यों के साथ परिषद् के सब से घनिष्ठ संबंध उसके दो मुख्य कार्यक्रमों के द्वारा हुए । पहला तो राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन का प्रचंड कार्यक्रम है । करीब-करीब सभी राज्यों ने इस परियोजना पर अमल किया । इस परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले शिक्षा निदेशक या सेकेंड्री शिक्षा बोर्डों द्वारा 1 से 11 तक की कक्षाओं के लिए निर्धारित पुस्तकों की सूची तैयार की जाती है । पुस्तक की और विशेष मूल्यांकन के लिए विकसित उपकरण की एक-एक प्रति विषय के स्कूल-अध्यापक को भेज दी जाती है जो मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है । इसके बाद जाँच के लिए पुस्तक और उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट पहले एक विशेषज्ञ को भेज दी जाती है और फिर विशेषज्ञ समिति को । इस प्रकार विशेषज्ञ समिति के पास तीन मूल्यांकन रिपोर्टें पहुँचती हैं जिनमें से एक राज्य के माध्यम से प्राप्त होती है । अधिकतर राज्यों ने इस मूल्यांकन में परिषद् को सहयोग दिया है । इस मूल्यांकन के फलस्वरूप आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मैसूर, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, पंजाब और पश्चिमी बंगाल राज्यों के लिए आवश्यक रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं । इस मूल्यांकन से यह पता चला है कि तीन प्रतिशत पुस्तकें ऐसी हैं जिनका भविष्य में प्रयोग बन्द करना होगा । लगभग 20 से 30 प्रतिशत पुस्तकें ऐसी हैं जिनकी कुछ सामग्री या तो निकाल दी जाएगी या फिर निर्दिष्ट भागों को पुनः लिखना पड़ेगा । जब विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टें संबंधित अधिकारियों को भेजी गईं तो अधिकतर राज्यों ने बड़ी तत्परता से उन पर अमल किया ।

विभिन्न राज्यों और राज्य समूहों के लिए क्षेत्रीय सलाहकारों के कार्यालयों की स्थापना से राज्यों के साथ संबंधों में सुधार हुआ है और परामर्श तथा सहयोग देने में सहायता मिली है । परिषद् के कुछ क्षेत्रीय सलाहकारों के पहल करने से बहुत से राज्यों ने अपने कार्यक्रमों में सुधार करना प्रारम्भ कर दिया है ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् और राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के बीच 1971-72 में हुए सहयोग कार्यकलापों का ब्यौरा परिशिष्ट 18 में दिया गया है ।

6. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय

चारों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में कुल मिलाकर लगभग 4,000 विद्यार्थी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित हैं। छोटे स्तर पर पीएच० डी० का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा चारों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में संलग्न चार प्रदर्शन स्कूलों में लगभग 2,000 छात्र हैं। इस प्रकार परिषद् इन महाविद्यालयों द्वारा 4,000 विश्वविद्यालय छात्रों और 2,000 स्कूल छात्रों को अनुदेश संबंधी सुविधाएँ प्रदान करती है। इन महाविद्यालयों में विशेष बात यह है कि ये अध्यापक-शिक्षा के संचालन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। ये सब कैम्पस महाविद्यालय हैं जिनको विभिन्न प्रकार की शिक्षा-सुविधाएँ प्राप्त हैं। स्कूल-शिक्षा के क्षेत्र में अनुपदेशात्मक और प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए ये सुविधाएँ पर्याप्त समझी जाती हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय महाविद्यालय मूलतः बहु-विद्याविभागीय संस्थाएँ हैं। इनके बहुरूपी कार्यक्रमों को देखते हुए कुछ विश्वविद्यालय, जिनसे ये अंगीकृत हैं, इनको स्वायत्त स्थिति प्रदान करने पर विचार कर रहे हैं। इन क्षेत्रीय महाविद्यालयों के विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम और स्कूल परीक्षा परिणाम दोनों ही असाधारणतः अच्छे हैं और बरबादी उपेक्षणीय है। क्षेत्रीय महाविद्यालयों से निकले हुए बहुत से छात्र जो स्नातकोत्तर पढ़ाई कर रहे हैं, इन पाठ्यक्रमों में काफी अच्छे चल रहे हैं। प्रवेश का स्तर काफी ऊँचा है। इस प्रकार विज्ञान पाठ्यक्रमों में केवल वही छात्र प्रवेश पाते हैं जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रीय महाविद्यालय जिनसे ये अंगीकृत हैं, इनको स्वायत्त स्थिति प्रदान करने पर विचार कर रहे हैं।

इन क्षेत्रीय महाविद्यालयों के विशेष महत्वपूर्ण कार्यकलाप सेवाकालीन अध्यापक-शिक्षा और अध्यापक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में हैं। प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षकों की भलाई के लिए भी कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए गए हैं और क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण कार्य है इसलिए इस क्षेत्र के कार्यक्रमों की गति बढ़ाने की योजना है।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों की एक विशेषता यह है कि अध्यापक-शिक्षा में कार्य-अनुभव की ओर ध्यान दिया जाता है। हमारा देश गरीब है और अध्यापकों को स्कूलों में कम से कम दो विषय पढ़ाने पड़ते हैं। कार्य-अनुभव के लिए अलग अध्यापक की नियुक्ति करना संभव नहीं है। इसलिए अगर विज्ञान और कला के अध्यापक कार्य-अनुभव के क्षेत्र में शिक्षित हैं तो वे स्कूल में एक या दो विषयों के पढ़ाने के अतिरिक्त यह कार्य भी सँभाल सकते हैं।

जहाँ तक शिक्षा महाविद्यालयों के प्रदर्शन स्कूलों का संबंध है, उनमें प्रत्येक कक्षा में नियमानुसार कार्य-अनुभव अनुदेश की योजना बना ली गई है जो अगले वर्ष से चालू की जाएगी।

प्रत्येक क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय की देखभाल एक प्रबंधक समिति द्वारा की जाती है जिसमें उस क्षेत्र के सब राज्यों के प्रतिनिधि सदस्य हैं। महाविद्यालय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय का कुलपति प्रबंधक समिति का अध्यक्ष होता है। महाविद्यालय के बहुत से कार्यक्रमों पर इसकी प्रबंधक समिति सोच विचार करती है। वास्तव में विभिन्न राज्यों के अध्यापकों और अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए सेवाकालीन कार्यक्रमों का आयोजन संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों के सुझाव या प्रार्थना पर ही किया जाता है।

7. अनुसंधान

अनुसंधान करना परिषद् का प्रमुख कार्यक्रम है। विभिन्न कार्यक्रमों के विकास के लिए कुछ न कुछ अनुसंधान करना पड़ता है। पाठ्यक्रम-विकास और पाठ्य पुस्तक के बनाने और मूल्यांकन करने के क्षेत्र में कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए सदैव कुछ अनुसंधान करना पड़ता है। इस सीमा तक कुछ अनुसंधान सदैव करना पड़ता है। ऐसा कहना केवल राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के ही लिए नहीं वरन् क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के लिए भी ठीक है। इसके अतिरिक्त मूल अनुसंधान पर भी कुछ ध्यान दिया जाता है जिसमें अपने आप कुछ अन्वेषण करने पड़ते हैं, जिनके समाप्त होने के बाद ही उनके परिणाम और नई समस्याएँ सामने आती हैं। ऐसे अन्वेषणों में काफी समय लगता है। एक ऐसे ही अन्वेषण अर्थात् $2\frac{1}{2}$ से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतिमान परियोजना के विकास के परिणाम अब तैयार हैं। इन अन्वेषणों के परिणामस्वरूप जो कि अहमदाबाद, इलाहाबाद, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और मद्रास के शहरी और देहाती क्षेत्रों में किए गए, यह पता चला है कि देहाती बच्चे 5+ आयु पर शहरी बच्चों के मुकाबले में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कम तैयार हैं। वास्तव में देहाती क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं से बच्चों के मस्तिष्क का विकास उतना नहीं हो पाता है जितना शहरी क्षेत्रों के बच्चों का $2\frac{1}{2}$ से 5 वर्ष की आयु का समय ऐसा होता है जबकि मस्तिष्क का विकास बड़ी तेजी से होता है। परिणामस्वरूप अन्वेषणों के परिणामों से एक बुनियादी समस्या आ खड़ी हुई है। यदि बच्चों के प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश होने से पूर्व उन्हें किसी प्रकार की स्कूल-पूर्व शिक्षा दे दी जाए तो संभवतः देहाती बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रकार तैयार भी हो जाएँगे और बरबादी तथा गतिहीनता भी कम हो सकेगी। इसके अलावा इस प्रकार की पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधा हो जाने से पिछड़ी जातियों के $2\frac{1}{2}$ से 5 वर्ष की आयु के बच्चों का मस्तिष्क ठीक प्रकार से विकसित हो सकेगा। ऐसी अवस्था में वे बिना किसी कठिनाई के शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यदि यह वास्तविक रूप से सफल हो जाए तो ऐसे बच्चों के लिए आगे चल कर स्थान आरक्षण और विशेष छात्रवृत्तियों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।

मातृभाषा और शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के एक

दूसरे अन्वेषण में स्कूल और कालेज स्तर पर भाषा के शिक्षण अपनाने के संबंध में प्राप्त आँकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है। भारतीय स्थितियों से संबंधित संपूर्ण आँकड़े उपलब्ध किए गए हैं। इस अन्वेषण से यह निष्कर्ष निकला है कि मातृभाषा ही शिक्षण का सब से अच्छा माध्यम है। इसके लिए यह कहा जा सकता है कि यह तो ज्ञात तथ्य है और कुछ हद तक यह सत्य भी है। फिर भी इन नीतियों और कार्यक्रमों को व्यावहारिक रूप से कार्यान्वित करने के लिए इस समस्या पर इसके विस्तृत संदर्भ में लागू की गई नियंत्रित स्थितियाँ बहुत आवश्यक हैं। इस अन्वेषण ने एक समय से अनुभव की जाने वाली आवश्यकता की पूर्ति की है।

1971-72 वर्ष में पूरी की गई तथा हाथ में ली गई अनुसंधान परियोजनाओं, अन्वेषणों तथा शैक्षिक सर्वेक्षणों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट 14 में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त परिषद् विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण की दूसरी संस्थाओं को अनुसंधान रिपोर्टों आदि के प्रकाशन के लिए सहायक अनुदान देती है। बहुत सी अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करते-करते कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसी परियोजनाओं के परिमाप या तो रिपोर्ट के आकार में प्रकाशित होते हैं या व्यावसायिक पत्रिकाओं में। परिषद् की जी० ए०आर०पी० (अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं के सहायतार्थ अनुदान) योजना के अन्तर्गत अब तक 96 अनुसंधान परियोजनाएँ, जो शिक्षा के विभिन्न मुख्य रूपों से संबंधित हैं देश के विभिन्न भागों की विभिन्न संस्थाओं को दी गईं।

1971-72 में जी०ए०आर०पी० योजना के अन्तर्गत कुल मिलाकर, 73,450 रुपये आर्थिक अनुदान में जिन संस्थाओं को दिए गए उनके नाम और उनकी परियोजनाओं के शीर्षक परिशिष्ट 15 में दिए गए हैं।

8. प्रकाशन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शायद देश के स्कूल पाठ्यपुस्तकों के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है जो 30 से 40 लाख रुपये मूल्य की पुस्तकें बेचती है। अब तक इन पुस्तकों के उत्पादन, छपाई और तथ्य सम्बन्धी अशुद्धियों के बारे में बहुत कम आलोचना हुई है। वास्तव में अनेक व्यक्तियों ने परिषद् की पुस्तकों की प्रशंसा की है। पुस्तकों की कीमत बिना लाभ-हानि के आधार पर निर्धारित की जाती है। यद्यपि क्रय-मूल्य के ऊपर पुस्तक विक्रेताओं के कमीशन और परिषद् के दूसरे प्रासंगिक व्ययों की गुंजायश रखी जाती है फिर भी परिषद् की पुस्तकें बाजार में सब से सस्ती हैं। ये सब पुस्तकें तुरंत ही बिक जाती हैं और इनके न मिलने के संबंध में बहुधा शिकायतें मिलती रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि निजी स्कूलों के प्रबंधकर्ताओं द्वारा पुस्तकों का अग्रिम आर्डर नहीं दिया जाता और संस्करण समाप्त होने पर बच्चों को पुस्तकों के लिए मारे-मारे फिरना

पड़ता है। अधिक पुस्तकों की प्रतियाँ छापने की योजना बनाई जा चुकी है ताकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकें जनता को सुगमता से मिल सकें। नई दिल्ली के कनाट प्लेस क्षेत्र में एक विक्रयपटल बनाने की अनुमति दी जा चुकी है। यह बात विशेष ध्यान देने की है कि 1971-72 में पाठ्यपुस्तकों की बिक्री से आमदनी कुल खर्च से 6 लाख रुपए अधिक हुई। यदि प्रकाशन कार्य-क्रम को कुछ सरकारी नियमों और प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया जाए तो पुस्तकों की बिक्री को अधिक बढ़ाना और प्रकाशन के कार्यों को अधिक से अधिक छात्र समुदाय तक पहुंचाना सम्भव हो सकेगा। यदि परिषद् को अपनी पुस्तकें विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने और छापने की अनुमति दे दी जाए तो पुस्तकों की बिक्री बहुत अधिक बढ़ सकती है। इन समस्याओं पर परिषद् विचार कर रही है।

1971-72 की विषय वार प्रकाशित पुस्तकों की सूची परिशिष्ट 21 में और विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों आदि द्वारा कोर्स में लगाई गई परिषद् की पाठ्य पुस्तकों की सूची इस परिशिष्ट के अनुबंध में दी गई है।

निम्नलिखित विषयों से संबंधित विस्तृत ब्यौरा उनके सामने लिखी हुई परिशिष्ट में दिया गया है :

परिषद् तथा उसकी समितियों के सदस्यगण	परिशिष्ट 1
1971-72 में हुई परिषद् और उसकी समितियों की बैठकों की कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण	परिशिष्ट 2
कैम्पसों का विकास	परिशिष्ट 4
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान पुस्तकालय	परिशिष्ट 5
राष्ट्रीय एकीकरण परियोजना	परिशिष्ट 8
जनसंख्या शिक्षा	परिशिष्ट 9
ग्रामीण प्रतिभा खोज योजना	परिशिष्ट 10
परीक्षा सुधार	परिशिष्ट 11
यूनेस्को रजत जयन्ती समारोह	परिशिष्ट 12
व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को अनुदान	परिशिष्ट 13
शिक्षा तथा समाज सेवा मंत्रालय के साथ सहयोग	परिशिष्ट 19
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	परिशिष्ट 20

कृतज्ञता ज्ञापन

परिषद् शिक्षा तथा समाज कल्याण के केन्द्रीय तथा राज्य मंत्रियों द्वारा उसके कार्यों में रुचि लेने के लिए अत्यन्त कृतज्ञ है। परिषद् शिक्षा तथा समाज

कल्याण मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रतिवेदन वर्ष में समय-समय पर दी गई सुविधाओं के लिए अत्यन्त कृतज्ञ है। परिषद् उन सभी संगठनों और विशेषकर राज्य शिक्षा विभागों के प्रति भी कृतज्ञ है जिन्होंने उसके कार्यकलापों को चालू रखने में सहयोग दिया है। परिषद् 'यूनेस्को', 'अमरीकी राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रतिष्ठान' रूस की सरकार, ब्रिटेन की सरकार और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य की भी कृतज्ञ है जिन्होंने विभिन्न रूपों में सहायता प्रदान की है।

परिशिष्ट I

परिषद् तथा उसकी समितियों के सदस्यगण

1971-72

(क) परिषद्

1. श्री सिद्धार्थ शंकर राय
केन्द्रीय मंत्री
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली। (अध्यक्ष)

2. डा० दौलत सिंह कोठारी
अध्यक्ष
विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली।

3. श्री टी० पी० सिंह
सचिव
भारत सरकार
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।

4. डा० के० एल० श्रीमाली
उपकुलपति,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी।

5. प्रो० एस०एन० सेन
उपकुलपति
कलकत्ता विश्वविद्यालय
कलकत्ता।

6. श्री एन०डी० सुंदरवडिवेलु
उप-कुलपति
मद्रास विश्वविद्यालय
मद्रास।

7. श्रीमती शारदा दीवान
उप-कुलपति
एस० एन० डी० टी०
महिला विश्वविद्यालय
1, नाथीबाई ठाकरसी रोड
बम्बई-20।

8. शिक्षा मंत्री
आंध्र प्रदेश
हैदराबाद।

9. शिक्षा मंत्री
असम
शिलाङ।

10. शिक्षा मंत्री
बिहार
पटना।

11. शिक्षा मंत्री
गुजरात
अहमदाबाद।

12. शिक्षा मंत्री
हरियाणा
चंडीगढ़ ।

13. शिक्षा मंत्री
हिमाचल प्रदेश
शिमला ।

14. उप शिक्षा मंत्री
जम्मू तथा कश्मीर
श्रीनगर ।

15. शिक्षा मंत्री
केरल
त्रिवेन्द्रम ।

16. शिक्षा मंत्री
मध्य प्रदेश
भोपाल ।

17. शिक्षा मंत्री
महाराष्ट्र,
बम्बई ।

18. शिक्षा मंत्री
मैसूर
बँगलोर ।

19. शिक्षा मंत्री
नागालैण्ड
कोहिमा ।

20. शिक्षा मंत्री
उड़ीसा
भुवनेश्वर ।

21. शिक्षा मंत्री
पंजाब
चण्डीगढ़ ।

22. शिक्षा मंत्री
राजस्थान
जयपुर ।

23. शिक्षा मंत्री
तमिल नाडु
मद्रास ।

24. शिक्षा मंत्री
उत्तर प्रदेश
लखनऊ ।

25. शिक्षा मंत्री
पश्चिम बंगाल
कलकत्ता ।

26. मुख्य कार्यकारी पार्षद
दिल्ली प्रशासन
दिल्ली ।

27. शिक्षा मंत्री
गोआ, दमन और दीव
पानाजी (गोआ)

28. शिक्षा मंत्री
पांडिचेरी सरकार
पांडिचेरी ।

29. शिक्षा मंत्री
त्रिपुरा सरकार
अगरतला ।

30. शिक्षा मंत्री
मेघालय
शिलाङ ।

31. सैयद नूरुल हसन
राज्य मंत्री
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली ।

32. प्रो०डी०पी० यादव
उप-मंत्री
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली।

33. प्रो०एस०वी०सी० अय्या
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली।

34. प्रो० एम० वी० माथुर
निदेशक
एशियायी शैक्षिक आयोजना
और प्रशासन संस्थान
दिल्ली।

35. प्रो० शान्ति नारायण
कालेजों के शाखाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली।

36. श्री एस० उदापाचार
मुख्य अध्यापक
नरूपतुंग बहुद्देशीय
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
हैदराबाद।

37. श्री डी० एस० बाजपेयी
प्रधानाचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
भारतीय टेक्नॉलॉजी संस्थान
कानपुर।

38. संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली।

39. डा० रवीन्द्र ह० दवे
अध्यक्ष
पाठ्यपुस्तक विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली।

40. डा० मोहन चंद्र पंत
अध्यक्ष
विज्ञान शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली।

41. श्री प्रभुदत्त शर्मा
प्रधानाचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
भुवनेश्वर।

42. श्री टी० आर० जयरामन
संयुक्त सचिव
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।

43. श्री ओ०पी० मोहला
वित्तीय सलाहकार
(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्)
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।

44. श्री भक्त दर्शन
15, गुरुद्वारा रकाब गंज मार्ग
नई दिल्ली-1

45. श्री एच० नरसिंहैय्या
प्रधानाचार्य
नेशनल कालेज
बेंगलौर।

46. श्री आई०जे० पटेल
अध्यक्ष
राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड
राज्य शिक्षा संस्थान
रायखंड
अहमदाबाद ।

47. श्री एस०पी० वर्मा
उप सचिव
मध्य प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग
भोपाल ।

48. प्रो० रईस अहमद
अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
अलीगढ़ ।

49. श्री डी०बी० फटंगारे
थोम्बर बिल्डिंग
कोपर गाँव
जिला अहमदनगर
महाराष्ट्र ।

50. श्री एस०बी० चित्तीवाबू
स्कूल शिक्षा निदेशक
तमिलनाडु
मद्रास ।

51. कुमारी के० पसरीचा
प्रधानाचार्य
कन्या महाविद्यालय
जालन्धर शहर ।

52. डा० डी०एन० गोखले
12, फर्गुसन कालेज कैम्पस
पूना ।

53. डा० के० कुरुविला जैकब
प्रधानाचार्य
दि कैथेड्रल एण्ड जान कौनन स्कूल
6, अउट्रम रोड
बम्बई ।

54. श्री एम० अब्दुल गनी साहब
429, पी०आर० स्ट्रीट
मुस्लिमपुर
वनियाम बादी
जिला उत्तरी अर्काट (त०ना०)

55. श्री के० सुकुमारन
शिक्षा अधिकारी
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
नेहरू हाउस
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली

सचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली । (सचिव)

(ख) कार्यकारी समिति

1. श्री सिद्धार्थ शंकर राय
केन्द्रीय मंत्री
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली । (अध्यक्ष)

2. सैयद नूरुल हसन
राज्य मंत्री
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली । (उपाध्यक्ष)

3. प्रो० डी०पी० यादव
उप-मंत्री
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली ।

4. प्रो० एस०वी० सी० अय्या
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली ।

5. डा० दौलतसिंह कोठारी
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग,
नई दिल्ली ।

6. प्रो० एम०वी० माथुर
निदेशक
एशियाई शैक्षिक आयोजना
तथा प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली ।

7. प्रो० शान्ति नारायण
कालेजों के शाखाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली ।

8. श्री एस० उदापाचार
मुख्य अध्यापक
नुरुपतुंग बहुद्देश्यीय उच्चतर
माध्यमिक विद्यालय
हैदराबाद ।

9. श्री डी०एस० बाजपेयी
प्रधानाचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
भारतीय टेक्नॉलॉजी संस्थान
कानपुर ।

10. संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली ।

11. डा० रवीन्द्र ह० दवे
अध्यक्ष
पाठ्यपुस्तक विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली ।

12. डा० मोहनचंद्र पंत
अध्यक्ष
विज्ञान शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली ।

13. श्री प्रभुदत्त शर्मा
प्रधानाचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
भुवनेश्वर ।

14. श्री टी० आर० जयरामन्
संयुक्त सचिव
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली ।

15. श्री ओ०पी० मोहला
वित्तीय सलाहकार (राष्ट्रीय शै० अ० और प्र०प०)
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली ।

16. सचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली । (सचिव)

(ग) वित्त समिति

1. श्री टी० आर० जयरामन्
संयुक्त सचिव
शिक्षा तथा समाज कल्याण
मंत्रालय
नई दिल्ली। (अध्यक्ष)

2. प्रो० एस० वी० सी० अय्या
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली।

3. प्रो० एम० वी० माथुर
निदेशक
एशियाई शैक्षिक आयोजन और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली।

4. प्रो० शान्ति नारायण
कालेजों के शाखाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय

5. श्री ओ० पी० मोहला
वित्तीय सलाहकार
(रा० शै० अ० और प्र० परिषद्)
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।

6. सैयद ऐनुल आबेदीन
सचिव, रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली। (सचिव)

(घ) कार्यक्रम सलाहकार समिति

1. निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली। (अध्यक्ष)

2. संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली। (उपाध्यक्ष)

3. प्रो० एच० बी० मजूमदार
प्रधानाचार्य
विश्व भारती विश्वविद्यालय
डाकघर, शान्ति निकेतन।

4. डा० डी० एम० देसाई
डीन
शिक्षा तथा मनोविज्ञान संकाय
एम० एस० यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा
बड़ौदा।

5. श्रीमती एम० ए० ठंकम्मा
अध्यक्ष, शिक्षा विभाग
केरल विश्वविद्यालय
थाईकांड
त्रिवेन्द्रम।

6. प्रो० वी० आर० तनेजा,
डीन तथा अध्यक्ष
शिक्षा विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय
चण्डीगढ़।

7. प्रो० सी० एम० बैन्नूर
डीन तथा प्रधानाचार्य
विश्वविद्यालय शिक्षा कालेज
कर्नाटक विश्वविद्यालय
धारवाड़।

राज्य शिक्षा संस्थानों के निदेशक

8. डा० (कुमारी) ए० नंदा
निदेशक
राज्य शिक्षा संस्थान
दिल्ली।

9. डा० एन० के० उपासनी
निदेशक
राज्य शिक्षा संस्थान
एम० एस० सदाशिव पीठ
कुमठेकर रोड
पूना।

10. श्री एम० घोष
प्रधानाचार्य
राज्य शिक्षा संस्थान
वाणीपुर
डाकघर बैंगाची
जिला, 24 परगना।

11. श्री टी० आर० दीनदयाल
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
6-2-688 चितलबस्ती
हैदराबाद।

12. बेगम एम० कुरेशी
निदेशक
राज्य शिक्षा संस्थान
श्रीनगर।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कर्मचारी सदस्य

13. श्री० एस० एल० अहलूवालियां
अध्यक्ष
शिक्षण साधन विभाग
नई दिल्ली।

14. कर्मचारी प्रतिनिधि
क्षेत्रीय शिक्षा कालेज
अजमेर (रिक्त)

15. कु० अहल्या चारी
आयुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
नई दिल्ली।

16. डा० आर० सी० दास
प्रधानाचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा कालेज
अजमेर।

17. डा० रवीन्द्र ह० दवे
अध्यक्ष
पाठ्यपुस्तक विभाग
नई दिल्ली।

18. कर्मचारी प्रतिनिधि
क्षेत्रीय शिक्षा कालेज
भोपाल (रिक्त)

19. डा० (कुमारी) एस० दत्त
रीडर
केन्द्रीय शिक्षा संस्थान
दिल्ली।

20. श्री० सी० वी० गोविन्द राव
स्थानापन्न प्रधानाचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा कालेज
मैसूर।

21. डा० (कुमारी) ई० मार
रीडर
अध्यापक शिक्षा विभाग
नई दिल्ली।

22. डा० (श्रीमती) पेरीन एच० मेहता
प्रभारी अध्यक्ष
शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा
आधार विभाग
नई दिल्ली।

23. त्रिभुवन शंकर मेहता
प्रभारी अध्यक्ष
सामाजिक विज्ञान तथा
मानविकी विभाग
नई दिल्ली।

24. डा० रामगोपाल मिश्र
प्रभारी अध्यक्ष
आधार सामग्री प्रक्रिया तथा
शैक्षिक सर्वेक्षण एकक
नई दिल्ली।

25. डा० मोहनचंद्र पन्त
अध्यक्ष
विज्ञान शिक्षा विभाग
नई दिल्ली।

26. श्री० डी० एस० रावत
प्रभारी अध्यक्ष
पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक
शिक्षा विभाग
नई दिल्ली।

27. प्रो० पी० के० रॉय
प्रधानाचार्य
केन्द्रीय शिक्षा संस्थान
दिल्ली।

28. श्री निखिल कुमार सान्याल
क्षेत्रीय सलाहकार
विज्ञान शिक्षा विभाग
नई दिल्ली।

29. डा० आत्मानंद शर्मा
रीडर
शैक्षिक मनोविज्ञान तथा
शिक्षा आधार विभाग
नई दिल्ली।

30. श्री प्रभुदत्त शर्मा
प्रधानाचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा कालेज
भुवनेश्वर।

31. श्री शंकर नारायण
रीडर
शिक्षण साधन विभाग
नई दिल्ली।

32. डा० जी० एस० श्रीकंतैया
प्रो० तथा अध्यक्ष
विज्ञान विभाग
क्षेत्रीय शिक्षा कालेज
भुवनेश्वर।

33. प्रो० जे० के० शुक्ल
प्रधानाचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा कालेज
भोपाल।

(ड.) प्रकाशन सलाहकार समिति

1. प्रो० ए० मुजीब
उप-कुलपति
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
नई दिल्ली।
(अध्यक्ष)

2. श्री एन० के० सुन्दरम
सहायक शिक्षा सलाहकार
प्रकाशक एकक
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय
नई दिल्ली।

3. कुमारी अहल्या चारी
आयुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
नेहरू हाउस
बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग
नई दिल्ली ।

4. श्री यू० आर० सियोले
निदेशक
पाठ्यपुस्तक उत्पादन एवं
पाठ्यक्रम ब्यूरो महाराष्ट्र राज्य
'सुरेख', विश्वविद्यालय मार्ग
पूना ।

5. श्री एम० पी० एन० शर्मा
प्रबन्धक संचालक
बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक
कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेट
व्हाइट हाउस
बुद्ध मार्ग, पटना ।

6. श्री एन० नारायण राव
निदेशक
आंध्र प्रदेश पाठ्यपुस्तक प्रेस
मिन्ट कम्पाउंड
हैदराबाद ।

7. श्री ए० ई० टी० बैरो
सचिव
भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र
परीक्षा परिषद्
बी-27, पूर्वी निजामुद्दीन
नई दिल्ली ।

8. श्री डी० आर० मनकेकर
39, भारती नगर
नई दिल्ली ।

9. बेगम एम० कुरेशी
निदेशक
राज्य शिक्षा संस्थान
श्रीनगर ।

10. प्रो० सी० एस० बेन्नूर
डीन तथा प्रधानाचार्य
विश्वविद्यालय शिक्षा कालेज
कर्नाटक विश्वविद्यालय
धारवाड़ ।

11. श्री टी० एस० सदाशिवन
अध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग,
मद्रास विश्वविद्यालय
मद्रास ।

12. श्री० टी० वी० थिमी गोडवा
पाठ्यपुस्तक निदेशक
30130-ए० कुमार पार्क
पश्चिम बंगलौर ।

13. श्री के० एल० बोर्डिया
अध्यक्ष
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
राजस्थान
अजमेर ।

14. श्री एस० एस० सोधी
अध्यक्ष
पंजाब स्कूल शिक्षा मण्डल
चण्डीगढ़ ।

15. श्री डी० एस० बाजपेयी
प्रधानाचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
भारतीय टैक्नॉलॉजी संस्थान
कानपुर ।

16. श्री निरंजन चक्रवर्ती
प्रभारी अध्यक्ष
प्रकाशन विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली (सदस्य-सचिव)

(च) विज्ञान सलाहकार समिति

1. डा० दौलतसिंह कोठारी
अध्यक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
नई दिल्ली। (अध्यक्ष)

2. डा० आर० सी० महरोत्रा
प्रोफेसर और अध्यक्ष
रसायन शास्त्र विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर।

3. डा० ए० एम० घोष
प्रोफेसर
बोस संस्थान
93/1, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड
कलकत्ता।

4. श्री आर० के० रथ
सचिव, उड़ीसा सरकार
शिक्षा विभाग
भुवनेश्वर।

5. प्रो० बी० वैंकटरामन
टाटा इंस्टीच्यूट आफ फंडामेंटल
रिसर्च
होमी भाभा रोड
बम्बई।

6. डा० ए० आर० वासुदेव मूर्ति
प्रोफेसर
निरिन्द्री और खनिज रसायन
विज्ञान
भारतीय विज्ञान संस्थान
बंगलौर-12।

7. डा० रईस अहमद
प्रोफेसर
भौतिकी विज्ञान विभाग
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
अलीगढ़।

8. डा० बी० एम० जौहरी
वनस्पति विज्ञान विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली।

9. श्री एम० उदापाचार
मुख्य अध्यापक
नरूपतुंग बहुद्देशीय उच्चतर
माध्यमिक विद्यालय
हैदराबाद।

10. प्रो० बी० आर० तनेजा
डीन तथा अध्यक्ष
शिक्षा विभाग
पंजाब विश्वविद्यालय
चंडीगढ़।

11. श्री एम० घोष
प्रधानाचार्य
राज्य शिक्षा संस्थान
बाणीपुर
डाकघर बैंगाची
जिला 24 परगना।

12. डा० आर० सी० दास
प्रधानाचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा कालेज
अजमेर।

13. डा० मोहनचंद्र पन्त
प्रधान
शिक्षा विज्ञान विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली। (सदस्य-सचिव)

(छ) निर्माण तथा काय समिति

1. प्रो० एस० वी० सी० अय्या
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली। (अध्यक्ष)

2. श्री बी० रामा राव
निर्माण सर्वेक्षक अधीक्षक (1)
केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग
निर्माण-भवन
नई दिल्ली।

3. श्री बी० आर० गम्भीर
सहायक वित्तीय सलाहकार
वित्त मंत्रालय (कार्य)
निर्माण भवन
नई दिल्ली।

4. श्री जे० एम० वेंजामिन
ज्येष्ठ वास्तुक (1)
केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग
(परिषद् का परामर्शी वास्तुक)
निर्माण भवन
नई दिल्ली।

5. श्री ओ० पी० मोहला
वित्तीय सलाहकार
(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्)
शिक्षा तथा समाज कल्याण
मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली।

6. श्री टी० आर० जयरामन
संयुक्त सचिव
शिक्षा तथा समाज कल्याण
मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली।

7. श्री एस० सी० वार्ष्णेय
उप-प्रधान प्रबंधक
दिल्ली बिजली पूर्ति निगम
राजघाट बिजलीघर
नई दिल्ली।

8. श्री एस० एम० हुसनायन
कार्यपालक इंजीनियर (भवन)
दिल्ली नगर-पालिका निगम
टाउन हाल
नई दिल्ली।

9. प्रो० शान्ति नारायण
कालेजों के शाखाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली।

10. संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली।

11. सैयद ऐनुल आबेदीन
सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली। (सदस्य-सचिव)

(ज) स्थापना समिति

1. डा० दौलतसिंह कोठारी
   अध्यक्ष
   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
   नई दिल्ली (अध्यक्ष)

2. प्रो० एस० वी० सी० अय्या
   निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
   प्रशिक्षण परिषद्
   नई दिल्ली (उपाध्यक्ष)

3. संयुक्त निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
   प्रशिक्षण परिषद्
   नई दिल्ली।

4. श्री टी० आर जयरामन
   संयुक्त निदेशक
   शिक्षा तथा समाज कल्याण
   मंत्रालय
   नई दिल्ली।

5. श्री ओ० पी० मोहला
   वित्तीय सलाहकार (परिषद्)
   शिक्षा तथा समाज कल्याण
   मंत्रालय
   नई दिल्ली।

6. प्रो० शान्ति नारायण
   कालेजों के शाखाध्यक्ष
   दिल्ली विश्वविद्यालय
   दिल्ली।

7. प्रो० एस० पी० लूथरा
   भारतीय टेक्नॉलॉजी संस्थान
   नई दिल्ली।

8. डा० बी० एन० गांगुली
   7-बी० हौज खास इनक्लेब
   ईश्वर भवन
   नई दिल्ली।

9. डा० बी० आर० शेषाचार
   अध्यक्ष, प्राणि शास्त्र विभाग
   दिल्ली विश्वविद्यालय
   दिल्ली।

10. सैयद ऐनुल आबेदीन
    सचिव
    राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
    प्रशिक्षण परिषद्
    नई दिल्ली। (सदस्य-सचिव)

परिशिष्ट 2

1971-72 में हुई परिषद् और उसकी समितियों की बैठकों की कार्यवाहियों का सारांश

परिषद् की महासमिति की एक विशेष बैठक नई दिल्ली में 24 जनवरी 1972 को परिषद् के नियमों के नियम 3 और 23 के संशोधनों पर विचार करने और उनको स्वीकार करने के लिए हुई।

परिषद् की कार्यकारी समिति की प्रतिवेदन वर्ष में चार बैठकें 23 जून 1971, 28 जनवरी, 10 फरवरी और 4 मार्च 1972 को हुईं। इन बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों का सारांश निम्नलिखित है :—

(1) कार्यकारी समिति ने परिषद् द्वारा पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन को जारी रखने और विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तक-समितियों (नामिकाओं) की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

(2) कार्यकारी समिति ने परिषद् में एक कल्याण अधिकारी के पद की स्थापना की स्वीकृति दे दी।

(3) कार्यकारी समिति ने क्षेत्रीय शिक्षा सलाहकारों के कार्यालयों को राज्यों में फरवरी 1973 के अन्त तक चलाए जाने की अनुमति दे दी। इसने यह भी फैसला किया कि क्षेत्रीय सलाहकारों के कार्यालयों की बड़े राज्यों में स्थापना के लिए शीघ्र अति शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएँ ताकि राज्यों से संपर्क प्रभावी रूप से स्थापित किया जा सके।

(4) कार्यकारी समिति ने जनजातीय शिक्षा एकक के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग में विलयन की स्वीकृति दी। इस एकक का वित्त-पोषण भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता था।

(5) कार्यकारी समिति ने तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उर्दू की पुस्तकों के प्रकाशन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

(6) कार्यकारी समिति ने यह फैसला किया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कर्मचारियों को परिषद् की पुस्तकों की एक प्रति खरीदने पर थोक दर की छूट दी जाए।

(7) कार्यकारी समिति ने यह भी फैसला किया कि केन्द्रीय शिक्षा संस्थान को दिल्ली विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 1972-73 से हस्तांतरित करने का हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(8) कार्यकारी समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्न विभागों और परिषद् के कार्यालय के अनुभागों में प्रति दिन की मजदूरी पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के विशेष स्थापना परियोजना (एस० पी० ई०) के अन्तर्गत खपत के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। ज्येष्ठता और उसके आधार पर तरक्की के अतिरिक्त, एस० पी० ई० के स्टाफ को सप्ताहांत और दूसरी छुट्टियाँ और नियमित वेतन दर से वेतन आदि उसी प्रकार दिया जाएगा जैसा कि परिषद् के नियमित कर्मचारियों का मिल रहा है।

(9) कार्यकारी समिति ने यह फैसला किया कि वे सब उत्कृष्ट गुणों के प्रोफेसर जिन्होंने कम से कम पाँच वर्ष तक लगातार नौकरी की है, 1600 से 1800 रुपये के सेलैक्शन ग्रेड के पात्र होंगे। इस बात पर जोर दिया गया कि इस कार्य को करने के लिये एक कार्यविधि बनाना बहुत आवश्यक है ताकि केवल योग्य व्यक्तियों की ही सेलैक्शन ग्रेड में नियुक्ति की जा सके।

(10) कार्यकारी समिति ने चार वर्षीय भाषा पाठ्यक्रम समिति की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया और सरकार से लंबी अवधि के आधार पर कार्यवाही करने की सिफारिश की।

(11) मिनीस्टीरियल स्टाफ ऐसोसिएशन की माँगों पर विचार करते हुए कार्यकारी समिति ने परिषद् में अनुकंपा निधि की उत्पत्ति के लिए कार्यवाही करने की सिफारिश की।

(12) कार्यकारी समिति ने यह फैसला किया है कि जब कभी परिषद् की शैक्षणिक संस्थाओं में कार्य कर रहे किसी अध्यापक की शैक्षणिक सत्र में सेवा निवृत्त आयु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की नौकरी स्वचालित रूप से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक चालू रहेगी। समिति ने इस संबंध में उपयुक्त नियम बनाए जाने का सुझाव दिया।

परिषद् की वित्त समिति की इस वर्ष दो बैठकें 7 अगस्त और 5 नवंबर 1971 को हुईं। पहली बैठक में इस समिति ने कार्यकारी समिति की कई समस्याओं पर सिफारिशें कीं जैसे शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन के डिप्लोमा पाठ्यक्रम

के संबंध में प्रश्न-पत्र बनाने और उत्तर-पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए पारिश्रमिक की दरें स्थिर करना, अध्यापन सहायता विभाग की नाट्यशाला का प्रयोग करने वालों के लिए किराए की दर का स्थिर करना, केन्द्रीय स्कूलों को परिषद् की पाठ्य-पुस्तकें खरीदने पर विशेष प्रतिबंधों के साथ 15 प्रतिशत की छूट देने की अनुमति, विज्ञान क्लबों और विज्ञान मेलों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना का पुनः प्रवर्तन, अनुसंधान अध्येताओं के यात्रा-भत्ते और दैनिक-भत्ते की दरें बढ़ाकर परिषद् के प्रशिक्षकों को मिलने वाली दरों के बराबर करना । दूसरी बैठक में इस समिति ने परिषद् के 1971-72 के परिशोधित अनुमान तथा 1972-73 के बजट अनुमानों पर विशेष रूप से विचार किया । इस बैठक में इस समिति ने परिषद् द्वारा भविष्य में तैयार किए जाने वाले बजट के संबंध में मार्गदर्शी सुझाव दिए ।

इस वर्ष कार्यक्रम सलाहकार समिति की एक ही बैठक 17 और 18 सितम्बर 1971 को हुई । इस समिति ने 1971-72 के परिशोधित कार्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों और केंद्रीय शिक्षा संस्थान के 1972-73 के प्रारूप प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें स्वीकृत किया । इस समिति ने कार्यकारी समिति द्वारा नए चारवर्षीय भाषा पाठ्यक्रम को क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में जारी रखने की स्वीकृति पर संतोष प्रकट किया और हर क्षेत्रीय महाविद्यालय से अंग्रेजी भाषा का एक-एक रीडर या प्रशिक्षक लेकर एक समिति बनाए जाने का सुझाव दिया जो अंग्रेजी भाषा के लिए नया चार वर्षीय अखंडित पाठ्यक्रम विकसित करे । इस समिति ने यह भी सुझाव दिया कि क्षेत्रीय महाविद्यालयों को चारवर्षीय भाषा राष्ट्रीय एकीकरण परियोजना के पाठ्यक्रम विकसित करने में मार्गदर्शन के लिए एक पाठ्यक्रम-समिति का गठन सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाए । इस समिति की मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार किया गया और इसके अध्यक्ष को एक छोटी विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का अधिकार दिया गया जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की इस परियोजना से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देगी । इस समिति ने परिषद् द्वारा ग्रीष्मकालीन विज्ञान-संस्थानों के कार्यक्रमों की विभिन्न पहलुओं से जाँच करने के लिए श्री एम० वी० राजगोपाल की अध्यक्षता में नियुक्त मूल्यांकन समिति की बात को नोट कर लिया । इस समिति ने परिषद् द्वारा प्रायोगिक परियोजनाओं की कार्यप्रणाली की जाँच करने के लिए नियुक्त पिछली एक समिति की मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार किया । इस समिति ने यह सुझाव दिया कि सेकेंड्री स्कूलों, प्राथमिक स्कूलों और जूनियर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में 500 रुपये तक की प्रायोगिक परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों को हस्तांतरित कर दिया जाए । 500 रुपये से अधिक की सेकेंड्री स्कूलों, प्राथमिक स्कूलों और जूनियर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की सारी प्रायोगिक परियोजनाओं को क्षेत्रीय महा-

विद्यालय जांच और स्वीकृति के लिए अध्यापक शिक्षा विभाग और पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग को भेजेगा। इस समिति ने फिल्मों और फिल्मस्ट्रिपों को खरीदने से संबंधित सुझाव देने और फिल्मों के पूर्वनिरीक्षण के लिए विभिन्न समितियों (नामिकाओं) की सदस्यता की जाँच के लिए एक उप-समिति की स्थापना की। इस समिति ने विभिन्न उप-समितियों जैसे जी० ए० आर० पी० योजना उप-समिति, अनुसंधान उप-समिति, व्यावसायिक शैक्षिक संगठन उप-समिति, सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उप-समिति द्वारा दिए गए सुझावों की जाँच की और उनको स्वीकार किया। समिति ने अनुसंधान उप-समिति और सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उप-समिति को अनुसंधान और विकास परियोजना उप-समिति और कार्यक्रम उप-समिति के रूप में पुनः गठित करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा कार्यकारी समिति को दिया गया एक महत्वपूर्ण सुझाव विज्ञान मेलों के आयोजन से संबंधित है। इस समिति ने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् विज्ञान मेलों के आयोजन का समर्थन करे और परिषद् स्वयं देश में विज्ञान-शिक्षा को फैलाने के लिए अखिल भारतीय विज्ञान मेलों का आयोजन करे।

परिशिष्ट 3

वर्ष 1970-72 के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की लेखा विवरणी

समेकित प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता

(संख्या रुपए में)

प्राप्तियाँ		भुगतान		
अल्पशेष	29,94,698-10	योजनेतर व्यय		
सरकार से सहायतार्थ अनुदान		(क) वेतन तथा भत्तों तथा		2,10,65,743-10
(क) रा० शै० अनु० प्रशि० परि०		कार्यक्रमों आदि पर व्यय		1,97,90,294-90
को सामान्य अनुदान	2,74,18,530-00	(ख) कर्ज तथा पेशगियाँ		6,16,380-00
(ख) विशेष अनुदान	27,86,543-00	घटाया वसूलियाँ	2,38,961-80	2,40,931-80
				3,75,448-20
अन्य स्रोतों से अंशदान प्राप्तियाँ	8,000-00			
(क) प्रकाशन आदि की बिक्री	28,32,961-58	योजना व्यय		1,08,684,79-27
(ख) अन्य प्राप्तियाँ	17,00,869-01	विशेष अनुदान में से व्यय		23,01,516-29
भविष्य निधियाँ	13,06,320-39	भविष्य निधि		6,54,071-40
अन्य विविध जमा रक़मों और	9,97,703-98	जमा रकमें और पेशगियाँ		19,23,494-75
पेशगियों से प्राप्तियाँ		इतिशेष		41,31,141-40
जोड़	4,00,45,444-06	जोड़		4,00,45,446-06

परिशिष्ट 4

कैम्पसों का विकास

(क) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कैम्पस :—टाइप (II) कैडर के 32 और टाइप (III) के 32 और निदेशक के बंगले का निर्माण जिनके लिए वर्ष 1970-71 में प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति दी गई थी, अब पूरा होने वाला है। टाइप (I) के 32, टाइप (IV) के 16 और टाइप (V) के 8 क्वार्टरों जिनके निर्माण के लिए प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति वर्ष 1970-71 में दी गई थी, उनका निर्माण कार्य 1971-72 में प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कैम्पस में खाली पड़ी ऊबड़-खाबड़ जमीन को, जिस पर झाड़ियाँ उग आई थीं, प्रतिवेदन वर्ष में समतल किया गया। अब इसको ठीक-ठाक करने का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपने का प्रस्ताव है ताकि आस-पड़ोस सुन्दर लग सके।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एन० आई० ई०) कैम्पस में दिल्ली नगर निगम द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था 4 दिसंबर 1971 से हो गई। ट्यूबवैल के पानी को, जो पीने के योग्य नहीं था और जिसका प्रयोग गुसलखानों में किया जाता था, बन्द कर दिया गया और उसकी जगह नगर निगम का पानी प्रयोग किया जाता है। ट्यूबवैल का पानी अब बागवानी के लिए प्रयोग किया जाता है।

प्रतिवेदन वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कैम्पस में ऊँचे हौज के निकट छने जल को इकट्ठा करने के लिए भूमि के भीतर 40,000 गैलन क्षमता वाले टैंक का निर्माण-कार्य पूरा हो गया। इसके अलावा भूमि के भीतर बने टैंक के निकट पम्प भी लगाए गए हैं ताकि इस टैंक के छने पानी को ऊँचे बने हौज में पहुँचाया जा सके।

कार, साइकिल और स्कूटर रखने के शेड का निर्माण-कार्य 1971-72 के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रारम्भ किया गया। कुछ ही महीनों में इस कार्य के पूरा होने की संभावना है।

(ख) **क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के कैम्पस** :—जहाँ तक क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के कैम्पसों के विकास का संबन्ध है, इसका मुख्य कार्य पूरा हो गया है। प्रतिवेदन वर्ष में महाविद्यालयों में कर्मचारियों के लिए निवास भवनों के निर्माण करवाने की माँग को पूरा करने के लिए विशेष महत्व दिया गया। यह फैसला किया गया कि अब से क्षेत्रीय महाविद्यालयों के भवनों के अनुरक्षण और नए निर्माण कार्यों को राज्य लोक निर्माण विभाग की बजाए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सुपुर्द कर दिया जाए।

परिशिष्ट 5

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान पुस्तकालय

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एन० आई० ई०) के नई दिल्ली स्थित कैम्पस में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का एक काफी बड़ा पुस्तकालय है। यह पुस्तकालय विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्न विभागों के अनुसंधान कर्मचारियों की आवश्यकताओं का पूर्ति करता है। इसके उपयोग कर्ताओं में वे लोग भी सम्मिलित हैं जो दूसरे अनुसंधान और शैक्षणिक संगठनों में कार्य करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कैम्पस में सारे वर्ष आयोजित सेमिनारों और कर्मशालाओं आदि में आए राज्य स्तर के प्रतिनिधियों और अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा भी पुस्तकालय का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह पुस्तकालय बहुत सी स्थानीय संस्थाओं को अन्तर-पुस्तकालय उधार सुविधाएँ भी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान पुस्तकालय में लगभग एक लाख पुस्तकें और लगभग चार हजार पत्र-पत्रिकाओं के जिल्द बँधे हुए अंक हैं। इनमें लगभग 280 पत्र-पत्रिकाएँ भारतीय तथा विदेशी हैं जो वार्षिक चन्दा देकर प्राप्त की जाती हैं और लगभग 75 बिना मूल्य के प्राप्त होती हैं।

उपयोग कर्ताओं की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान पुस्तकालय हर मास शैक्षणिक विचार धाराओं संबन्धित विषयों पर लगभग 150 नई पुस्तकें खरीदता है।

प्रतिवेदन वर्ष में लगभग 2,500 नई पुस्तकें पुस्तकालय में बढ़ाई गई। इन नई पुस्तकों की एक सूची राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सब विभागों में घुमाई गई।

वर्ष 1971-72 में पुस्तकालय के हॉल और संदर्भ कक्ष की भीड़ की समस्याओं और अध्ययन कक्ष में बैठने की जगह को बढ़ाने के लिए तथा पुस्तकालय की सेवाओं को बढ़ाने के लिए 56,000 रुपये से कुछ अधिक मूल्य का फर्नीचर और उपकरण खरीदा।

पुस्तकालय का स्थान, उपयुक्त फर्नीचर और उपकरण आदि की कमी की समस्याओं का सामना करने और उनका समाधान करने के लिए पिछले वर्ष जिस राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान पुस्तकालय समिति की, जिसको केशवन समिति भी कहते हैं, नियुक्ति की गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस समिति ने पुस्तकालय खंड की डिजाइन, उसकी भू सम्पत्ति और पुस्तकालय स्टाफ की आवश्यकताओं और उनकी वेतन-दरों के संबन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

परिशिष्ट 6

पाठ्यक्रम विकास

वर्ष 1971-72 में पाठ्यक्रम विकास के क्षेत्र में की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है ।

1. विज्ञान और गणित :

1·01 प्राथमिक स्कूल स्तर पर विज्ञान :—विज्ञान में स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम विकास का लक्ष्य बच्चों के क्रियात्मक सहयोग से विज्ञान शिक्षण को सुधारना है । इस प्रयत्न में 'उत्पादन' की अपेक्षा विज्ञान की 'प्रक्रिया' पर जोर दिया गया है । प्रतिवेदन वर्ष में कक्षा पाँच के लिए 'साइन्स इज डूइंग' पाठ्यपुस्तक लिखी गई, सम्पादित की गई और उसकी अनेक प्रतिलिपियाँ तैयार की गई । ये प्रतिलिपियाँ आंध्र प्रदेश, मैसूर, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू और कश्मीर राज्यों को ग्रहण/अनुकूलन और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने और छापने के लिए भेजी गई । इस वर्ष विज्ञान शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत इस पाठ्यपुस्तक की हिन्दी अंग्रेजी पांडुलिपियाँ प्रेस को भेजी गई । इस पाठ्यपुस्तक के चित्र के आर्टपुल राज्यों में छप रहे क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों के लिए भेजे गए । इसकी अध्यापक दर्शिका की पांडुलिपि भी अंग्रेजी में तैयार की गई और उसका हिन्दी में अनुवाद किया गया । कक्षा तीन और चार की एक और पाठ्यपुस्तक 'मूल्यांकन विवरणिका' की प्रतियाँ राज्यों को उनके सुपरवाइजरों के स्कूल-निरीक्षण के समय प्रयोग करने के लिए भेजी गई ।

1·02 माध्यमिक विज्ञान शिक्षा परियोजना (यूनेस्को सहायता प्राप्त) :—यह एक चालू परियोजना है । प्रतिवेदन वर्ष में माध्यमिक स्कूल स्तर के पहले वर्ष के लिए विज्ञान के विभिन्न विषयों के पहले पाठ्यक्रमीय सामग्री प्रारूप विकसित किए गए और उनको छपने योग्य बनाया गया । मिडिल स्कूल स्तर के दूसरे वर्ष के लिए सारे विज्ञान विषयों की पाठ्यक्रमीय सामग्री को संशोधित किया गया और छापा गया । इसी स्तर के तीसरे वर्ष के लिए पाठ्यपुस्तकें छपने योग्य की गई । इस संबंध में किए गए कार्य का विषयानुसार विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है :—

भौतिकी :—कक्षा नौ के लिए 'भौतिकी भाग एक' पाठ्यपुस्तक लिखी गई। उसकी प्रतिलिपियाँ तैयार की गई और राज्यों को टिप्पणी के लिए भेजी गई। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर चित्रों को छोड़कर इसको संशोधित किया गया और छपने योग्य बनाया गया। कक्षा 10 की 'भौतिकी भाग दो' के चार अध्यायों का प्रारूप तैयार किया गया और पहला अध्याय लिखा भी गया। कक्षा 7 की पाठ्य-पुस्तक संशोधित कर छापी गई और कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक संशोधित की गई और उसका हिन्दी अनुवाद करके प्रेस को छपने के लिए भेजा गया। कक्षा 6 और 8 की अध्यापक दर्शिकाएँ पूर्णतः संशोधित की गई। कक्षा 6 और 7 के लिए किट गाइड, जिनमें कुछ प्रयोगों के संबंध में छोटे लेख भी हैं, मिम्योग्राफ करके वितरण के लिए तैयार किया गया। कक्षा 7 और 8 के लिए प्रदर्शन किट और उनके आदर्श रूप तैयार किए गए।

रसायन विज्ञान :—कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के छः अध्यायों के प्रारम्भिक प्रारूप तैयार किए गए जिनमें से तीन को सम्पादकीय समिति ने अंतिम रूप दिया। मिडिल कक्षाओं की 'रसायन विज्ञान' पाठ्यपुस्तक के भाग एक और दो के हिन्दी और अंग्रेजी रूपान्तरों को पुनः मुद्रण के लिए संशोधित किया गया। संशोधित पाठ्यपुस्तक के आधार पर 'रसायन विज्ञान भाग एक' की नई अध्यापक दर्शिका तैयार की गई, और उसको अंतिम रूप देकर छापा गया। रसायन विज्ञान प्रदर्शन किट तैयार और मिम्यूग्राफ किया गया। मिडिल स्कूल स्तर की 'रसायन विज्ञान' के आदर्श रूप विकसित किए गए और उनको अंतिम रूप दिया गया।

जीव विज्ञान :—कक्षा 9 के लिए जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक लिखने का कार्य चालू है। मिडिल स्कूल स्तर की 'जीव विज्ञान भाग एक' और 'जीव विज्ञान भाग दो' पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया गया और छपने भेजा गया। जीव विज्ञान किट के लिए अनुदेशीय पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया और मिम्यूग्राफ किया गया।

गणित :—देश के विभिन्न भागों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर कक्षा 6 की अंकगणित की पाठ्यपुस्तक और उसकी अध्यापक दर्शिका को संशोधित किया गया। कक्षा 8 की 'अंकगणित' के प्रारूप को संशोधित किया गया और 'अंकगणित-बीजगणित भाग एक' और 'अंकगणित-बीजगणित भाग दो' की अध्यापक दर्शिकाएँ तैयार की गई। कक्षा 9 के लिए अंकगणित और रेखागणित के प्रथम प्रारूप तैयार किए गए और विशेषज्ञों के साथ इस संबंध में विचार-विमर्श किया गया। श्रव्य-दृश्य सहायता प्रदर्शन किट और प्रयोगशाला किट तैयार किए जा रहे हैं। कक्षा दो के लिए "इन्साइट इन्टु मैथेमेटिक्स भाग दो" का पहला प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

1·03 विज्ञान शिक्षा (अध्ययन दल) के विकास के लिए व्यापक योजना :— 1971-72 अध्ययन दलों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष था। जीव विज्ञान और रसायन-विज्ञान अध्ययन दलों ने स्कूल स्तर के लिए पाठ्यपुस्तकें और अध्यापक दर्शिकाएँ बनाने का कार्य लगभग पूरा कर लिया है। संयोजक अध्ययन दल के अतिरिक्त, इन दो विषयों के सभी अध्ययन दलों ने एक अप्रैल 1971 से काम बंद कर दिया। जयपुर का भौतिकी अध्ययन दल एक अप्रैल 1972 को समाप्त कर दिया गया। इस विषय के शेष चार अध्ययन दलों ने, जो दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर और देहरादून में कार्य कर रहे हैं, सहयोगिक प्रयत्नों से उपयोगी सामग्री तैयार करने का फैसला किया। मैकैनिक्स के अतिरिक्त हाई स्कूल स्तर के पहले वर्षों के लिए पाठ्यपुस्तक विकसित की गई और उसके प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा था। मिडिल स्कूल स्तर की 'भौतिकी भाग तीन' को छपने के लिए भेज दिया गया। रसायन विज्ञान में मिडिल स्कूल स्तर के लिए पाठ्यक्रम सामग्री और, हाई स्कूल स्तर के पहले वर्ष के लिए पाठ्यक्रम और प्रयोगशाला पुस्तिका छापी गई। हाई स्कूल स्तर के पहले वर्ष के लिए रसायन विज्ञान की अध्यापक दर्शिका छपने के लिए प्रेस में भेजी गई और इसी विषय में हाई स्कूल स्तर के दूसरे और तीसरे वर्षों के लिए प्रयोगशाला पुस्तिका को प्रेस योग्य बनाया गया। हाई स्कूल स्तर के अंतिम दो वर्षों के लिए रसायन विज्ञान की अध्यापक दर्शिका विकसित करने का कार्य जारी था और जल्द ही इसको समाप्त करने की आशा थी। डा० जे० एन० कपूर के मेरठ विश्वविद्यालय के उप-कुलपति बन जाने से उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए मेरठ में एक गणित का अध्ययन दल प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। इस नए गणित के अध्ययन दल ने प्रतिवेदन वर्ष में अधिकतर हाई स्कूल स्तर के पहले और दूसरे वर्षों के लिए सामग्री विकसित की। अब तक मिडिल स्कूल की रेखागणित की तीन और बीजगणित की दो पुस्तकें छापी जा चुकी हैं। तीसरी पुस्तक की छपाई जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके अलावा रेखागणित की पहली और दूसरी पुस्तक की अध्यापक दर्शिका छापी गई और अंकगणित-बीजगणित की दूसरी और तीसरी पुस्तकों की अध्यापक दर्शिका छपने के लिए प्रेस भेजी गई। पाठ्यक्रमीय सामग्री को राज्य के विज्ञान शिक्षा संस्थानों और अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों को टिप्पणी के लिए भेजा गया। टिप्पणियाँ प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

1.04 स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण को दृढ़ करने के लिए यूनेस्को-यूनीसेफ सहायता प्राप्त मार्गदर्शी परियोजना :— अप्रैल 1967 में यूनेस्को-यूनीसेफ के साथ शिक्षा मंत्रालय के हुए समझौते के अंतर्गत सारे देश में स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण को सुधारने और बढ़ाने के लिए स्कूल वर्ष 1970 के शुरू से एक परियोजना प्रारंभ की गई। वर्ष 1971-72 तक सभी राज्य और तीन संघ क्षेत्र इस परियोजना को अपने चुने हुए 50 प्राथमिक और 30 मिडिल स्कूलों में कार्यान्वयन के लिए सहमत हो गए हैं। प्रतिवेदन वर्ष में परिषद् ने यूनीसेफ के नई दिल्ली स्थित अधिकारियों से संपर्क रख कर कार्य किया और भाग ले रहे सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में इस

अभियान परियोजना के कार्यान्वयन में उनकी सहायता की। परिषद् द्वारा विकसित अनुदेश सामग्रियाँ (पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम के साथ अध्यापक दर्शिकाएँ) राज्यों के ग्रहण/अनुकूलन और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए और प्रायोगिक स्कूलों में प्रयोग के लिए भेजी गई। इन सामग्रियों के हिन्दी अनुवाद परिषद् द्वारा सीधे हिन्दी भाषी राज्यों को भेज दिए गए। नए विज्ञान पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक स्कूलों द्वारा उपयोग के लिए परिषद् ने विज्ञान उपकरण किट के नमूने भी दिए। परिषद् ने राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थानों के मुख्य कार्मिकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जिनको बाद में अपने-अपने राज्यों के प्रयोगात्मक स्कूलों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना था। इसके अतिरिक्त परिषद् ने इस परियोजना के अंतर्गत 100 अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों और 400 अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों को यूनीसेफ उपकरण बाँटने की व्यवस्था की। 500 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को भेजे गए उपकरण का लगभग कुल मूल्य 95 लाख रुपये था। प्रतिवेदन वर्ष में बम्बई और मद्रास बंदरगाहों पर यूनीसेफ से कवर और टैक्स्ट कागज प्राप्त हुआ। आवरण कागज शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के आदेशानुसार राज्यों को वितरित कर दिया गया। शेष आवरण कागज आगे वितरित होने तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रकाशन एकक के गोदाम में रखा गया है। इसी प्रकार बम्बई बंदरगाह का शेष टैक्स्ट कागज नई दिल्ली में प्रकाशन एकक के गोदाम में और मद्रास बंदरगाह का शेष टैक्स्ट कागज क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में संबंधित राज्यों को वितरित करने तक रखा गया है। यूनीसेफ से प्राप्त आवरण कागज का मूल्य लगभग 6·25 लाख रुपये और टैक्स्ट कागज का लगभग 56 लाख रुपये है।

1·05 विज्ञान में पूरक पठन सामग्री का उत्पादन :—प्रतिवेदन वर्ष में, विज्ञान में पूरक पठन सामग्री तैयार करने का कार्य चालू रहा। इस कार्यक्रम की प्रगति का विवरण निम्नलिखित है :—

1. पुस्तकें जिनको छपने के लिए प्रेस में भेजा गया :—

(1) दि बर्ड माइग्रेशन

(2) ए० बी० सी० ऑफ एटम

(3) मेघनाद साहा का जीवन और कार्य

(4) फाइट अगेंस्ट डिज़ीजेज़-कैमोथ्रपी

(5) प्लांट वाइरेसस

(6) आवर एग्रीकल्चर

(7) दि स्पाइसेस

(8) मैनमेड फॉरेस्ट

(9) बायलौजिकल फ्लाक्स

2. पुस्तकें जो छपाई की प्रूफ स्थिति तक पहुँची :—

(1) दि स्टोरी ऑफ ट्रांस्पोर्ट

(2) आवर ट्री नेबर्स

(3) मेरीन प्लांट्स

(4) माइक्रोब्स

(5) मैडिसिनल प्लांट्स

3. पांडुलिपियाँ जो स्वीकृति के अंतिम चरण पर पहुँचीं :—

(1) दि स्टोरी ऑफ ग्लास

(2) दि स्टोरी ऑफ ऑयल

(3) एनीमल्स विदआउट बैकबोन

4. पांडुलिपियाँ जो अस्वीकृत कर दी गईं :—

(1) दि रिडिल ऑफ लाइफ

(2) पावर फ्रॉम वाटर

शेष 30 पुस्तकों में से 10 के पांडुलेख तैयार हो गए और उनको या तो समीक्षकों को भेज दिया गया या समीक्षा उपरांत संवर्द्धन के लिए लेखकों को भेज दिए गए।

1·06 विज्ञान किटों का उत्पादन :—परिषद् की केन्द्रीय विज्ञान कर्मशाला ने नए वैज्ञानिक उपकरणों के आवश्यक आदर्श तैयार करके तथा यूनेस्को-यूनीसेफ सहायता प्राप्त अभियान परियोजनाओं के कार्य का उत्तरदायित्व लेकर भी विज्ञान के पाठ्यक्रम विकास कार्यक्रमों में सहायता देना जारी रखा। प्रतिवेदन वर्ष में मिडिल स्कूल स्तर के अंतिम वर्ष के लिए भौतिकी प्रदर्शन किट नं० III विकसित किया गया। इसके साथ-साथ इस स्तर के लिए भौतिकी किट शृंखला पूरी हो गई। प्रकाश, चुम्बकीयता और विद्युत के विषय क्षेत्रों पर तात्कालिक उपकरण विकसित किए गए। एक आदर्श रूप विकसित किया गया और उसका प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया। इस नमूने के आधार पर 74 वस्तुओं से युक्त 600 किट बक्से प्रयोगात्मक स्कूलों को वर्ष 1972-73 में देने के लिए तैयार किए जाएँगे। किट बक्से की छत इतनी चौड़ी होगी कि ग्रामों के स्कूलों में जहाँ अलग से मेजें नहीं हैं, इसका

प्रदर्शन-मेज के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। किट को रखने में कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि उसे कमरे के एक कोने में रखा जा सकता है। छात्र भौतिकी किट नं० III भी विकसित किए गए। छात्र-किट में बहुत सी वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका प्रयोग छात्र स्वयं कर सकते हैं। एक समय में 45 छात्र एक साथ इस किट का उपयोग कर सकते हैं। छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या दो दलों में विभक्त हो कर कार्य कर सकते हैं। छात्रों को रसायन विज्ञान परीक्षण की उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान करने के लिए एक विशेष किट (मिडिल स्कूलों के रसायन विज्ञान प्रदर्शन किट का पूरक किट) विकसित किया गया। दो या दो से अधिक छात्र एक ही साथ इस पर कार्य कर सकते हैं। यह किट 37 वस्तुओं से युक्त एक छोटे अल्यूमिनियम बक्से में है। यह किट इस ढंग से बनाया गया है कि गाँव के स्कूलों में जहाँ अलग से मेजें नहीं हैं, इसका प्रदर्शन-मेज के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। किट को रखने में कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि उसे कमरे के एक कोने में रखा जा सकता है। विज्ञान शिक्षण की यूनेस्को-यूनीसेफ-सहायता प्राप्त मार्गदर्शी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के छः छः सौ किट 1971-72 वर्ष में परिषद् की केन्द्रीय विज्ञान कर्मशाला में तैयार किए गए :—

1. भौतिकी प्रदर्शन किट नं० II
2. रसायन विज्ञान किट मिडिल स्कूलों के लिए
3. मिडिल स्कूलों के लिए जीव विज्ञान किट

इसके अतिरिक्त भौतिक अध्ययन दल के 15 किट कर्मशाला में तैयार किए गए। यह किट एक राज्य के प्रमुख संस्थानों और प्रयोगात्मक स्कूलों में प्रयोग के लिए भेजे गए।

1.07 विज्ञान शिक्षा के लिए अनुदेश सामग्री केन्द्र :—प्रतिवेदन वर्ष में विज्ञान शिक्षा के अनुदेश सामग्री केन्द्र ने स्कूल विज्ञान ज्ञान को एकत्रित करने और प्रचार करने का कार्य जारी रखा। इस केन्द्र द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन निम्नलिखित हैं :—

1. प्रदर्शित सामग्री को अच्छा और भावपूर्ण बनाने के लिए उसका पुनः गठन।
2. जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य से विज्ञान सामग्री और अध्यापन सहायताओं की प्राप्ति।
3. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कैम्पस, भुवनेश्वर, बालभवन और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन, और
4. भुवनेश्वर में विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन के अवसर पर पुस्तिकाओं की तैयारी।

केन्द्र ने इस वर्ष विज्ञान पत्रिकाएँ और दूसरी सेकेंड्री विज्ञान सामग्रियाँ 24 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से विनिमय आधार पर प्राप्त कीं। इस वर्ष राज्यों के अध्यापक शिक्षकों, स्कूल निरीक्षकों, वैज्ञानिक पर्यवेक्षकों, वैज्ञानिक परामर्शदाताओं, विशिष्ट व्यक्तियों और विदेशी विद्वानों द्वारा केन्द्र का निरीक्षण हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विज्ञान शिक्षा विभाग में प्राथमिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना की ओर प्रगति हुई है। किट के उपकरण के आधार पर कार्यकलापों के प्रदर्शन के साथ प्राथमिक विज्ञान अनुदेश सामग्री के विकास की विभिन्न अवस्थाओं और तात्कालिक उपकरणों को केन्द्र में प्रदर्शित किया गया है।

1·08 **आनुषंगिक पाठ्यक्रम परियोजना** :—प्राथमिक विज्ञान के शिक्षण और तत्वज्ञान के नए प्रयास को समझाने के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत अंग्रेजी में "साइन्स इज डूइंग" फिल्म तैयार की गई। यूनेस्को-यूनीसेफ सहायता प्राप्त अभियान परियोजा के अंतर्गत राज्यों को वितरित करने के लिए हिन्दी में फिल्म तैयार की गई जिनका प्रयोग अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों में होगा। प्राथमिक विज्ञान पर दूसरी फिल्म "रॉक्स, एवावेल्स उ'ड मिनिरेल्स" का खाका तैयार किया गया और उस पर विचार विमर्श किया गया। तीसरी फिल्म "टीचिंग ऑफ एलीमेन्ट्री फिजिक्स टुडे" की शूटिंग का पांडुलेख लगभग तैयार हो गया था। इस फिल्म का उद्देश्य मिडिल स्कूल स्तर पर नए शैक्षणिक प्रौद्योगिकी की प्रभावता पर प्रकाश डालना है।

प्रतिवेदन वर्ष में प्राथमिक विज्ञान शिक्षण और भौतिकी शिक्षण पर दो स्लाइडें तैयार की गई और उनकी प्रतियाँ समस्त देश में लगभग 100 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को भेजा गया। मिडिल स्कूल स्तर के हर वर्ष के लिए विज्ञान के प्रत्येक विषय पर दो फिल्म स्ट्रिपें और 20 स्लाइडें तैयार करने के कार्यक्रम की योजना बनाई गई। मिडिल स्कूल भौतिकी और जीव विज्ञान पर बनाई गई 20 और 30 स्लाइडों के लिए एक शूटिंग पांडुलेख तैयार किया गया।

भौतिकी में द्रव्य के दबाव पर बनाई जाने वाली फिल्मस्ट्रिप लगभग पूरी हो चुकी थी और गणित फिल्मस्ट्रिप बनाने का कार्य चालू हो गया था। मिडिल स्कूल भौतिकी की फिल्मस्ट्रिप "स्ट्रक्चर ऑफ मैटर" का शूटिंग पांडुलेख तैयार किया गया।

कक्षा तीन और चार के लिए बनाए गए पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन पुस्तिका की प्रतिलिपियाँ तैयार करके राज्यों को वहाँ के निरीक्षकों के स्कूल निरीक्षण के समय प्रयोग करने के लिए भेज दी गयीं। इसी प्रकार की पुस्तिकाएँ कक्षा 6 की भौतिकी और जीव विज्ञान और कक्षा 8 की भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए तैयार की गईं। सचित्र किट गाइड्स भी तैयार की गईं और उनकी मिम्योग्राफ प्रतियाँ विज्ञान शिक्षण की यूनेस्को-यूनीसेफ सहायता प्राप्त अभियान परियोजना के अंतर्गत प्रयोगात्मक स्कूलों को भेजी गईं। फरवरी 1973 में मनाई जाने वाली

कापरनिकसर शताब्दी के लिए 'कापरनिकस' पर एक पुस्तिका बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

2. सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी

2·01 सामाजिक अध्ययन :—अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन की एक विस्तृत हस्तपुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया। इसकी पांडुलिपि प्रेस भेजने के लिए तैयार थी। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के दूसरे भाग के तैयार करने के कार्य में प्रगति हुई। कक्षा 1 से 12 तक के लिए सामाजिक अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम प्रारूप को संशोधित किया गया। परिषद् ने आई० आई० टी० कानपुर के प्रयोगात्मक स्कूल के सहयोग से सामाजिक अध्ययन कक्षा एक से पाँच तक की अभ्यास पुस्तिकाएँ तैयार कीं।

2·02 इतिहास :—वर्तमान में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विश्व इतिहास विषय को पढ़ाए जाने की प्रवृत्ति नजर आ रही है। बहुधा इस पाठ्यक्रम के गठन का कोई तार्किक आधार नहीं होता है। इस विषय के शिक्षण के उचित ऐतिहासिक संदर्भ को निश्चित करने के लिए परिषद् ने 1971-72 में विश्व इतिहास पर एक परियोजना का आयोजना किया। इस परियोजना का उद्देश्य विश्व इतिहास पाठ्यक्रम का उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए गठन करना है। इसके लिए अध्ययन योजना और विषयसूची के विभिन्न एककों का विशेष तार्किक ढंग से विस्तार में कार्य होता है। इस पाठ्यक्रम को लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय कर्मशाला में तैयार किया गया और अंतिम रूप दिया गया। एक वर्किंग ग्रुप द्वारा मिडिल स्तर के इतिहास के अध्यापकों के लिए एक हस्तपुस्तिका का खाका तैयार किया गया। इस वर्किंग ग्रुप ने इस हस्तपुस्तिका के कुछ अध्यायों को विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया। कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक 'आधुनिक भारत' को तैयार और मुद्रित किया गया। सेकेंड्री स्तर पर इतिहास शिक्षण में विद्यार्थियों के भाग लेने पर हुए एक अखिल भारतीय सेमिनार की अनुवर्ती कार्य. वाही के अनुसार एक पुस्तिका तैयार करने का कार्य इस वर्ष भी चालू रहा। इस पुस्तिका की पांडुलिपि जल्दी ही प्रेस को भेज देने की सम्भावना है। सेकेंड्री स्कूलों के इतिहास के अध्यापकों के लिए तैयार की गई हस्तपुस्तिका के कुछ अध्यायों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया गया।

2·03 नागरिक शास्त्र :—उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम को नवम्बर 1971 में हुई एक कर्मशाला में विकसित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम प्रारूप को एक समीक्षा के सामने अंतिम रूप देने के लिए रखा गया। पांडुलिपि को जल्दी ही प्रेस भेजने की संभावना है। नागरिक शास्त्र विषय के अनुभवी व्यक्तियों की एक समीक्षा दल ने जून-जुलाई 1971 में हुई एक

बैठक में कक्षा 8 की नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक 'स्वतंत्र भारत' की पांडुलिपि की समीक्षा की। समीक्षा दल की रिपोर्ट के आधार पर इस पांडुलिपि को राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग में अंतिम रूप दिया गया। इस पांडुलिपि को बाद में छपने के लिए भेज दिया गया। इस पुस्तक के साथ ही मिडिल स्कूल स्तर की नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों के तैयार करने का कार्य पूरा हो गया।

2·04 भूगोल :—कक्षा 8 की भूगोल पाठ्यपुस्तक 'यूरोप और भारत' के हिन्दी और अंग्रेजी अनुवाद की पांडुलिपियाँ गत वर्ष ही तैयार कर ली गई थीं। प्रतिवेदन में इसके चित्र बनाने और छापने का कार्य पूरा कर लिया गया। इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद अगस्त 1971 में छप गया। अंग्रेजी संस्करण का कार्य अंतिम चरण पर था और उसके जल्दी मुद्रित हो जाने की सम्भावना थी।

2·05 अर्थशास्त्र :—नवम्बर 1971 में आयोजित एक कर्मशाला में सेकेंड्री स्कूलों के लिए एक अर्थशास्त्र अध्यापक दर्शिका की सामग्री विकसित की गई और उसको अंतिम रूप दिया गया।

2·06 मातृ भाषा :—उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की हिन्दी गद्य और पद्य की नई पाठ्यपुस्तकों (काव्य भारती और गद्य भारती) के अंतिम प्रारूप को तैयार किया गया और अब उनकी पांडुलिपि प्रेस के लिए तैयार है। सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग द्वारा तैयार की गई हिन्दी की नई प्रवेशिका टिप्पणी के लिए पाठ्यपुस्तक विभाग को भेज दी गई। टिप्पणियाँ प्राप्त हो गई हैं और उनका अध्ययन किया जा रहा है।

2·07 दूसरी भाषाएँ :—द्वितीय भाषा के रूप में बँगला भाषा की प्रथम पाठ्यपुस्तक की प्रेस पांडुलिपि और चित्र तैयार किए गए। पुस्तक को छपने के लिए भेज दिया गया।

2·08 संस्कृत :—संस्कृत की पहली पाठ्यपुस्तक तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इस श्रृंखला की पहली और दूसरी पाठ्यपुस्कों के 1972-73 में तैयार होने की संभावना है।

2·09 प्राथमिक स्तर में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मानकों का विकास :—प्रतिवेदन वर्ष में निम्नलिखित पूरक पठन पांडुलिपियों को अंतिम रूप दिया गया और परिषद् के प्रकाशन एकक को छपने के लिये भेज दिया गया है :

1. गिरिराज हिमालय
2. पीप्स थ्रू दि मिलैनियम
3. वन सम्पत्ति

2·10 स्कूल शिक्षा के लिए समन्वित पाठ्यक्रम योजना :—प्रतिवेदन वर्ष में सारे स्कूल स्तर के लिए सामान्य शिक्षा का समन्वित पाठ्यक्रम तैयार किया गया। इस योजना में स्कूल शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल स्तर की अध्ययन योजना, विभिन्न विषयों के पढ़ाने का समय, हिन्दी अध्ययन का प्रथम और दूसरी भाषा के रूप में विस्तृत पाठ्यक्रम, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा जनसंख्या शिक्षा सम्मिलित है।

2·11 अनुदेशीय सामग्री की तैयारी :—1971-72 में इतिहास और भूगोल की 24 पुस्तिकाओं की पांडुलिपियों को अंतिम रूप दिया गया। इस वर्ष इन दो विषयों की 6 पुस्तिकाओं को तैयार किया गया और छपने भेजा गया।

2·12 भाषाओं के शिक्षण को सुधारने के लिये विधियों और सामग्रियों के विकसित करने की योजना का एन० सी० ई० आर० टी० से मैसूर के भारतीय भाषाओं के केन्द्रीय संस्थान को हस्तांतरण :—केन्द्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के मई 28, 1971 के पत्र संख्या एफ० 8-17/71 एल०/2 द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार भाषाओं के शिक्षण को सुधारने के लिए विधियों और सामग्रियों के विकसित करने की योजना को एन० सी० ई० आर० टी० से मैसूर के भारतीय भाषाओं के केन्द्रीय संस्थान (सी० आई० आई० एल०) को हस्तांतरित कर दिया गया। चूँकि 1971-72 में योजना को कार्यान्वित करने के लिए निधि परिषद् के बजट में है, इसलिए यह फैसला किया गया कि सी० आई० आई० एल० का निदेशक उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के नियंत्रण का कार्य तुरन्त ग्रहण कर लेगा जिनको कि एन० सी० ई० आर० टी० ने केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान, हैदराबाद और डेकन कालेज, पूना और अन्नामलाई विश्वविद्यालय के भाषाओं में उच्च अध्ययन के केन्द्रों को सुपुर्द किया है। सी० आई० आई० एल० के निदेशक की सिफारिशों पर एन० सी० ई० आर० टी० इन संस्थाओं को 1971-72 में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निधि देगा। परिषद् सी० आई० आई० एल० के निदेशक को परियोजनाओं के निरीक्षण में आवश्यक निजी सहायता देने को सहमत हो गई है। वर्ष 1972-73 से इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था सी० आई० आई० एल०, मैसूर के बजट में कर दी जायेगी।

(3) प्राथमिक स्तर में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम मानकों का विकास

प्राथमिक शिक्षा स्तर के लिए न्यूनतम पाठ्यक्रम मानकों को विकसित करने की परियोजना पाठ्यक्रम योजना क्षेत्र में एक नई परियोजना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक स्कूल जाने वाले छात्र के लिये अपेक्षित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर न्यूनतम ध्येयों की प्राप्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सर्वसम्मत्ति के लिए वातावरण उत्पन्न करना है। प्रतिवेदन वर्ष में प्राथमिक स्तर पर प्राप्त शिक्षण परिणामों के

आंकड़े एक अखिल भारतीय कर्मशाला में तैयार किए गए जिसमें राज्य शिक्षा विभागों के प्रतिनिधियों और राज्य शिक्षा संस्थानों के इस क्षेत्र के गैर सरकारी विशेषज्ञों ने भाग लिया। प्राप्त शिक्षण परिणामों की पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए और जाँच-पड़ताल की जाएगी।

(4) कार्य अनुभव पाठ्यक्रम

परिषद् द्वारा कार्य-अनुभव में विकसित पाठ्यक्रम को 1971-72 में हैदराबाद शहर और जिले के 30 चुने हुए स्कूलों में आजमाया गया। इन स्कूलों के अध्यापकों को कार्य-अनुभव पाठ्यक्रम में अनुस्थापित किया गया और कार्यक्रम को चलाने के लिये उपकरण भी उपलब्ध किए गए।

(5) शिक्षण सहायक साधन

पिछले कुछ वर्षों से पूर्ण विद्यालय स्तर पर शिक्षा में शिक्षण उपकरणों के उपयोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम पर राष्ट्रीय परिषद् कार्य करती रही। इसमें अल्प व्यय तकनीकें जैसे फलैनल ग्राफ किट, ग्राफिक किट आदि शामिल हैं, जो विद्यालय अवस्था में अत्यंत उपयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ी मात्रा में विविध स्कूल विषयों की फिल्म स्ट्रिपें, चार्ट्स रेखाचित्र, और अन्य संबंधित सामग्री का निर्माण किया गया। प्रतिवेदन वर्ष में निम्नलिखित किट सामग्रियों का उत्पादन किया गया।

फिल्में

"साइंस इज डूइंग" पर एक फिल्म तयार की गई जिसके 100 प्रिंट्स तैयार किए गए। इस फिल्म को हिन्दी में भी डब किया गया।

"टीचिंग ऑफ एलीमेंटरी फिजिक्स टुडे" का उपचार पांडुलेख तैयार किया गया और संशोधित किया गया।

बच्चों की फिल्म "सुनो कथा श्री राम की" के चार प्रिन्ट्स तैयार किए गए और विदेश मंत्रालय को भेजे गए।

फिल्म स्ट्रिपें

निम्नलिखित फिल्म स्ट्रिपें तैयार की गई :—

1. जम्मू और कश्मीर
2. रोड सेफ्टी
3. थ्री डी टीचिंग एड्स इन प्लास्टर ऑफ पेरिस

4. डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग ऐड्स

राष्ट्रीय आपातस्थिति पर पोस्टर

राष्ट्रीय आपातस्थिति के दौरान निम्नलिखित पोस्टर तैयार किए गए, छापे गए और दिल्ली की शैक्षिक संस्थाओं को बाँटे गए :—

1. डोनेट ब्लड

2. नया देश बँगला देश

3. राष्ट्रीय एकता

4. "घूस खोरी" इज ए सोशल क्राइम

5. सोचो

आवर इंडिया पर अध्ययन किट :—"आवर इंडिया" अध्ययन किट का संशोधित संस्करण तैयार किया गया।

प्राचीन भारत पर इतिहास पैकेज :—प्रतिवेदन वर्ष में प्राचीन भारत पर इतिहास पैकेज बनाने के कार्य को समाप्त करने की दिशा में प्रगति हुई है।

परिशिष्ट 7

राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना

विज्ञान प्रतिभा खोज की 1971 की परीक्षा में लगभग 1000 प्रत्याशी साक्षात्करण के लिए सफल हुए। साक्षात्कारण के आधार पर 359 प्रत्याशी अंतिम रूप से छात्रवृत्तियों के लिए चुने गए। 1968 से 1971 तक छात्रवृत्ति पाने वाले प्रत्याशियों की संख्या का राज्यानुसार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

विज्ञान प्रतिभा खोज की 1972 की परीक्षा सारे देश में 350 केन्द्रों में आयोजित की गई और इसमें लगभग 7,200 प्रत्याशियों ने भाग लिया। इस परीक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का फैसला 1972 में इन्टरव्यू के बाद होगा।

अवर स्नातक स्तर के प्रत्याशियों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में चार सप्ताह की अवधि के 19 ग्रीष्मकालीन स्कूलों की योजना तैयार की गई जिनमें से मई-जून 1971 में 18 ग्रीष्मकालीन स्कूलों का विभिन्न विश्वविद्यालय केन्द्रों में आयोजन हो सका। स्नातकोत्तर प्रत्याशियों को उनके ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों के लिए 25 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उच्च शिक्षा के संस्थानों में भेजा गया। अमरीका और इंग्लैंड से 15 प्रतिभाशाली छात्रों के दल ने सितम्बर 1971 में इस देश का दौरा किया। इनके लिए राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना के दिल्ली स्थित प्रत्याशियों से मिलने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

अनुबंध

1968 से 1971 तक राष्ट्रीय विज्ञान-प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियाँ पाने वाले प्रत्याशियों की संख्या का राज्यानुसार विवरण

राज्य क्षेत्र का नाम	प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या			
	1968	1969	1970	1971
1. आंध्र प्रदेश	4	11	3	11
2. असम	4	5	—	3
3. बिहार	7	14	6	8
4. गुजरात	4	7	3	6
5. हरियाणा	—	1	—	—
6. जम्मू तथा कश्मीर	—	—	1	—
7. केरल	32	11	13	10
8. मध्य प्रदेश	9	10	8	15
9. महाराष्ट्र	30	35	36	51
10. मैसूर	30	5	12	15
11. नागालैंड	—	—	—	—
12. उड़ीसा	3	2	2	10
13. पंजाब	3	2	6	2
14. राजस्थान	9	8	20	4
15. तमिलनाडु	16	21	28	32
16. उत्तर प्रदेश	46	25	15	24
17. पश्चिम बंगाल	55	77	54	72
18. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—
19. चंडीगढ़	1	—	2	—
20. दिल्ली	100	124	149	93

21. गोवा	—	—	—	—
22. हिमाचल प्रदेश	1	1	1	—
23. लक्कादीव, मिनीकाय तथा अमीन दिवी द्वीप समूह	—	—	—	—
24. मणिपुर	1	—	—	—
25. नेफा	—	—	—	—
26. पांडिचेरी	—	—	—	—
27. त्रिपुरा	—	—	—	—
जोड़	355 (5)	359 (10)	359 (11)	359 (11)

नोट :—कोष्ठक में दी गई संख्या गणित के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति पाए छात्रों की संख्या प्रदर्शित करती है ।

परिशिष्ट 8

शिक्षा तथा राष्ट्रीय एकीकरण परियोजना समाज कल्याण मंत्रालय ने परिषद् को विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूल के छात्रों में राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने का कार्य सौंपा। परिषद् ने प्रतिवेदन वर्ष में राष्ट्रीय एकीकरण परियोजना के अंतर्गत जो प्रमुख कार्यक्रम प्रारम्भ किए वे निम्नलिखित हैं :—

(क) छात्रों तथा अध्यापकों के लिए अन्तर्राज्यीय शिविरों का आयोजन करना तथा अध्यापकों और मुख्याधापकों के लिए अलग से शिविरों का आयोजन करना।

(ख) चुने हुए स्कूलों में "हमारा भारत परियोजना" शुरू करना, और

(ग) छात्रों तथा अध्यापकों के लिए विषय से संबंधित उपयुक्त सामग्री तैयार करना।

(क) अन्तर्राज्यीय शिविरों का आयोजन

मई-जून 1971 में छात्र-अध्यापक के सात अंतर्राज्यीय शिविर श्रीनगर, पूना, त्रिवन्दरम, दार्जिलिंग, छम्ब, नेतरहाट और माउंट आबू में आयोजित किए गए। नवम्बर-दिसम्बर 1971 और जनवरी 1972 में दस शिविरों के आयोजन की योजना बनाई गई थी परन्तु राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति के कारण केवल दो शिविर भटिंडा और कानपुर में आयोजित किए गए। इन दोनों शिविरों में पाँच राज्यों से छात्र और अध्यापक आमन्त्रित किए गए।

अब तक लगभग सभी राज्य इस योजना में भाग ले चुके हैं और प्रत्येक राज्य के बारह से अधिक स्कूलों ने अन्तर्राज्यीय छात्र-अध्यापक शिविरों में भाग लिया है।

प्रत्येक शिविर को आयोजित करने से पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कैम्पस में शिविर निदेशकों तथा आयोजकों के लिए दो दिन की अनुस्थापना बैठक की व्यवस्था की गई।

छात्रों तथा अध्यापकों के शिविरों में जो कार्यक्रम किए गए उनमें शिविर में आए अन्य साथियों की भाषाएँ सीखना, वार्ताएँ, विचार-विमर्श और वाद-विवाद, प्रदर्शनियाँ, परिभ्रमण और यात्राएँ, शारीरिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की प्रोन्नति के लिए कार्यक्रम सांस्कृतिक तथा मनोरंजक कार्यक्रम आदि सम्मिलित थे ।

मई-जून 1971 में बड़ौदा और कोयम्बतूर में दो अन्तर्राज्यीय शिविर केवल अध्यापकों के लिए आयोजित किए गए । लगभग सभी राज्यों के अध्यापकों ने इन शिविरों में भाग लिया । इन अध्यापक शिविरों के कार्यकलापों में 'अपना राज्य जानो' परियोजना, इस विषय से संबंधित अनुदेशन सामग्री की तैयारी, विशेषज्ञों द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ाने में अध्यापकों के कर्तव्य, सामाजिक अध्ययन द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण, भूगोल और सृजनशील नाट्यों द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण जैसे विषयों पर वक्तव्य सम्मिलित है ।

एक शिविर लखनऊ में नवम्बर 1971 में केवल स्कूलों के मुख्याध्यापकों के लिए आयोजित किया गया । असम और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के 71 मुख्याध्यापकों ने इस शिविर में भाग लिया । प्रसिद्ध वक्ताओं को शिविरकों सेविचार-विमर्श के लिए आमन्त्रित किया गया । शिविरकों को 6 दलों में विभक्त किया गया । प्रत्येक दल निम्नलिखित विषयों में से एक से संबंधित था ।

(1) पाठ्यक्रम

(2) पाठ्यक्रम कार्यकलाप

(3) विचार विनिमय द्वारा ज्ञान

(4) स्कूल और समाज

(5) हमारा भारत प्रदर्शनी

(6) समन्वय

इन दलों द्वारा तैयार सामग्री से एक हस्तपुस्तिका तैयार की गई जिसका प्रयोग स्कूलों में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाने के लिए आयोजित कार्यकलापों के मार्गदर्शन के लिए किया जा सकता है । इस हस्तपुस्तिका की सामग्री ठीक की जा रही है और छपवाने की योजना है । शिविर में आए मुख्याध्यापक अपने साथ अपने-अपने राज्य की विशेषताओं से संबंधित सामग्री लाए । इस सामग्री का शिविर में प्रदर्शन किया गया ।

(ख) 'हमारा भारत परियोजन'

'हमारा भारत परियोजन' की योजना शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूल के बच्चों में राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने के समस्त कार्यक्रम का

एक अभिन्न अंग है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को विभिन्नताओं में एकता समझना है जो हमारे भारत का विशिष्ट लक्षण है। इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

(1) छात्रों तथा अध्यापकों के अन्तर्राज्यीय शिविरों में प्राप्त उपलब्धियों तथा अनुभवों को कार्यान्वित करना,

(2) प्रत्येक स्कूल में छात्रों तथा अध्यापकों के अन्तर्राज्यीय शिविरों के कार्य को अनुसरण करना, और

(3) छात्रों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करने के लिए शिविरों में भाग लेने वाले सभी स्कूलों को परियोजना में शामिल करके छात्रों तथा अध्यापकों के अन्तर्राज्यीय शिविरों के प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार करना।

इस परियोजना के अंतर्गत शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय छटे हुए 100 स्कूलों को 1000 रुपए प्रति स्कूल की दर से अनुदान देती है।

स्कूलों द्वारा इस परियोजना के अन्तर्गत जो कार्यकलाप किए जाते हैं वह हैं निबंध, पाठांतर, वाक्पटुता और वाद-विवाद प्रतियोगताएँ, हस्तलिखित पत्रिकाओं का प्रकाशन जिनमें छात्र रचित लेख हों, राज्यों के ऐतिहासिक, भूगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं पर किए जा रहे अध्ययन पर आधारित चार्ट्स, माडेल, नकशे, ग्राफ इत्यादि बनाना।

(ग) छात्रों तथा अध्यापकों के लिए अनुदेशन सामग्री तैयार करना :—

परियोजना के इस पहलू के अंतर्गत छात्रों तथा अध्यापकों, दोनों के लिए उपयोगी सामग्री प्रकाशित करने का विचार है। प्रतिवेदन वर्ष में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के अध्यापकों के लिए एक हस्तपुस्तिका 'ज्योग्राफी एंड नेशनल इंटीग्रेशन' तैयार की जा रही थी। भारत की विभिन्न भाषाओं के बहुत से राष्ट्रीय एकीकरण के गीतों को एकत्र करके पुस्तक के रूप में संग्रह किया गया। 'आवर नेशनल सांग' नामक पुस्तक को राष्ट्रीय एकीकरण परियोजना की स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखी जानी थी। 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों के लाभ के लिए एक पूरकपठन रीडर 'भारत को प्रकृति के उपहार' निर्माणाधीन थी। राष्ट्रीय एकीकरण पर एक सामान्य सीखने-सिखाने की युक्ति का अध्ययन किट विकसित किया जा रहा है जिसमें संबंधित नाना प्रकार की श्रव्य-दृश्य सामग्री और विषय से संबंधित साहित्य को एकत्रित किया गया है।

परिशिष्ट 9

जनसंख्या शिक्षा

जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हमारे जैसे विकासशील देशों के लिए चिन्ता का विषय है। उन्नति से होने वाले सारे लाभ जनसंख्या की अद्‌भुत वृद्धि नष्ट कर देती है। इसी लिए जनसंख्या शिक्षा को सारे विश्व में आवश्यक समझा जा रहा है।

स्कूल स्तर पर जनसंख्या शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने जनसंख्या शिक्षा की नई परियोजना का कार्यभार 1969-70 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को सौंप दिया। परिषद् ने 1970-71 में सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग में एक नये एकक की स्थापना की जो इस क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करेगा और उनको कार्यान्वित करेगा।

प्रतिवेदन वर्ष में इस एकक ने स्कूल स्तर के लिए जनसंख्या शिक्षा में एक पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार किया और अनुदेश सामग्री तैयार करने और इन कार्यक्रमों को राज्यों में कार्यान्वित करने का कार्य आरम्भ किया। विभिन्न राज्यों के शिक्षा निदेशकों और राज्य शिक्षा संस्थानों के निदेशकों को एकक द्वारा विकसित सामग्रियों और पाठ्यक्रमों से अवगत कराने के लिए एक भारतीय कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया। स्कूल छात्र, अध्यापक प्रशिक्षक और स्कूल छोड़े हुए विद्यार्थियों के लिए जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए इस कान्फ्रेंस ने लाभदायक सुझाव दिए। इस एकक द्वारा कहानी पुस्तकों और आहार हस्त-पुस्तिका के लिए तैयार की गई अनुदेशन सामग्री की इस वर्ष दो समीक्षा दलों की बैठकों में समीक्षा की गई। अध्यापकों के लिए जनसंख्या शिक्षा पर सेवा-पूर्व और सेवा-कालीन प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक वर्कशाप का आयोजन किया गया। जनसंख्या शिक्षा पर दूसरी वर्कशाप का आयोजन परिषद् ने हरियाणा सरकार के सहयोग से किया। भारत की परिवार नियोजन संस्था, कोलम्बो प्लान ब्यौरो, कोलम्बो, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्रालय, नई दिल्ली, भारतीय चिकित्सा संस्था, नई दिल्ली, और उदयपुर, पटना और गुड़गाँव

के राज्य शिक्षा संस्थानों इत्यादि द्वारा जनसंख्या शिक्षा और उस से संबंधित विषयों पर आयोजित कार्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा एकक के अफसरों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त इस एकक ने प्रतिवेदन वर्ष में निम्नलिखित साहित्य प्रकाशित किया :—

(1) रिपोर्ट ऑफ दि नेशनल सेमिनार ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन।

(2) पॉपुलेशन एजुकेशन इन स्कूल कैरीकुल्ला

(3) रीडिंग्स इन पॉपुलेशन एजुकेशन

(4) पॉपुलेशन—ए ड्राफ्ट सिलेबस

(5) इंडियन पॉपुलेशन सिचुएशन

(6) ए बिब्लयो ग्राफी ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन

(7) प्लग प्वांइट्स फॉर पॉपुलेशन एजुकेशन इन स्कूल कैरीकुल्ला,

(8) पॉपुलेशन एजुकेशन अंडर दि करेन्ट प्रॉबलम्स इन एजुकेशन सीरीज

जिन दो पुस्तकों की पांडुलिपियाँ प्रेस में छपने भेजी गई वे हैं :— (1) विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अक्तूबर 1971 में आयोजित नेशनल कानफ्रेंस की रिपोर्ट, और (2) रीडिंग्स इन पॉपुलेशन एजुकेशन (द्वितीय भाग)।

परिशिष्ट 10

ग्रामीण प्रतिभा खोज योजना

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ने माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की एक योजना प्रारम्भ की है। जबकि इस योजना का प्रशासकीय दायित्व शिक्षा मन्त्रालय पर है फिर भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने के लिए दूसरे स्तर पर परीक्षा लेने के काम में राज्यों को अकादमिक मार्गदर्शन उपलब्ध करने की जिम्मेदारी सँभालने के लिए कहा गया। परिषद् से यह भी कहा गया कि वह प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने और विभिन्न राज्यों की पाठचर्या को एक दूसरे की तुलना में अधिकाधिक समरूप बनाने के लिए इस योजना के अकादमिक पक्ष का समन्वय और अनुसंधान करे। इस योजना के अधीन अकादमिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए परिषद् में एक विशेष एकक बनाने का प्रस्ताव है। परिषद् की कार्यकारी समिति की 10 फरवरी 1972 को हुई बैठक में इस एकक के कार्यों और विस्तार क्षेत्रों का विस्तार करने के बारे में विचार किया गया ताकि पिछड़ी जातियों के प्रतिभाशाली बच्चों को छाँटने का कार्य भी इस एकक को दिया जा सके। कार्यकारी परिषद् इस प्रस्तावित विशेष एकक की परिषद् में स्थापना और उसके कार्यों के प्रश्न पर आगे विचार करने के लिए एक उप-समिति की नियुक्ति की। इस एकक की स्थापना होने तक परिषद् ने 1971-72 में परीक्षा सुधार कार्यक्रम द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर इस योजना को राज्यों में कार्यान्वित करने में मार्गदर्शन के लिए तदर्थ प्रबन्ध किया। परिषद् में प्रस्तावित एकक की स्थापना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को ढूंढ निकालने का कार्य और तरीके और वैज्ञानिक ढंग से किया जाएगा।

परिशिष्ट 11

परीक्षा सुधार

कई वर्षों से परिषद् देश की परीक्षा प्रणाली के सुधार में जुटी हुई है। परिषद् के परीक्षा सुधार कार्यक्रम के दो मुख्य लक्ष्य हैं :

(1) छात्रों के विकास को नापने के लिए परीक्षाओं को विधिमान्य विश्वसनीय उपकरण बनाना, और

(2) सारी अध्यापन-अवबोधन विधियों को सुधारने के लिए परीक्षाओं को एक शक्तिशाली उपकरण बनाना।

परिषद् द्वारा विकसित परीक्षा सुधार के विस्तृत कार्यक्रम में जो सन्निहित है वह है लिखित परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों, प्रश्न-पत्रों और अंक देने की विधियों में सुधार, व्यावहारिक परीक्षाओं में विषयसूची का निर्माण और मौखिक वर्णन का समावेश। यह कार्यक्रम निरीक्षण, इन्टर्व्यू और रेटिंग स्कूलों आदि में मूल्यांकन विधियों के विस्तार की सिफारिश करता है। इसका लक्ष्य परीक्षाओं के प्रबन्ध करने के तरीकों और श्रेणी प्रमाणीकरण और वर्गीकरण के लिए परीक्षण गणना के प्रयोग के लिए ही सुधार करना नहीं है वरन् अनुदेश उपायों, शैक्षणिक भविष्य-वाणी और निरीक्षण उपायों आदि से भी है। इसके परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, अनुदेश सामग्री और अनुदेश उपायों और अध्यापक प्रशिक्षण क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा गया है। परिषद् के परीक्षा सुधार कार्यक्रम के बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो निम्नलिखित है :

(1) पड़ोसी देशों, जैसे नेपाल, की इस कार्यक्रम में रुचि,

(2) विभिन्न राज्य स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं द्वारा एन० सी० ई० आर० टी० के विकसित कार्यक्रम के अनुसरण में स्वेच्छिक चेष्टाएँ,

(3) विभिन्न परीक्षा बोर्डों द्वारा परीक्षा में सुधार करना

(4) कुछ विश्वविद्यालयों और राज्य शिक्षा के तकनीकी बोर्डों द्वारा एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा विकसित सामग्री और तकनीकों का उपयोग, और

(5) इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित अनेक व्यक्तियों द्वारा शैक्षिक मूल्यांकन पर लेख तैयार करना ।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के पुनर्गठित रूप में भी परीक्षा सुधार के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था अभी विकसित करनी है। प्रतिवेदन वर्ष में पाठ्यपुस्तक विभाग में परीक्षा सुधार पर पहले से कार्य कर रहे अफसरों ने इस क्षेत्र का भी कुछ कार्य संभाला। इस वर्ष किए गए कार्यकलाप यह थे— विभिन्न परीक्षा बोर्डों द्वारा रचित 1969-70 की सेकेंड्री परीक्षाओं के नतीजों का विश्लेषण पूरा कर लिया, 1970-71 के नतीजों के विश्लेषण का कार्य आरम्भ कर दिया है, आगे सुधारने और मजबूत करने की दृष्टि से राजस्थान की आंतरिक निर्धारण परियोजना का मूल्यांकन, विश्वविद्यालयों को पहले से भेजे विशेष और आवश्यक पाठ्यक्रम के संशोधित रूप को विकसित करने की दृष्टि से विभिन्न विश्वविद्यालयों के बी० एड० के पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मूल्यांकन की विषय-सूची के विश्लेषण कार्य को जारी रखना, गोवा, दमन एवं दीव के शिक्षा विभाग भारतीय स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा परिषद्, राजस्थान, मैसूर और मध्य प्रदेश सेकेंड्री शिक्षा के राज्य बोर्डों के लिए मूल्यांकन कर्मशालाओं का आयोजन, और विभिन्न राज्यों में मूल्यांकन कार्यक्रमों में लगे अफसरों के लिए एक सेमिनार का आयोजन करना ।

परिशिष्ट 12

यूनेस्को रजत जयंती समारोह

प्रतिवेदन वर्ष यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारत राष्ट्रीय आयोग के सुझाव पर परिषद् और शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने यूनेस्को का पच्चीसवाँ वार्षिकोत्सव मनाया। इसके विशेष कार्यक्रम में यूनेस्को के भूतपूर्व उपमहानिदेशक और वर्तमान मद्रास इंस्टीच्यूट आफ डेव्लपमेंट स्टडीज के निदेशक, डा० मैलकाम एम० आदिशेषय्या का "यूनेस्को इन ट्वेन्टीफाइव इयर्स—ए रिटरास्पेक्ट एंड ए प्रास्पेक्ट" पर भाषण सम्मिलित है। भाषण को छपाकर उसकी प्रतियाँ विशिष्ट श्रोताओं को जिनमें यूनेस्को, यूनीसेफ, यू० एन० डी० पी०, डब्लू० एच० ओ०, एफ० ए० ओ० इत्यादि के दिल्ली स्थित अफसर, यू० एस० ए० आई० डी०, ब्रिटिश काउंसिल, केन्द्रीय शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय और एन० सी० ई० आर० टी० के अफसरों को बाँटी गईं। विशेष समारोह के दूसरे कार्यक्रम यह थे एन० सी० ई० आर० टी के निदेशक प्रो० एस० वी० सी० एय्या रचित "ए चिल्ड्रेन्स साइंस इनजैक्शन प्रोग्राम" पुस्तिका का मुद्रण, डा० आदिशेषय्या द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कैम्पस में लघु पाइप का लगाना, और एन० आई० ई० कैम्पस में स्कूल अध्यापकों और छात्रों के लाभ के लिए एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी में दूसरे आमन्त्रित लोगों के अतिरिक्त राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना के स्थानीय प्रत्याशियों को भी आमन्त्रित किया गया। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों और केन्द्रीय शिक्षा संस्थान में हुए समारोहों में सिम्पोजियम, वक्ताओं द्वारा भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद-विवाद, लेख प्रतियोगिता, यूनेस्को के अंशदान पर शैक्षिक फिल्मों का प्रदर्शन इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

परिशिष्ट 13

व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को अनुदान (1971-72)

देश में बहुत से व्यावसायिक संगठन हैं जो प्रत्यक्षतः अथवा परोक्ष रूप से स्कूली शिक्षा के लिए गुणकारी कार्य करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् गत कई वर्षों से ऐसे संगठनों को आर्थिक सहायता देने की परियोजना, केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ की गई स्वयंसेवी शैक्षिक संगठनों की सहायता की योजना के आधार पर चला रही है। विभिन्न व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को 1971-72 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों के नाम	स्वीकृत राशि (रुपये में)
1.	भारतीय अध्यापक-शिक्षक संघ, दिल्ली	10,000-00
2.	अखिल भारतीय विज्ञान अध्यापक संघ, लोधी स्टेट, दिल्ली	8,500-00
3.	अखिल भारतीय शैक्षिक संस्थाओं की फैड्रेशन, नई दिल्ली	3,000-00
4.	भारतीय स्कूल-पूर्व शिक्षा संघ, नई दिल्ली	4,500-00
5.	भारतीय गणित अध्यापक संघ, मद्रास	5,700-00
6.	विज्ञान शिक्षा विकास संघ, मद्रास	3,500-00
7.	भारतीय अभिभावक-अध्यापक राष्ट्रीय संघ, नई दिल्ली।	2,500-00
8.	बंग विज्ञान परिषद्, कलकत्ता	3,500-00
9.	बाल चित्र संस्थान, रवीन्द्र सरोवर, कलकत्ता	5,000-00
10.	भारतीय भूगोल अध्यापक संघ, मद्रास	4,000-00
	कुल जोड़ :	50,200-00

परिशिष्ट 14

अनुसंधान अध्ययन, अन्वेषण और सर्वेक्षण (1971-72)

प्रतिवेदन वर्ष में हस्तगत परियोजनाओं के संबंध में और प्रगति हुई थी और कुछ नए अध्ययन और सर्वेक्षण भी आरम्भ किए गए थे। इस वर्ष के दौरान पूरे हुए या आरम्भ किए गए अध्ययनों, अन्वेषणों और शैक्षिक सर्वेक्षणों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

(क) अध्ययन

(1) परीक्षण विकास

1·01 **सहकारी परीक्षण विकास परियोजना :** इस परियोजना का उद्देश्य दो मनोवैज्ञानिक उपकरणों को विकसित करना है—एक बुद्धि परीक्षण और दूसरा अभिरुचि। वर्ष 1971-72 में 7-16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए समांतर आकार के अनुक्रमी बुद्धि परीक्षण सामान्य आँकड़े एकत्रित करने के लिए बंगला, तमिल और मलयाली भाषाओं में छापे गए। अभिरुचि सूची का कनिष्ठ आकार स्कूल छात्रों और श्रेष्ठ आकार कालेज छात्रों के लिए हिन्दी, मराठी और कन्नड़ भाषाओं में छात्रों और दस चुने हुए व्यावसायिक दलों के प्रयोग के लिए छापे गए। इन दोनों उपकरणों से संबंधित प्रतिमानों और सांख्यिकीय विश्लेषणों को विकसित करने के कार्य में इस वर्ष प्रगति हुई है।

1·02 **विभेदक अभिक्षमता परीक्षण माला :** गत वर्ष पूर्व-परीक्षण पुस्तिकाएँ दो राज्यों में प्रयोग के लिए भेजी गई और दो मदों का विश्लेषण आँकड़ों के आधार पर किया गया। इन परीक्षणों का सम्पादन किया गया और प्रतिमान अध्ययन के लिए अंतिम स्वरूप बनाने की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार अनुदेशों में संशोधन किया गया। तीन उत्तर-पत्रों के ढाँचे तैयार किए गए और उनको छापा गया। नमूने के तौर पर हिन्दी-भाषी राज्यों के 240 स्कूलों को चुना गया। संबंधित राज्य अधिकारियों से राज्यों में परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया गया।

1·03 **देशनांक तथा करणी संबंधी नैदानिक परीक्षणों का विकास करना :** एन० आई० ई०-एच० ई० डब्लू० परियोजना "आल इण्डिया अचीवमेंट इन

मैथेमेटिक्स सर्वे" से पता चला है कि देशनांक तथा करणी विपय तुलनात्मक रूप से कठिन है। इसलिए ऐसा अनुभव किया गया कि बच्चों की इस विपय में कमजोरी का पता लगाने के लिए नैदानिक परीक्षणों को विकसित किया जाए। एक बार परीक्षण से किसी कमजोरी का पता लगते ही उस विपय पर और प्रभावपूर्ण अनुदेश सामग्री को विकसित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रतिवेदन वर्ष में परीक्षण मदों को लिखने का कार्य, इस क्षेत्र में प्रारम्भिक अध्ययन पूरा करने के बाद, हाथ में लिया गया। परीक्षण मदों का परीक्षण करके अंतिम परीक्षण स्वरूप तैयार किया जाएगा। यह अंतिम परीक्षण स्कूल अध्यापकों के सामान्य प्रयोग के लिए जारी किया जाएगा।

1·04 **कक्षा 1-7 के लिए उपलब्धि परीक्षण माला का मानकीकरण :** 1971-72 वर्ष में मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में कक्षा 1-7 के लिए उपलब्धि परीक्षण माला के मानकीकरण का कार्य प्रारम्भ हुआ।

1·05 **लेखा-संधारण और वाणिज्य तत्वों की निर्मित्ति और मानकीकरण :** भुवनेश्वर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय ने लेखा-संधारण और वाणिज्य तत्वों की निर्मिति और मानकीकरण का कार्य प्रारम्भ किया। परीक्षण के प्रारूप तैयार किए गए और पूर्वी क्षेत्र के नमूने के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उनका प्रयोग किया गया।

1.06 **भारत की दूसरी मानसिक मापक हस्तपुस्तिका :** भारत की पहली मानसिक हस्तपुस्तिका 1966 में प्रकाशित हुई थी। इसके अद्यतन का अनुभव करते हुए प्रतिवेदन वर्ष में इसके संशोधन की परियोजना प्रारम्भ की गई।

(2) मार्गदर्शन तथा परामर्श

2·10 **व्यवसाय अध्ययन :** इस परियोजना का उद्देश्य आठवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में व्यवसायों के शिक्षण की विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन तथा मूल्यांकन करना है। 1971-72 में कक्षा दस के विज्ञान और वाणिज्य स्रोतों पर प्रयोगात्मक कार्य किए गए। अध्ययन के लिए प्रत्येक स्रोत के तीन खण्ड लिए गए।

(3) शिशु विकास

3.01. **2½ से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतिमान परियोजना का विकास :** इस परियोजना का उद्देश्य 2½ से 5 वर्ष की आयु वर्ग के भारतीय बच्चों में विकास के मानक तैयार करना है। 1971-72 में निम्नलिखित रिपोर्टें तैयार की गई :

(1) स्कूल-पूर्व छात्रों का प्रेरक विकास; और

(2) विभिन्न वर्गीय तथा देशांतरीय ढंग से प्राप्त प्रतिमानों की तुलना ।

3·02. 5½ से 11 **वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतिमान परियोजना का विकास** : इस परियोजना का उद्देश्य 5½ से 11 वर्ष की आयु के भारतीय बच्चों की शिक्षा के प्रक्रम में सुधार करने के विचार से इस आयु-वर्ग के विकास को समझना है । इस अध्ययन का लक्ष्य घर तथा स्कूल में पर्यावरणगत प्रक्रमचरों के बीच संबंधों का अन्वेषण करना तथा स्कूली उपलब्धि संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक परिपक्वता पर इनके प्रभाव का अध्ययन करना है । इसके अलावा, उपलब्ध तथ्य सामग्री के आधार पर विकास के विभिन्न पहलुओं के लिए मानक भी तैयार किए जाएँगे । यह परियोजना बम्बई, केरल, उस्मानिया, बंगलौर और राँची विश्व-विद्यालयों के पाँच केन्द्रों और गांधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी, के एक केन्द्र के सहयोग से प्रारम्भ की गई है । दिल्ली केन्द्र के लिए बीज-अध्ययन की एक योजना बनाई गई है । प्रतिवेदन वर्ष में इस अध्ययन के लिए आवश्यक साधन विकसित करने का कार्य किया गया । विभिन्न केन्द्रों पर हो रहे मार्गदर्शी अध्ययन या तो समाप्त हो गए थे या समाप्ति पर थे ।

3·03 **स्कूल-पूर्व वर्गों में दो विधियों से शिक्षित संकल्पना निर्माण का अध्ययन** : इस अध्ययन का उद्देश्य निर्देशित अनुभवों के द्वारा तथा अन्य अनुभवों के संदर्भ में बोध प्रशिक्षण के द्वारा जो स्कूल-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम के भाग हैं संप्रत्यय निर्माण में तुलनात्मक प्रभावशीलता और विलगन में बोध प्रशिक्षण के वैयक्तिक सामाजिक समायोजन का पता लगाना है । 1971-72 में तथ्य सामग्री का विश्लेषण करके रिपोर्ट का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया ।

4. किशोरावस्था

4·01 **किशोरों के लिए व्यक्तिगत सूची का विकास** :—1971-72 में आगे अध्ययन के लिए 10 उप-मापक्रमों में 250 मदों से युक्त किशोरों के लिए व्यक्तिगत सूची का अंतिम रूप तैयार किया गया । इसकी अनुदेशन नियम-पुस्तिका भी तैयार की गई ।

4·02 **किशोरों की प्राधिकरण के प्रति अभिवृत्ति अध्ययन हेतु मापक्रम का विकास** :—प्रतिवेदन वर्ष में मदों के चुनाव का कार्य जारी रहा । ऐसी आशा की जाती है, कि मई 1972 तक स्थिति मापक्रम का अंतिम रूप सामर्थ और प्रतिमान अध्ययन के लिए तैयार हो जाने की संभावना है ।

4·03 **किशोरावस्था पर सहकारी अनुसंधान** :—किशोरावस्था पर प्रबन्धों की सूची दो विश्वविद्यालयों—जामिया मिल्लिया इस्लामिया और दिल्ली विश्व-विद्यालय द्वारा तैयार की गई और वैषयिक पुस्तक सूची के रूप में दिल्ली केन्द्र ने क्रमबद्ध किया । परिषद् द्वारा सहकारी अनुसंधान परियोजनाओं के कार्य करने के

ढाँचे के संबंध में फैसला लिए जाने तक इस परियोजना का आगे का कार्य स्थगित कर दिया गया है।

5. सामाजिक मनोविज्ञान

छात्रों के अध्ययन व्यवहार में सुधार के लिए सामाजिक पुनर्बलन तकनीक का प्रयोग :—इस परियोजना का उद्देश्य छात्रों के अध्ययन की आदतों के सुधार के लिए सामाजिक पुनर्बलन तकनीक का प्रयोग करना है। 1971-72 में अध्ययन समाप्त करके रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया गया। इस अध्ययन के नतीजों से पता चलता है कि अध्यापक इस तकनीक का प्रयोग करके छात्रों को कृत्यों के उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

6. कार्यक्रमित अधिगम

कार्यक्रम बद्ध अधिगम के सामूहिक गतिक्रम के विरुद्ध सापेक्ष प्रभावकारिता का एक अध्ययन :—इस परियोजना का उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक स्तर और कक्षा 7 के लिए सांख्यिकी में कार्यक्रमित इकाइयाँ विकसित करना है। इस प्रकार विकसित की गई सामग्री का प्रयोग अधिगम की विभिन्न अवस्थाओं में किया जाएगा जैसे व्यक्तिगत अधिगम, दल अधिगम जबकि दल का नियन्त्रण अध्यापक कर रहा हो, दल अधिगम जबकि दल छोटे आकार का हो और सदृश और विरुद्ध निपुणताओं पर आधारित हो और कार्यक्रमित सामग्री का प्रयोग अपने विचारानुसार करने में स्वतंत्र हों। सांख्यिकी सामग्री तीन इकाइयों में है :—

(1) तथ्य सामग्री की निश्चित अवधियों और वर्गीकरण की प्रस्तावना, (2) केन्द्रीय प्रवृत्ति के उपाय, और (3) विसर्जन के उपाय। इसमें से दो इकाइयाँ प्रतिवेदन वर्ष में प्रयोग के लिए तैयार की गई और तीसरी इकाई की प्रतिलिपियाँ तैयार की गईं। बीजगणित में पोलीनोमियल इकाई की प्रतिलिपियाँ भी तैयार की गईं। इस सामग्री का दिल्ली के विशेष स्कूलों में ऊपर लिखी हुई अवस्थाओं में परीक्षण करने और सापेक्ष प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए नतीजों का विश्लेषण करने का प्रस्ताव है।

7. प्रतिभा

प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रतिभा का अभिज्ञान :—"प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रतिभा का अभिज्ञान" पर एक अनुसंधान परियोजना 1964 में एन० आई० ई०-एच० ई० डब्लू० परियोजनाओं के अंतर्गत चालू की गई थी। मार्च 1967 में समाप्त हुए प्रथम चरण में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रतिभा के अभिज्ञान पर बहुत से परीक्षण विकसित किए गए। अप्रैल 1967 से मार्च 1971

तक द्वितीय चरण में विकसित प्रतिभा अभिज्ञान के परीक्षणों में संशोधन और प्रतिभा और आयु, लिंग, सामाजिक स्थिति, व्यक्तित्व और शहरी-देहाती चरों के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन हुआ है। ज्यादातर परीक्षणों का संशोधन समाप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त सर्जनात्मकता पर चार नए परीक्षण विकसित किए गए। 1971-72 में परीक्षण माला के सारे परीक्षणों को संशोधित करने का कार्य समाप्त कर लिया गया और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के स्कूलों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर प्रतिभा, आयु, लिंग, व्यक्तित्व और शहरी और देहाती चरों का विश्लेषण किया गया।

7·02 राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना के प्रत्याशियों और अप्रत्याशियों की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन :—इस अध्ययन का उद्देश्य राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना के प्रत्याशियों और अप्रत्याशियों की विशेषताओं की पहचान करना है। व्यक्तित्व के परिचयपूर्ण और अपरिचयपूर्ण पहलुओं को मापने के लिए परीक्षणों की माला दिल्ली के कालेजों में पढ़ रहे बी०एससी० और एम०एससी० प्रत्याशियों और अप्रत्याशियों को दी गई। परीक्षण के लिए यह उत्तर प्रदेश (लखनऊ और इलाहाबाद के कालेजों में पढ़ रहे), महाराष्ट्र (बम्बई और पूना के कालेजों में पढ़ रहे), मध्य प्रदेश (जबलपुर के कालेजों में पढ़ रहे), तमिलनाडु (मद्रास और मदुराय के कालेजों में पढ़ रहे) और मैसूर (बंगलोर के कालेजों में पढ़ रहे) के अप्रत्याशियों को भी दिए गए।

8. शिक्षा का इतिहास

8·01 मातृभाषा और शिक्षा में अवसरों की सदृश्यता :—"मातृभाषा और शिक्षा में अवसरों की सदृश्यता पर एक अनुसंधान परियोजना अप्रैल 1971 में प्रारम्भ की गई। इसका कार्य दिसम्बर 1971 में समाप्त हो गया। इस अध्ययन की रिपोर्ट को प्रेस में छपने भेज दिया गया है। इस अध्ययन में शिक्षा के विदेशी माध्यम की व्यवस्था और व्यवहार में अवसरों की सदृश्यता के आपसी संबंधों की ऐतिहासिक दृष्टि से जाँच की गई है। इस अध्ययन की मुख्य प्राप्ति यह है कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम रखने से, मुख्यतः विश्वविद्यालय स्तर पर, भारत में शैक्षिक समता के व्यवहार को काफी क्षति पहुँची है। इसलिए इस अध्ययन ने यह सुझाव दिया है कि मातृभाषा को ही प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाए।

8·02 **भारतीय स्कूलों में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण और स्वाधीनता के पश्चात् उसका विकास** :—

स्कूलों की पाठ्यचर्या में सामाजिक अध्ययन की विभिन्न शाखाओं के पाठ्य-क्रम पर बदलती हुई सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव का मूल्यांकन

करना, इन विषयों की पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करना, इस बात पर विचार करना कि क्या इन विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापकों के पास उचित साधन हैं और क्या उन्हें इनकी उपेक्षाओं की जानकारी देने के लिए कदम उठाए गए हैं और इस बात की जाँच करना कि क्या शैक्षिक प्रशासकों को अध्ययन की इस शाखा में परिवर्तन लाने की हाल की माँग के बारे में पता है। इन सब अध्ययनों को प्रतिवेदन वर्ष में चालू रखा गया। 1970-71 में दिल्ली के स्कूलों से एकत्र तथ्य सामग्री का विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन को भारत के सभी राज्यों में नियत समय पर करने का प्रस्ताव है। तथ्य सामग्री को एकत्र करने के लिए राज्यों को प्रश्नावली भेज दी गई।

9. तुलनात्मक शिक्षा

9·01 माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश और विषयों के वरण पर दबाव का एक तुलनात्मक अध्ययन :—

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं :—

(1) विभिन्न देशों में माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश पर तथा स्कूल के विषयों के वरण पर डाले जाने वाले दबावों की प्रकृति का विश्लेषण करना, और

(2) व्यष्टि सफलता तथा वरण की स्वतंत्रता के परिणाम का पता लगाना। प्रतिवेदन वर्ष में देश के 12 केन्द्रों पर किए गए कार्य के आधार पर तैयार प्रबंधों का सम्पादन किया गया। अतिरिक्त सामग्री का इन लेखों में समावेश किया गया। इस अध्ययन की रिपोर्ट प्रकाशन एकक को छपने के लिए भेज दी गई। इसके अतिरिक्त नेपाल, लंका और फिलिपाइन्स से तथ्य सामग्री एकत्रित करने का कार्य प्रगति की ओर अग्रसर है।

9·02 कुछ चुने हुए देशों में भाषा संबंधी नीतियों को प्रभावित करने वाले कारकों का तुलनात्मक अध्ययन

इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(1) उन विशेष साधनों का जो बहुभाषीय देशों में भाषा की नीति निर्धारित करने और उसके कार्यान्वय में निर्णायक भाग लेते हैं उनका पता लगाना और विश्लेषण करना, और

(2) विभिन्न शैक्षिक प्रणालियों के एक ही प्रकार के परिवर्तनशील सेटों के आधार पर उनकी भाषा नीतियों के संदर्भ में एक तुलनात्मक अध्ययन करना।

1971-72 में बहुभाषीय देशों में भाषा नीति को प्रभावित करने वाले कारणों का पता लगाने के लिए इस अध्ययन द्वारा एकत्र सामग्री का विश्लेषण किया गया। प्रस्तावना अध्याय के पहले प्रारूप का तैयार किया गया।

10. पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन

10·01 मानक हिन्दी में भाषागत विश्लेषण और ध्वन्यात्मक परिवर्तनों का विवरण

गत वर्ष ऐसे सूचकों से जो हिन्दी की एक बोली घर में मातृभाषा के रूप में और स्तरीय हिन्दी घर के बाहर समाज में समान्य प्रथम भाषा के रूप में बोलते हैं, तथ्य सामग्री वाक-नमूनों के रूप में सभी हिन्दी भाषी राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के उन्नीस बोली क्षेत्रों से एकत्र की गई। तथ्य सामग्री के ध्वन्यात्मक अनुकरण और विश्लेषण के बाद हिन्दी के विभिन्न बोली क्षेत्रों में उपलब्ध ध्वन्यात्मक परिवर्तनों को पहचाना गया और उनका अध्ययन किया गया। परन्तु बोली जाने वाली स्तरीय हिन्दी के प्रतिमानों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों के एक दल की बैठक में यह फैसला किया गया कि ऐसे सूचकों को पंजीकृत किया जाए जो हिन्दी की बोली नहीं बोलते हैं और स्तरीय हिन्दी, हिन्दुस्तानी या उर्दू का मातृभाषा के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए 1971-72 में तथ्य सामग्री एकत्र करने के लिए उपकरण विकसित किए गए और इलाहाबाद, आगरा और लखनऊ क्षेत्रों के स्तरीय हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू भाषियों से आवश्यक तथ्य सामग्री एकत्रित की गई, पंजीकृत की गई और उनका विश्लेषण किया गया। इन अध्ययनों की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

क्योंकि हिन्दी के उन्नीस बोली क्षेत्रों से पहले एकत्रित की गई तथ्य सामग्री में महत्व निर्दिष्ट नहीं किया गया था और 57,000 मदों को पंजीकृत किया गया था। उन सबका फिर से अध्ययन किया गया और सब मदों में महत्व को विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया।

10·02 भाषा संबंधी मूलभूत अनुसंधान

भाषा संबंधी मूलभूत अनुसंधान पर दूसरा राष्ट्रीय सेमिनार एक मार्च 1972 को संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, में आयोजित किया गया। दर्शनशास्त्र, व्याकरण और काव्यशास्त्र इत्यादि विभिन्न शाखाओं से संबंधित भारतीय विचार-धारा के लगभग 25 विद्वानों ने इस गोष्ठी में भाग लिया। गोष्ठी में प्रस्तुत प्रबन्धों का सम्पादन किया जा रहा है जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए जाएँगे।

10·03 हिन्दी लिखने में प्रयोग की जाने वाली देवनागरी हस्तलिपि का वर्णात्मक विश्लेषण

इस परियोजना को देवनागरी हस्तलिपि प्रयोग करने वालों की हिन्दी लेखन प्रणाली का अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया था। हिन्दी लेखन प्रणाली के

परिच्छेद, वाक्य, अनुच्छेद, वाक्यांश शब्द अक्षर स्तरों और ध्वनि वर्णनात्मक पत्र-व्यवहार का अध्ययन किया गया। इसके अतिरिक्त हिन्दी अक्षरों का रेखाचित्रों में विश्लेपण किया गया और उनके वितरण का भी उल्लेख किया गया। हिन्दी अक्षरों की संरचना, स्थान और पुंज के साथ-साथ स्थानिक हिन्दी भाषियों की हस्तलिपि पर एकत्रित सामग्री के आधार पर अक्षरों के निर्माण के क्रम और उसकी संख्या का भी अध्ययन किया गया। इस अध्ययन की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

10·04 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल स्तरों में मातृभाषा (हिन्दी) में बच्चों के प्रस्तुत स्तरों का अध्ययन : इस परियोजना का प्रारम्भिक कार्य 1971-72 में प्रारम्भ कर दिया गया था। यह फैसला किया गया कि सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग और शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा आधार विभाग अंतर-विभागीय परियोजना के रूप में कार्य करेंगे।

10·05 स्कूल बच्चों के लिए हिन्दी में शैक्षिक शब्दावली का विकास : यह परियोजना सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग और शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा आधार विभाग ने मिलकर प्रारम्भ की। बोली जाने वाली शब्दावली के संबंध में तथ्य सामग्री प्राथमिक स्कूल के बच्चों से एकत्रित की गई। तथ्य सामग्री के विश्लेषण का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है।

10·06 विभिन्न राज्यों के स्कूली पाठ्यक्रम में विश्व इतिहास के स्थान का एक अध्ययन : 1971-72 में विभिन्न राज्यों के स्कूल पाठ्यक्रम में विश्व इतिहास के स्थान के अध्ययन का कार्य शुरू कर दिया गया। पाठ्यक्रम के विश्लेपण में पाठ्यक्रम में अनुसरण की गई विषय की योजना, प्रति सप्ताह दिया जाने वाला समय, व्यावहारिक कार्य के लिए सुझाव, शिक्षण के तरीके और मूल्यांकन सम्मिलित है। पाठ्यक्रम के विश्लेपण पर आधारित विश्व इतिहास का स्थिति पर एक पुस्तिका जल्दी ही प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।

10·07 विभिन्न राज्यों के स्कूली पाठ्यक्रमों में नागरिकशास्त्र के स्थान का एक अध्ययन : प्रतिवेदन वर्ष में 14 राज्यों के पाठ्यक्रम में नागरिकशास्त्र की स्थिति का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के आधार पर उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए नागरिकशास्त्र का नया पाठ्यक्रम विकसित किया जाएगा।

10·08 इस वर्ष भुवनेश्वर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में द्विभाषीय शिक्षण और भारतीय बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के संरचनात्मक पहुंच का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। स्टाफ के अभाव के कारण इस अध्ययन में कोई प्रगति न हो सकी। 1971-72 में इस अध्ययन को चालू रखने का प्रस्ताव है।

10.09 अहिन्दी भाषियों को भाषा प्रयोगशाला तकनीकों से हिन्दी शिक्षण के सामर्थ्य का पता लगाने के लिए एक अध्ययन : अहिन्दी भाषियों का भाषा प्रयोगशाला तकनीकों से हिन्दी शिक्षण के सामर्थ्य का पता लगाने के लिए 1971-72 में परिषद् की भाषा प्रयोगशाला में एक प्रयोगात्मक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन को दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से जारी रखा गया।

10.10 सामाजिक अध्ययन शिक्षण के कुछ विशेष उद्देश्य और उनको प्राप्त करने के उपायों से संबंधित एक विश्लेषणात्मक अध्ययन : यह अध्ययन मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में पूरा किया गया और इसकी रिपोर्ट इस वर्ष निकाली गई।

10.11 राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा संचालित हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के परिणामों का विश्लेषण : प्रतिवेदन वर्ष में राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा 1969-70 में संचालित हाई स्कूल-उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के परिणामों के विश्लेषण का कार्य समाप्त कर लिया गया और 1970-71 की परीक्षाओं के परिणामों के विश्लेषण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया।

10.12 आंतरिक आकलन कार्यक्रम के मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन : राजस्थान में आंतरिक आकलन कार्यक्रम के मूल्यांकन का कार्य इस वर्ष के दौरान इसको सुधारने और सुदृढ़ करने के लिए चालू रहा।

10.13 शैक्षिक मूल्यांकन विषय-वस्तु के संबंध में बी० एड० पाठ्यक्रम का अध्ययन : 1971-72 में विभिन्न विश्वविद्यालयों के बी० एड० पाठ्यक्रम का शैक्षिक मूल्यांकन की विषय-वस्तु के संबंध में विश्लेषण का कार्य विभिन्न विश्वविद्यालयों को पहले भेजे गए विषय का अनिवार्य और विशेष प्रकार का नया संशोधित संस्करण विकसित करने की दृष्टि से चालू रहा।

11. पूर्व प्राथमिक शिक्षा

पूर्व-प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए कार्यकलापों की तुलना में आचरण परिणाम का अध्ययन :

स्कूल-पूर्व शिक्षा बहुधा निजी हाथों में नियन्त्रित है और इसलिए विभिन्न संस्थाएँ अपने स्कूलों के कार्यक्रम/कार्यकलाप तैयार करने में अपनी रीतियों का अनुसरण करते हैं। ऐसे कार्यकलापों को जानने के लिए और उनमें से अच्छे कार्यकलापों को देश के दूसरे स्कूलों तक पहुँचाने के लिए परिषद् ने यह परियोजना आरम्भ की थी। प्रतिवेदन वर्ष में जाँच के लिए उपकरण तैयार किए गए और उनको अंतिम रूप दिया गया। 60 अध्यापकों से भी जवाब प्राप्त हुए हैं।

12. प्राथमिक शिक्षा

12·01 प्राथमिक स्तर पर बरबादी तथा गतिरोध को कम करने के लिए श्रेणीकृत स्कूल प्रणाली के संबंध में प्रायोगिक परियोजना :

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के लोनी ब्लाक में "अश्रेणीकृत स्कूल प्रणाली" के संबंध में परिषद् ने एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बरबादी तथा गतिरोध को कम करने में इसके प्रभाव का अध्ययन करना है। यह परियोजना 20 प्राथमिक स्कूलों में लागू की गई है जिनमें से दस स्कूल प्रयोगिक स्कूल हैं और दस नियन्त्रित स्कूल हैं। प्रतिवेदन वर्ष में गत दस वर्षों में बरबादी और गतिरोध की घटनाओं के आँकड़े एकत्रित करने का कार्य चालू रखा गया और 6 स्कूल से आँकड़े एकत्र किए गए। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्कूलों के हैडमास्टरों तथा सहायक अध्यापकों को अश्रेणीकृत स्कूल प्रणाली में अन्तर्निहित मूलभूत विचारों का स्थिति ज्ञान कराने के पश्चात्, यह परियोजन पहली सितम्बर 1971 को चालू की गई थी। दस स्कूलों के प्रयोगिक दल के कक्षा I को, नए बच्चों के आने की संभावना के साथ, अश्रेणीकृत ढाँचे में रखा गया।

12·02 प्राथमिक स्कूलों में विभिन्न स्कूली विषयों में छात्रों की उपलब्धियों पर पठन के प्रभाव का अध्ययन :

इस अध्ययन के पहले चरण में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए वैज्ञानिक आधार पर विकसित शब्दावली की सूची तैयार करना है। 1971-72 के दौरान पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग, पाठ्यपुस्तक विभाग, सामाजिक अध्ययन और मानविकी विभाग और शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा-आधार विभाग के अंतरविभागीय प्रयत्नों से शब्दावली एकत्रित करने के लिए पृष्ठभूमि सामग्री और उपकरण तैयार किए गए। राज्य शिक्षा संस्थानों को शब्दावली एकत्र करने का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार एकत्रित शब्दावली का पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक विभाग में विश्लेषण किया गया।

12·03 प्राथमिक स्कूलों में बहुकक्षीय शिक्षण :

1971-72 के दौरान हरियाणा राज्य के गुड़गाँव के चुने प्राथमिक स्कूलों में बहुकक्षीय शिक्षण तकनीकों और साहित्य को विकसित करने के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना आरम्भ की गई। हरियाणा के राज्य शिक्षा संस्थान और चुने अध्यापकों की सहायता से इस परियोजना के ढाँचे को अंतिम रूप दिया गया। अध्यापकों को बहुकक्षीय शिक्षण धारण और शिक्षण इकाइयों की तैयारी के संबंध में अनुस्थापन दिया गया। प्राथमिक स्तर पर विभिन्न स्कूल विषयों में शिक्षण इकाइयाँ विकसित की गईं। यह कार्य आगामी वर्षों में चालू रखने का प्रस्ताव है।

13. जनजातीय शिक्षा

13·01 प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों में जनजातीय क्षेत्रों में बरबादी तथा गतिरोध

इस अध्ययन को प्रारम्भ करने का उद्देश्य प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों में जनजातीय क्षेत्रों में बरबादी तथा गतिरोध को कम करने के उपायों का पता लगाना है। इस संबंध में क्रिया—कार्यक्रम के प्रारूप को तैयार करने का कार्य हाथ में लिया गया।

13.02 जनजातीय युवकों की महत्वाकांक्षाओं तथा लक्ष्यों का अध्ययन

महत्वाकांक्षाओं तथा लक्ष्यों की पृष्ठभूमि में शिक्षा और आधुनिकीरण के कारण उत्पन्न जनजातीय युवकों की समस्याओं का पता लगाना इस अध्ययन का उद्देश्य है। यह परियोजना पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक विभाग का जनजातीय शिक्षा एकक और शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा आधार विभाग दोनों मिल कर चला रहे हैं। गत वर्ष इस अध्ययन की अनुसंधान संबंधी तैयार की गई रूपरेखा को 1971-72 में संशोधित किया गया।

13.03 जनजातीय छात्रों पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन

इस अध्ययन का उद्देश्य पठन क्षमता, निष्पादन, चिन्ता और एकीकरण के विचार के संदर्भ में जनजातीय छात्रों पर शिक्षा के प्रभाव का पता लगाना है। इस वर्ष के दौरान इस अध्ययन की रूपरेखा तैयार की गई।

13.04 जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा तथा सामाजिक आर्थिक गतिशीलता का अध्ययन

इस अध्ययन का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में पेशों के ढंग में तबदीली, अजनजातीयता, सांस्कृतिक तबदीली और सामाजिक तथा भौगोलिक परिवर्तनशीलता पर शिक्षा के योगदान का पता लगाना है। इस अध्ययन की रूपरेखा इस वर्ष तैयार की गई थी।

13.05 जनजातीय उपभाषाओं का जनजातीय छात्रों की शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन

इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या जनजातीय उपभाषाओं की क्षेत्रीय लिपि में तैयार पाठ्यपुस्तकें उनमें बरबादी और गतिहीनता को कम कर सकती हैं और उनमें पढ़ने के प्रति शौक पैदा कर सकती हैं और अध्ययन की ओर आकर्षित कर सकती हैं। क्योंकि जनजातीय उपभाषाओं में पाठ्यपुस्तकें विभिन्न राज्यों में लगानी थीं इसलिए संबंधित राज्य सरकारों की मंजूरी भी लेनी थी। बिहार और पश्चिम बंगाल की मंजूरी इस वर्ष के दौरान प्राप्त हो गई और उड़ीसा सरकार की मंजूरी प्रतीक्षित थी। इन तीन राज्यों में पाठ्यपुस्तकें परियोजना के आधार पर लगाने का प्रस्ताव है।

14. अध्यापक शिक्षा

14.01 शिक्षा कालेजों में अनुसंधान का संवर्धन

पूर्वी क्षेत्र के अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए अनुसंधान परियोजनाओं की योजना पर चौथा सेमिनार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर में 7 से 16 अक्तूबर 1971 तक आयोजित हुआ। सेमिनार में भाग लेने पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम राज्यों से अध्यापक प्रशिक्षक आए। हर भागीदार की अनुसंधान परियोजना बनाने में सहायता की गई। शिक्षा के विकास क्षेत्रों और स्कूल शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा की समस्याओं पर भागीदारों ने अनुसंधान रूपरेखाएँ तैयार कीं।

14.02 प्रशिक्षण कालेजों के श्रेणीकरण के लिए उपस्कर का विकास

प्रतिवेदन वर्ष में निम्नलिखित क्षेत्रों के अंतर्गत मदें एकत्रित करने के सूचना प्रारूप और आवश्यक पहलुओं से संबंधित सिद्धांत तैयार करने का कार्य किया गया।

1. भौतिक साधन
2. मनुष्य-शक्ति साधन
3. अनुदेशीय कार्यक्रम, और
4. अलंकृत कार्यक्रम।

14.03 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में अभ्यास-अध्यापन के मूल्यांकन में सुधार

बी० एड० पाठ्यक्रम और प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संबंध में प्रश्न-पत्र, पाठ्यक्रम और अन्य संबंधित साहित्य सम्पूर्ण भारत से एकत्रित किया गया। सभी विश्वविद्यालयों और अध्यापक प्रशिक्षण की माध्यमिक संस्थाओं की परीक्षण संस्थाओं में से 16 नमूने के तौर पर चुनी गई। उनके उद्देश्यों के हिसाब से उनके पाठ्यक्रमों का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट का प्रारूप "दि आबजैक्टिव्ज आफ द सिलैबी" शीर्षक से तैयार किया गया।

14.04 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर में अपनाई गई दाखिले की प्रक्रिया का अध्ययन

पिछले क्षेत्रों के दलों का अनुसरण-अध्ययन कालेज में अपनाई गई दाखिले की प्रक्रिया में सुधार करने के विचार से क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर में किया गया। अब चूंकि छात्रवृत्तियाँ केवल 50 प्रतिशत नामांकित विद्यार्थियों को ही दी जाती हैं इसीलिए विद्यार्थियों के चयन की आवश्यक प्रक्रियाओं को विकसित करने की जरूरत पड़ी। ऐसी आशा की जाती है कि यह अध्ययन इस दिशा में सहायता करेगा।

14·05 4-वर्षीय तथा 1-वर्षीय बी० एड० पाठ्यक्रमों के स्नातकों का अनुसरण अध्ययन :

इस वर्ष के दौरान क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर से 4-वर्षीय और 1-वर्षीय बी० एड० पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होने वाले स्नातकों का अनुसरण-अध्ययन प्रारम्भ किया गया।

15. शैक्षिक प्रौद्योगिकी

शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर लगभग 300 पुस्तकें, रिपोर्टें और दूसरे मुख्य संलेख अध्यापकों और अध्यापक शिक्षा के लाभ लिए 1971-72 के दौरान टीकाकृत किए गए।

16. पाठ्यपुस्तक की तैयारी का मूल्यांकन

16·01 राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों की स्थिति का अध्ययन :

इस अध्ययन का कार्य गत वर्ष आरंभ किया गया था। प्रतिवेतन वर्ष में यह अध्ययन समाप्त कर लिया गया।

16·02 विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यक भाषा वर्गों में पाठ्यपुस्तकों की स्थिति का अध्ययन :

स्कूली पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीय बोर्ड की दूसरी बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर यह अध्ययन गत वर्ष आरंभ किया गया था। 1971-72 के दौरान कुछ राज्यों का अध्ययन पूरा कर लिया गया।

16·03 इतिहास की विषय-वस्तु के चयन तथा प्रस्तुतीकरण का अध्ययन :

इस अध्ययन का कार्य जो गत वर्ष आरंभ किया गया था 1971-72 में भी चालू रखा गया।

16·04 स्कूल के विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों की तैयारी तथा मूल्यांकन के सिद्धांत तथा प्रक्रियाएँ :

यह अनुसंधान विकास परियोजना है। इस में पाठ्यपुस्तकें तैयार करने तथा उनके मूल्यांकन करने के मूलभूत सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं को विकसित करने का कार्य शामिल है। ऐसे अध्ययन के नतीजे विषय विशेषज्ञों, अध्यापन-विज्ञान विशेषज्ञों, अध्यापकों इत्यादि के समक्ष रखे जाते हैं। ऐसे दल द्वारा नतीजों की विधिमान्यता के पश्चात् उनको व्यापक टिप्पणियों के लिए परिचालित किया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न उद्देश्यों जैसे सुधार, चयन, टिप्पणियों आदि से पुस्तकें और पाठ्यपुस्तकें मूल्यांकन करने के लिए उपकरणों के विकास का कार्य आरंभ किया जाता है। इसके बाद इस सारी सामग्री से हस्तपुस्तिका तैयार करने का कार्य किया

जाता है। हस्तपुस्तिका पर विशेषज्ञों के एक दल द्वारा विचार-विमर्श होता है, समीक्षा होती है और उसको अंतिम रूप देकर मुद्रित किया जाता है। इसको छापने से पहले एक एक प्रयोगात्मक संस्करण तैयार किया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत सारे स्कूल विषयों को चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव है। 1969-70 और 1970-71 के दौरान आठ विषयों का कार्य समाप्त किया जा चुका था। 1971-72 में इतिहास, भूगोल, जीव-विज्ञान और गणित की हस्तपुस्तिकाओं के अंतिम संस्करण प्रेस को छपने के लिए भेज दिए गए। प्रतिवेदन वर्ष में तीन और विषयों—द्वितीय भाषा, सामान्य विज्ञान और नागरिकशास्त्र पर कार्य किया गया और इसी प्रकार का कार्य अर्थशास्त्र और रसायन-विज्ञान के विषयों पर आरंभ किया गया।

17. अन्य अध्ययन

17·01 **अध्यापकों के सामाजिक स्तर का अध्ययन :**

यू० जी० सी० सहायता प्राप्त अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत अध्यापकों के सामाजिक स्तर का अध्ययन 1971-72 में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर में महाविद्यालय के एक स्टाफ सदस्य ने पूरा कर लिया।

17·02 **मैकाले के हेरारकीकल सिन्ड्रोम विश्लेषण द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुसंधानकारी सामर्थ्य का वर्गीकरण :**

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर में यह अध्ययन समाप्त कर लिया गया और इस वर्ष के दौरान इसकी रिपोर्ट निकाली गई।

17·03 **भाषा अधिगम भार, बुद्धि और शैक्षणिक प्राप्तियाँ :**

यह अध्ययन क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर में पूरा किया गया और इस वर्ष के दौरान इसकी रिपोर्ट निकाली गई।

17·04 **छात्रों की अमौखिक बुद्धिमत्ता से संबंधित सामाजिक-आर्थिक वातावरण का अध्ययन**

यह अध्ययन क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर में पूरा किया गया और इस वर्ष के दौरान इसकी रिपोर्ट निकाली गई।

(ख) शैक्षणिक सर्वेक्षण

1. भारत में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का नमूना सर्वेक्षण

1971-72 में निम्नलिखित स्थितियों पर सर्वेक्षण पूरा किया गया और उनकी रिपोर्ट मिम्योग्राफ की गई :

1. भारत के माध्यमिक स्कूल (नमूने में शामिल किए गए स्कूलों के संबंध में सामान्य सूचनाएँ)
2. माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक

3. अध्यापकों का अध्यापन व्यवसाय के प्रति भाव
4. अध्यापकों की व्यावसायिक समस्याएँ
5. अध्यापक और राष्ट्रीय एकीकरण
6. हैडमास्टरों की दृष्टि में अध्यापक

उपरोक्त सर्वेक्षण से विकसित 1500 अध्यापकों से संबंधित अंतरस्कूल कार्य-कलापों के अध्ययन का कार्य समाप्ति पर था।

2. माध्यमिक स्कूलों/इंटरमीडियट कालेजों में छात्रों की शक्षणिक प्रगति के लिए उपलब्ध सुविधाओं का नमूना सर्वेक्षण

इस सर्वेक्षण का उद्देश्य पुस्तकालय तथा वाचनालय, प्रयोगशालाओं, कर्मशालाओं, श्रव्य-दृश्य साधनों, विषय-क्लबों तथा संस्थाओं, मार्गदर्शन सेवाओं, दोपहर के भोजन, स्कूल की स्वास्थ्य सेवा आदि के लिए सुविधाओं जैसे पहलुओं के संबंध में सूचना एकत्र करना है। 1970-71 में यह नमूना-सर्वेक्षण देश के 3 प्रतिशत हाई और हायर सेकेंड्री स्कूलों और इंटरमीडियट कालेजों में किया गया। प्रतिवेदन वर्ष में यह सर्वेक्षण देश के दूसरे 3 प्रतिशत नमूने स्कूलों में किया गया। तीन प्रतिशत और नमूने स्कूलों से तथ्य सामग्री एकत्रित करने का कार्य पूरा किया गया और 1970-71 में एकत्र की गई तथ्य सामग्री का कार्य इस वर्ष के दौरान जारी रहा।

3. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पब्लिक परीक्षाओं में अनाचारों का अध्ययन

इस अध्ययन में विभिन्न स्तरों के विभिन्न प्रकार के अनाचारों का अध्ययन, समस्या हल करने के उपकरण, समस्या हल करने के बहुत से शैक्षणिक और प्रशासकीय उपाए, विभिन्न प्रकार के अनाचारों के लिए दिए जाने वाले दंड और इन समस्याओं को हल करने के लिए अधिकारियों के विचार शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा के सभी बोर्डों द्वारा 1969,1970 और 1971 में की जाने वाली नियमित और पूरक परीक्षाओं में ज्ञात किए गए अनाचारों का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन की रिपोर्ट के मई 1972 तक तैयार हो जाने की संभावना है।

4. तीसरा अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण

तीसरे अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण का प्रारम्भिक कार्य 1971—72 में शुरू कर दिया गया।

5. भारत में शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन पर उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण

विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में शैक्षणिक और व्यावसायिक

मार्गदर्शन की उपलब्ध सुविधाओं के निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया गया :

(1) पूरे समय के लिए परामर्शदाताओं, अध्यापक परामर्शदाताओं और जीविका विशेषज्ञों को नियुक्त करने वाली संस्थाओं की संख्या ।

(2) इन संस्थाओं में शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के चालू कार्यक्रम ।

(3) विभिन्न राज्यों में उपलब्ध प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की संख्या ।

(4) शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के राज्य ब्यूरो जैसी प्रत्येक राज्य की मुख्य एजेंसी में उपलब्ध श्रमिकों का स्तर, और

(5) प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्रों की चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में शैक्षणिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए वित्तीय परिव्यय ।

6. अभिभावक-अध्यापक संघों का सर्वेक्षण

दिल्ली में अभिभावक-संघों का एक सर्वेक्षण 1971-72 में शुरू किया गया । तैयार की गई इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में अभिभावक-अध्यापक संघों के विकास, इसकी कार्यकारी समितियों के गठन, सदस्यों से लिया जाने वाला शुल्क, संघों द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम इत्यादि के संबंध में विवरण दिया गया है । अभिभावक-अध्यापक संघों द्वारा ली जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में इस रिपोर्ट में बहुत से लाभदायक सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट की एक परिशिष्ट में पी० टी० ए० के एक आदर्श संविधान का सुझाव भी दिया गया है ।

7. माध्यमिक अध्यापक शिक्षा का तीसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण

सर्वेक्षण के लिए एक प्रश्नावली छापी गई और उसे देश के सभी शिक्षा कालेजों को भेजा गया । 35 प्रतिशत शिक्षा कालेजों ने प्रश्नावली भर कर लौटा दी है । जिन कालेजों ने जवाब नहीं दिया है उनको सूचना जल्दी भेजने के लिए याद दिला दिया गया ।

8. प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीय सर्वेक्षण

इस सर्वेक्षण के लिए एक प्रश्नावली छापी गई और उसे राज्यों में राज्य शिक्षा संस्थानों द्वारा और संघ क्षेत्रों में शिक्षा निदेशकों द्वारा देश की सभी प्रारम्भिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को भेज दिया गया है। राज्य शिक्षा संस्थानों ने तथ्य सामग्री एकत्रित की है जिसका विश्लेषण राज्यानुसार रिपोर्टें तैयार करने के लिए संस्थान के स्टाफ द्वारा किया जाएगा । संघ क्षेत्रों द्वारा प्रारम्भिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त तथ्य सामग्री का विश्लेषण परिषद् में किया जाएगा ।

9. माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों में श्रव्य-दृश्य उपकरण तथा सामग्री की उपलभ्यता, उपयोगिता और आवश्यकता के बारे में सर्वेक्षण

1971-72 वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों के माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों में श्रव्य-दृश्य उपकरण तथा सामग्री की उपलभ्यता, उपयोगिता और आवश्यकता के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के लिए छापी गई प्रश्नावली देश के सभी माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों को भेजी गई। इनसे उत्तर प्राप्त हो रहे हैं।

10. राज्य स्तर पर श्रव्य-दृश्य शिक्षा के विकास स्तर का सर्वेक्षण

1971-72 में राज्य स्तर पर श्रव्य-दृश्य शिक्षा के विकास के स्तर पर एक सर्वेक्षण किया गया। विभिन्न राज्यों से तथ्य सामग्री एकत्र की गई। तथ्य सामग्री के विश्लेषण का कार्य चालू है।

11. भारत में पूर्व स्कूलों का सर्वेक्षण

इस परियोजना के संबंध में विकसित प्रश्नावली का कुछ स्कूलों में परीक्षण किया गया और इस परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर उस प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया गया। पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग तथा आधार सामग्री प्रक्रिया तथा शैक्षिक सर्वेक्षण एकक दोनों मिलकर यह सर्वेक्षण कर रहे हैं।

12. बिहार राज्य में वाणिज्य शिक्षा की स्थिति पर सर्वेक्षण

सर्वेक्षण के लिए एक प्रश्नावली बिहार राज्य के सारे माध्यमिक स्कूलों को भेजी गई। कुछ स्कूलों से उत्तर प्राप्त हो गए हैं और उनकी जाँच की जा रही है।

(ग) प्रयोगात्मक परियोजनाएँ

प्रतिवेदन वर्ष में माध्यमिक स्कूलों से प्राप्त 359 परियोजना प्रस्तावों में से 255 मंजूर किए गए और उनको 86,000 रु० के अनुदान की स्वीकृति की गई। इसके अतिरिक्त इस योजना का कार्य-क्षेत्र बढ़ाकर इसमें प्राथमिक स्कूलों तथा जूनियर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को शामिल कर लिया गया। विभिन्न राज्यों के प्राथमिक स्कूलों तथा जूनियर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं से इस वर्ष प्राप्त 200 परियोजना प्रस्तावों में से 100 को कुल मिलाकर 10,000 रुपए का अनुदान मंजूर किया गया। प्रयोगात्मक परियोजनाओं का प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों और जूनियर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में मार्गदर्शन करने वाले साधन-अधिकारियों के लिए 1971-72 में अनुस्थापना कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। माध्यमिक स्कूलों में प्रयोगात्मक परियोजनाओं के योजना कार्य को विकसित करने के लिए 1969-70 में नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट परिषद् की कार्यक्रम सलाहकार समिति को पेश कर दी है।

परिशिष्ट 15

अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायतानुदान
(जी० ए० आर० पी०)
1971-72

इस योजना के अधीन, 1971-72 में परिषद् द्वारा 3 नई और 11 चालू परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी गई। जिन संस्थाओं को अनुदान दिए गए उनके नाम और उनकी परियोजनाओं के शीर्षक अनुबंध में दिए गए हैं ।

अनुबंध

शिक्षा में अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायतानुदान योजना के अंतर्गत 1971-72 में दिए गए अनुदान की विवरणी

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	परियोजना का शीर्षक	स्वीकृत अनुदान राशि (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	दर्शनशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	विश्वविद्यालय छात्रों के कार्य अनुस्थापन के सह-संबंधों पर एक अन्वेषण	11,700-00
2.	सेंट एन्स ट्रेनिंग कालेज, मंगलौर।	नवीं कक्षा के छात्रों की विज्ञान की विशेष धारणाओं को समझने के लिए अन्वेषण	1,000-00
3.	विश्वविद्यालय प्रशिक्षण कालेज, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर।	नागपुर के स्कूलों के 8 से 12 वर्ष के बीच के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों का सर्वेक्षण	550-48
4.	बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग कालेज, गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर।	प्रशिक्षण कालेज में शिक्षा पद्धतियों में प्रयोग	5,000-00

1	2	3	4
5.	शिक्षा विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।	बाल्यावस्था में भाषा का विकास	2,430-00
6.	इंस्टीट्यूट ग्राफ इंगलिश, कलकत्ता	पश्चिमी बंगाल के स्कूलों में दूसरी भाषा के रूप में बंगाली भाषा का अध्ययन	14,870-00
7.	विश्वविद्यालय अध्यापन मनोविज्ञान विभाग, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर ।	क्षेत्रीय-संघीय हिन्दी में मूल दक्षताओं के नैदानिक परीक्षण का मानकीकरण तथा निर्माण	7,000-00
8.	गवर्नमेन्ट ट्रेनिंग कालेज, त्रिचूर	कक्षा में शिक्षण योग्यता पर विशेष सामाजिक तत्वों का प्रभाव	2,000-00
9.	राज्य शैक्षणिक अनुसंधान ब्यूरो, बंगलौर ।	मैसूर राज्य में शिक्षा का इतिहास	1,000-00
10.	जी०एच०जी० खालसा कालेज ग्राफ एजुकेशन, गुरूसार सधार, लुधियाना ।	प्रशिक्षण कालेजों के स्नातकों का अनुवर्ती कार्य, कालेज के पश्चात् रोजगार और समायोजन	2,500-00
11.	विद्याभवन जी०एस० टीचर्स कालेज, उदयपुर ।	अध्यापकों के व्यावसायिक कार्य के एक विश्लेषण के आधार पर उनकी शिक्षा का यथार्थवादी कार्यक्रम विकसित करना ।	10,000-00

1	2	3	4
12.	विमेंस ट्रेनिंग कालेज, दयालबाग, आगरा।	वर्तमान पर्यवेक्षी विधियाँ: उनका मूल्यांकन तथा सुधार।	5,000-00
13.	जी० के० इंटीट्यूट ऑफ रूरल एजुकेशन, गर्गोटी, जिला कोल्हापुर।	प्राथमिक स्कूलों की कक्षा 1 से 5 के लिए एक अवर्गित इकाई।	500-00
14.	शिक्षा संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।	अध्यापक अभिवृत्ति सूची का विकास तथा छात्र अध्यापकों की वैयक्तिक अभिवृत्तियों में परिवर्तन का अध्ययन।	9,900-00
		कुल जोड़	73,450-48

परिशिष्ट 16

प्रशिक्षण कार्यक्रम (1971-72)

पिछले वर्षों की भाँति 1971-72 में भी परिषद् ने नीचे दिए गए अपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा अध्यापकों तथा अध्यापक-शिक्षकों की सेवा-पूर्व तथा सेवा-कालीन शिक्षा की ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया।

1. सेवा-पूर्व शिक्षा

1·01 **केन्द्रीय शिक्षा संस्थान :**

प्रतिवेदन वर्ष में, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली ने दिल्ली विश्वविद्यालय के बी० एड० और एम० एड० की डिग्रियों के नियमित पाठ्यक्रम जारी रखे। संस्थान ने एम० एड० डिग्री के दो वर्षीय संध्याकालीन अंशकालिक पाठ्यक्रम और इस विश्वविद्यालय की पीएच० डी० डिग्री के लिए अनुसंधान पाठ्यक्रम को जारी रखा। दो शोध छात्र श्री जगदीश मित्र महाजन और कुमारी ए० वासंथा इस वर्ष पी एच० डी० डिग्री दिए जाने के लिए हकदार घोषित किए गए। बी० एड० पत्राचार पाठ्य क्रम को 1971-72 से बन्द कर दिया गया। प्रतिवेदन वर्ष में संस्थान में कुल 210 छात्र थे जिनमें 17 बी० एड० के नियमित पाठ्यक्रम में, 20 एम० एड० के नियमित पाठ्यक्रम में और 19 एम० एड० के संध्याकालीन अंशकालिक पाठ्यक्रम में थे।

1·02 **क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय :**

परिषद् के अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय हैं। ये महाविद्यालय स्थापित करने का मुख्य प्रयोजन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के बाद 4-वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों के द्वारा, जिनमें विभिन्न विषयों का शिक्षण तथा शिक्षण संबंधी प्रशिक्षण संयुक्त रूप से हो, अध्यापकों को तैयार करना था। प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य के 4-वर्षीय पाठ्यक्रम क्रमशः 1968-69 तथा 1970-71 से समाप्त कर दिए गए थे। फिर भी वाणिज्य का 4-वर्षीय पाठ्यक्रम भोपाल और मैसूर के क्षेत्रीय महाविद्यालय में और प्रौद्योगिकी का 4-वर्षीय पाठ्यक्रम अजमेर क्षेत्रीय महाविद्यालय में पहले से नामांकित विद्यार्थियों के लिए चालू रखे गए। प्रतिवेदन वर्ष में, विज्ञान तथा अंग्रेजी के 4-वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम जारी रखे गए थे। इसके अतिरिक्त इन विषयों के संशोधित पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए थे। शिक्षा

महाविद्यालयों में वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा भाषा में स्नातक अध्यापकों के लिए बी० एड० के एक-वर्षीय पाठ्यक्रम जारी रखे गए। भुवनेश्वर तथा भोपाल क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में एम० एड० पाठ्यक्रम के लिए सीमित मात्रा में कुछ प्रदान की गई सुविधाएँ जारी रखी गई। इसके अलावा अजमेर क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में विज्ञान में एम० एड० पाठ्यक्रम जुलाई 1971 से शुरू किया गया। 1971-72 के शैक्षणिक सत्र में सभी क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में 4-वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों और एक-वर्षीय बी० एड० पाठ्यक्रमों में कुल 1997 छात्र नामांकित थे। एम० एड० पाठ्यक्रम में भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में 6 छात्र और अजमेर तथा भुवनेश्वर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में से प्रत्येक में 10 छात्र दाखिल किए गए।

देश के उच्च/उच्चत्तर माध्यमिक स्कूलों अप्रशिक्षित अध्यापकों को खत्म करने के लिए, परिषद् ग्रीष्मकालीन स्कूलों एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों का आयोजन करती रही है जिनके बाद इसके चारों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों से बी० एड० की डिग्री ली जा सकती थी। इस पाठ्यक्रम में दो गर्मी की छुट्टियों (4 महीनों) के दौरान पूर्णकालिक आशु प्रशिक्षण और दो गर्मियों की छुट्टियों के बीच की दस महीने की अवधि में पत्राचार के द्वारा अनुदेश सम्मिलित हैं। 1971-72 में चारों क्षेत्रीय कालेजों में इस पाठ्यक्रम के छात्रों की कुल संख्या 1,781 थी।

2. सेवा-कालीन शिक्षा

प्रतिवेदन वर्ष में परिषद् द्वारा अध्यापकों तथा स्कूली शिक्षा से संबद्ध अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाने के लिए किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

2·01 **ग्रीष्मकालीन विज्ञान संस्थान :**

(क) माध्यमिक स्कूल/विश्वविद्यालय/पूर्व पाठ्यक्रम/इंटरमीडिएट कालेज प्रशिक्षण कालेज के विज्ञान तथा गणित के अध्यापकों को उनके विषयों में हुए नवीनतम विकास से अवगत कराने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा परिषद् के सहयोग से पिछले कुछ वर्षों में ग्रीष्मकालीन संस्थानों का आयोजन करती रही है। ये ग्रीष्मकालीन संस्थान समान्यत: 5-6 सप्ताह की अवधि के लिए होते हैं और इनका आयोजन विश्वविद्यालय-कालेजों के ज्ञान साधन व्यक्तियों की सहायता से विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की अध्यक्षता में किया जाता है। प्रतिवेदन वर्ष में विज्ञान तथा गणित के 64 ग्रीष्मकालीन संस्थानों का देश के विभिन्न केन्द्रों में आयोजन किया गया। प्रतिवेदन वर्ष में ग्रीष्म विज्ञान संस्थानों के कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली की जाँच करने के लिए परिषद् ने श्री एम० वी० राजगोपाल की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है और इन संस्थानों की उपयोगिता और प्रभावता को सुधारने के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। वर्ष 1972 से

एन० सी० ई० आर० टी० का मार्गदर्शन राजगोपाल समिति की सिफारिशों द्वारा होगा जो ग्रीष्म विज्ञान संस्थानों को चलाने के लिए अकेले ही उत्तरदायी होगी। 1972 की गर्मियों में ऐसे 84 संस्थानों के आयोजन की योजना है।

(ख) परिषद् ने राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड, गुजरात के सहयोग से प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए 31 मई से 12 जून 1971 तक विज्ञान और गणित में एक ग्रीष्म-कालीन संस्थान का आयोजन किया। इस संस्थान का उद्देश्य भाग लेने वालों को राज्य के प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में चालू पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए अनुस्थापन देना है। 49 अध्यापक प्रशिक्षकों ने संस्थान में भाग लिया।

2.02. सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी के ग्रीष्मकालीन संस्थान

(क) परिषद् ने राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड, गुजरात के सहयोग से प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए 6 से 11 जून 1971 तक सामाजिक विज्ञान तथा भाषा में एक ग्रीष्मकालीन संस्थान का आयोजन किया। गुजरात के प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के 40 सामाजिक विज्ञान के अध्यापक प्रशिक्षकों और 50 भाषा के अध्यापक प्रशिक्षकों ने इस संस्थान में भाग लिया। सामाजिक विज्ञान में विषय को समाकलित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और विश्व शांति को विकसित करने के लिए पढ़ाने पर जोर दिया गया। भाषा शिक्षण में मौखिक कार्य और मातृ भाषा के सही उच्चारण पर महत्त्व दिया गया।

(ख) 27 मई से 30 जून 1971 तक देहरादून में प्रयोगिक भाषा विज्ञान तथा भाषा-शिक्षण पर एक ग्रीष्मकालीन संस्थान का आयोजन किया गया। यह संस्थान दो स्तरों—एक तो सामान्य स्तर और दूसरा अग्रिम स्तर, पर आयोजित किया गया। सामान्य स्तरीय पाठ्यक्रम में नए व्यक्तियों ने भाग लिया और अग्रिम स्तरीय पाठ्यक्रम में उन व्यक्तियों ने भाग लिया जो परिषद् द्वारा पहले आयोजित ऐसे पाठ्यक्रमों में भाग ले चुके थे या इसी प्रकार का प्रशिक्षण कहीं और प्राप्त कर चुके थे। विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों, अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों और माध्यमिक स्कूलों से 34 व्यक्तियों ने सामान्य स्तरीय पाठ्यक्रम में और 16 ने अग्रिम स्तरीय पाठ्यक्रम में भाग लिया। सभी भाग लेने वाले या तो हिन्दी भाषा और साहित्य के अध्यापक थे या इसी क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे थे।

2.03. प्रौद्योगिकी परियोजना पर ग्रीष्मकालीन संस्थान

पूर्वी क्षेत्र के भौतिकी के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर ने प्रौद्योगिकी परियोजना (कार्य-अनुभव) में एक ग्रीष्मकालीन संस्थान का आयोजन 1-6-1971 से 5-7-1971 तक किया। इस संस्थान में 17 अध्यापकों ने भाग लिया। भाग लेने वालों ने रूपांकन, निर्माण और प्रयोगात्मक सहित वैज्ञानिक परियोजनाएँ तैयार कीं। सब मिलाकर 175 परियोजनाएँ तैयार की गईं।

2.04. भारतीय शिक्षा की समकालीन समस्याओं पर ग्रीष्मकालीन संस्थान

इस संस्थान का आयोजन उदयपुर में 20 मई से 19 जून 1971 तक किया गया। इसमें भारतीय शिक्षा की बहुत सी समस्याओं जैसे शिक्षा में विशेषता के विरुद्ध मात्रा, शिक्षा और आर्थिक विकास, शिक्षा और आधुनिकीकरण, पड़ोसी स्कूलों और शिक्षा के व्यवसायीकरण इत्यादि पर विचार किया गया।

2.05. अधिगम, अभिप्रेरणा और समूह-प्रक्रम पर ग्रीष्मकालीन संस्थान

यह संस्थान मैसूर विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कालेजों, प्रशिक्षण कालेजों के शिक्षा और मनोविज्ञान विभागों के प्रशिक्षकों के लिए आयोजित किया गया था। इस संस्थान का उद्देश्य अध्यापक प्रशिक्षकों का अधिगम, अभिप्रेरणा और समूह-प्रक्रम क्षेत्रों में ज्ञान वृद्धि करना था जिनसे बाद में ऐसी आशा की जाती थी कि वह सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार करेंगे।

2.06. मार्गदर्शन में अनुसंधान प्रणाली पर शरदकालीन संस्थान

इस संस्थान में ऐसे व्यक्तियों को आमन्त्रित किया गया था जो या तो अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में मार्गदर्शन शिक्षण का कार्य कर रहे थे या मार्गदर्शन क्षेत्र में स्वयं अनुसंधान कर रहे थे या किसी का इसमें मार्गदर्शन कर रहे थे। इस संस्थान का उद्देश्य भाग लेने वालों के मार्गदर्शन से संबंधित अनुसंधान प्रणाली के ज्ञान में वृद्धि करना था। इस संस्थान का आयोजन राज्य शिक्षा संस्थान, पूना में किया गया था। देश के विभिन्न भागों से सब मिलाकर 25 व्यक्तियों ने भाग लिया। इस संस्थान को 35 दिन चलाने की योजना थी परन्तु 18 दिनों के बाद राष्ट्रीय आपात स्थिति के कारण इसे बन्द कर देना पड़ा। इन 18 दिनों के दौरान लगभग 50 प्रतिशत पाठ्यक्रम पूरा किया जा चुका था। इन भाग लेने वालों के प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए इनको 1972 की गर्मियों में इस विषय पर आयोजित होने वाले संस्थान में आमन्त्रित करने का फैसला किया गया।

2.07. शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन डिप्लोमा पाठ्यक्रम

शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन संबंधी 11वाँ पूर्णकालिक स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम 15 जुलाई 1971 से 14 अप्रैल 1972 तक आयोजित किया गया। इस पाठ्यक्रम का रूपांकन राज्य मार्गदर्शन ब्यूरो के सलाहकारों और प्रशिक्षण कालेजों में मार्गदर्शन पढ़ाने वाले अध्यापक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। 25 व्यक्तियों की क्षमता के विपरीत इस पाठ्यक्रम में 22 व्यक्तियों ने भाग लिया और उनमें से 20 ने पूरा किया। इन 20 भाग लेने वालों में से 10 राज्य सरकारों द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए थे।

2.08. अन्य अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभिन्न क्षेत्रों में अन्य अनेक अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों की संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है।

1. दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को अध्यापन व्यवसाय में प्रशिक्षित करने के लिए एक तीन सप्ताह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 52 अध्यापकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

2. दिल्ली के अध्यापकों के लिए माध्यमिक स्कूलों में श्रव्य-दृश्य उपकरणों के प्रयोग पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

3. दिल्ली के माध्यमिक स्कूलों में कार्य कर रहे पुस्तकालय-अध्यक्षों के लिए स्कूल पुस्तकालय के प्रभावपूर्ण प्रयोग के संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 41 स्कूलों के पुस्तकालय-अध्यक्षों ने भाग लिया।

4. दिल्ली नगर निगम के अनुरोध पर विज्ञान क्लबों के प्रयोजकों को विभिन्न कार्यकलापों में प्रशिक्षण देने के लिए दो एक-एक सप्ताह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 77 अध्यापकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

5. दिल्ली स्कूलों के भूगोल अध्यापकों के लिए भूगोल के अध्यापन संबंधी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

6. दिल्ली के अध्यापकों के लिए प्रयोगात्मक परियोजनाओं के रूपांकनों को विकसित करने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

7. श्रव्य-दृश्य शिक्षा संबंधी 6 सप्ताह के एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन 12 मई से 22 जून 1971 तक किया गया जिसमें अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों और राज्य शिक्षा संस्थानों से आए 22 अध्यापक प्रशिक्षकों ने भाग लिया।

8. अक्तूबर-नवंबर 1971 में श्रव्य-दृश्य उपकरणों की कार्यपद्धति संधारण तथा मरम्मत के संबंध में एक मासीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न भागों से आए 12 व्यक्तियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

9. अगस्त 1971 में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर में श्रव्य-दृश्य शिक्षा में एक-मासीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया। पूर्वी क्षेत्र के अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के 16 अध्यापकों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। इसमें श्रव्य-दृश्य पाठ्यक्रम के कम दाम वाले साधनों पर जोर दिया गया।

10. प्राथमिक अध्यापक शिक्षण संस्थाओं के अध्यापक प्रशिक्षकों और राज्य शिक्षा संस्थानों के अधिकारियों के हैदराबाद में अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों को परिषद् द्वारा विकसित सामाजिक अध्ययन में सेवा-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम से अवगत कराया और राज्यों में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए उनको अनुस्थापित किया।

11. भारत सरकार के प्रथम श्रेणी के अफसरों के लिए हिन्दी में परिषद् की भाषा प्रयोगशाला में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के सहयोग से दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

12. नेफा के अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए 'प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी का दूसरी भाषा के रूप में शिक्षण' पर जनवरी 1972 में एक महीने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया । इस पाठ्यक्रम में एक विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी के अध्यापन की विषत वस्तु तथा प्रणाली दोनों का समन्वय किया गया ।

13. अक्तूबर 1971. में परिषद् की भाषा प्रयोगशाला में प्रशिक्षण कालेजों के लेक्चरारों तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए दूसरी या तीसरी भाषा के शिक्षण में टेप रिकार्डों तथा भाषा प्रयोगशालाओं के प्रयोग पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया ।

14. प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों के लिए परिषद् की भाषा प्रयोगशाला में मई 1971 में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया ।

15. प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम एक रांची में अक्तूबर-नवम्बर 1971 के दौरान और दूसरा दिल्ली में दिसम्बर 1971 से जनवरी 1972 के दौरान आयोजित किए गए । कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित थे :—

(क) भाग लेने वालों को जनजातीय संस्कृति और उसकी अच्छाइयों का ज्ञान कराना ।

(ख) उन्हें जनजातीय शिक्षा की विशेष समस्याओं से अवगत कराना ।

(ग) जनजातीय बच्चों के मुताबिक कक्षा स्थिति में सुधार करना, और

(घ) जनजातीय बच्चों में उपलब्धि प्रवृत्ति विकसित करना ।

16. प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षकों को प्रयोगात्मक परियोजनाएँ चलाने के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

17. दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के अनुरोध पर चुने हुए प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों तथा पर्यवेक्षकों को प्राथमिक स्कूलों में बरबादी और गतिहीनता को कम करने के कार्यक्रमों के विकसित करने से संबंधित तीन दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

18. उत्तरी क्षेत्र के पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए शिशु विकास पर एक दो-सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया । 23 व्यक्तियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया ।

19. व्यवहार सुधार पर एक आनुक्रमिक पाठ्यक्रम (स्तर II) का दिल्ली में 9 से 22 मार्च 1972 तक आयोजन किया गया । देश के विभिन्न भागों से 35 व्यक्तियों ने भाग लिया । इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित थे :—

(क) भाग लेने वालों को व्यवहार सुधार के क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति से अवगत कराना,

(ख) भाग लेने वालों को कक्षा की स्थितियों में लाभदायक विभिन्न व्यवहार सुधार तकनीकों से अवगत कराना, और

(ग) भारतीय स्कूल स्थिति के विशेष संदर्भ में प्रयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाना।

20. अप्रैल 1971 में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर में अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षण पर एक सेवा-कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। उड़ीसा के स्कूलों के अंग्रेजी के 23 अध्यापकों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षण को आधुनिक भाषा विषयक उपागमनों में अनुस्थापित करना था।

21. उड़ीसा सरकार के राज्य शिक्षा विभाग के अनुरोध पर क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर ने जून 1971 में कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्यक्रम का आयोजन किया। इस पाठ्यक्रम में उड़ीसा के गहन कृषि विकास जिलों से आए व्यक्तियों ने भाग लिया।

22. उड़ीसा के माध्यमिक स्कूलों से आए जीव विज्ञान के अध्यापकों के लिए छः दिवसीय सेवा-कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन जनवरी 1972 में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर में किया गया। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य भाग लेने वालों को माध्यमिक स्कूल स्तर के संदर्भ में जीव विज्ञान के अध्यापन के विषय तत्व तथा प्रणाली में हुए कुछ महत्वपूर्ण विकासों से अवगत कराना है।

23. पूर्वी क्षेत्र के अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के चुने हुए अध्यापकों के दल की एक बैठक मनोविज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के निर्माण की दृष्टि से बी० एड० के मनोविज्ञान कार्यक्रम पर विचारविमर्श करने के लिए बुलाई गई। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों पर भी विचार-विमर्श किया गया। दस अध्यापक प्रशिक्षकों ने इस विचार-विमर्श में भाग लिया जो पाँच दिन तक चालू रहा।

24. प्रतिवेदन वर्ष में उड़ीसा के अंग्रेजी के अध्यापकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विचार-विमर्श और अनुस्थापना का मुख्य विषय "बोली जाने वाली अंग्रेजी" था। उच्चारण का ध्यान रखते हुए ध्वनिशास्त्र के मूलतत्वों पर जोर दिया गया। 19 अध्यापकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया जो मार्च 1972 में छः दिनों तक चला।

25. 13 से 22 मार्च 1972 तक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली और चंडीगढ़ संघ क्षेत्रों के प्राथमिक तथा माध्यमिक विस्तार सेवा केन्द्रों के अवैतनिक निदेशकों तथा समन्वय कर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे : सेवा-कालीन शिक्षा के विकासशील विचारों, तकनीकों, तरीकों, और योजनाओं तथा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्न विभागों में हुए

अनुसंधान और अध्ययनों, और विभिन्न केन्द्रों में कार्यान्वित हो रहे सेवा-कार्यों के संबंध में अवगत कराना।

26. 6 जुलाई से 9 जुलाई 1971 तक क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर ने सहयोगी स्कूलों के अध्यक्षों तथा अध्यापकों के लिए चार-वर्षीय बी० एस सी० एड० और बी० ए० एड० के अध्यापन कार्यक्रम का आयोजन किया। 40 स्कूल अध्यक्षों तथा अध्यापकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। भाग लेने वालों को अध्यापन और मूल्यांकन के वस्तुपरक लक्ष्यों के संबंध में अनुस्थापित किया गया।

27. सहयोगी स्कूलों के अध्यक्षों तथा अध्यापकों के लिए एक वर्षीय बी० एड० के अध्यापन कार्यक्रम में स्थानबद्धता पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर में 10 नवम्बर से 12 नवम्बर 1971 तक हुआ। 73 अध्यक्षों तथा अध्यापकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। भाग लेने वालों ने अध्यापन तथा मूल्यांकन तथा पाठयोजना के वस्तुपरक लक्ष्य के संबंध में विचार-विमर्श किया।

28. पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए विज्ञान और गणित में इन राज्यों के विश्वविद्यालयों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले बी० एड० पाठ्यक्रम की योजना तैयार करने के लिए एक सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम तैयार किया गया। यह कार्यक्रम विज्ञान शिक्षा और अध्यापक शिक्षा विभागों ने मिलकर आयोजित किया।

29. राज्य विज्ञान संस्थानों के निदेशकों और दूसरे राज्यों के मुख्य अधिकारियों को विज्ञान शिक्षण पर प्राथमिक और मिश्रित स्कूलों के लिए विकसित किए गए नए तरीके और पाठ्यक्रम सामग्री के विषय तत्त्व से अवगत कराने के लिए 10 दिन की अवधि का एक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनको इन दो स्तरों के विज्ञान शिक्षण किटों और उपकरणों से भी परिचित कराया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण को सुधारने के लिए यूनेस्को-यूनीसेफ-सहायता प्राप्त मार्गदर्शी परियोजना का एक अंग था।

30. कार्यक्रमबद्ध अधिगम पर छठे आनुक्रमिक पाठ्यक्रम का आयोजन जून 1971 में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल में किया गया।

परिशिष्ट 17

विस्तार और क्षेत्र सेवाएँ

1971-72 के दौरान विस्तार और क्षेत्र सेवाओं की व्यवस्था के लिए किए गए कार्य की उन्नति निम्नलिखित पैराग्राफों में दी जाती है :—

1. विस्तार सेवा केन्द्र

देश में चुने हुए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थित 95 माध्यमिक और 45 प्राथमिक विस्तार सेवा केन्द्रों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण 1-4-71 से उनकी अपनी राज्य सरकारों को स्थानांतरित किया गया था। तथापि, राज्यों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के क्षेत्र सलाहकारों द्वारा सीमित मात्रा में उन केन्द्रों को शैक्षणिक मार्ग-दर्शन किया जाना जारी रहेगा। क्षेत्र सलाहकारों द्वारा किए गए मार्ग-दर्शन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

मार्च, 1972 में राजस्थान में विस्तार सेवाओं का वार्षिक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में विगत वर्ष में अभिप्राप्त अनुभवों की समीक्षा की गई और 1972-73 के लिए कार्यक्रम बनाया गया। क्षेत्र सलाहकार, जयपुर ने सम्मेलन में भाग लेने वालों को 1972-73 के लिए विस्तार सेवा केन्द्रों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में सहायता प्रदान की। यह निर्णय किया गया कि 1972 के उन कुछ कार्यकलापों को जारी रखा जाए जो प्रायोगिक परियोजनाएँ, विचार-गोष्ठी पठन, संस्थागत योजना, अध्याय प्रदर्शन, परीक्षित पद्धतियों का प्रसार, विद्यालय भाव ग्रंथियों, प्रधानाध्यापकों की गोष्ठी और अध्यापकों के अध्ययन क्षेत्र, मूल्यांकन कार्यक्रम और बालवाड़ी परियोजना जैसे कार्यकलाप विगत में उपयोगी पाए गए थे। क्षेत्र सलाहकार के सुझाव पर सभी भाग लेने वाले इस बात से सहमत हुए कि निम्नलिखित क्षेत्रों में नए कार्यक्रम जारी और विकसित किए जाएँ :—

(क) शिशु शिक्षा का गति त्वरण।

(ख) राष्ट्रीय विकास और सामाजिक एवं आर्थिक दर्जे की शिक्षा में अध्यापकों के योगदान को महसूस करने में सहायता देना।

(ग) शिक्षा-पद्धति की कमियों के बारे में जनमत को सूत्रबद्ध करना जिससे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज, 1968 में अन्तर्विष्ट जैसे निर्णयों

को कार्यान्वित कर समाज और सरकार को उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित करना।

(घ) शैक्षणिक कार्यकलापों द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण।

क्षेत्र सलाहकार (शिलाङ) ने असम सरकार के साथ राज्य में विस्तार सेवा केन्द्रों को अपने अधिकार में लेने के लिए सतत प्रयत्न किए। उसने मणिपुर और त्रिपुरा के विस्तार सेवा केन्द्रों के अवैतनिक निदेशकों और समन्वयकों का मणिपुर सरकार के सहयोग से मार्च, 1972 में इम्फाल में एक सम्मेलन आयोजित किया। उसने सम्मेलन में दो सुझाव दिए, जिनमें से एक "योजना विस्तार कार्यक्रम की तकनीकें" और दूसरा "राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् एवं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के वर्तमान कार्यक्रमों का इतिवृत्त और संगठन" के बारे में था। क्षेत्र कार्यालय, शिलाङ के प्राध्यापक ने भी "शैक्षणिक विकास में विस्तार केन्द्रों की भूमिका" के बारे में सुझाव दिया। मणिपुर के साथ प्राथमिक विस्तार केन्द्रों के अवैतनिक निदेशकों और समन्वयकों तथा अगरतला के प्राथमिक विस्तार केन्द्रों के समन्वयकों ने सम्मेलन में भाग लिया।

क्षेत्र सलाहकार (त्रिवेंद्रम) ने राज्य स्तरीय सम्मेलन में केरल के माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, विद्यालयों के पर्यवेक्षकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियों और कक्षाओं में उपस्थित होने वाली समस्याओं के बारे में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की भूमिका के बारे में अवगत कराया।

क्षेत्र सलाहकार (दिल्ली और उत्तर प्रदेश) ने राज्य में स्थायी आधार पर विस्तार सेवा केन्द्रों को चालू रखने के प्रश्न के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को आश्वस्त किया। उसने अगस्त, 1971 में लखनऊ में हुए वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लिया। अन्य बातों के साथ-साथ सम्मेलन में राज्य सरकार से यह अनुरोध करते हुए संकल्प पारित किया गया कि केवल विद्यमान प्रसारण सेवा केन्द्रों को ही चालू न रखा जाए अपितु, नए केन्द्र भी खोले जाएँ। क्षेत्र सलाहकार (दिल्ली और उत्तर प्रदेश) ने माध्यमिक विस्तार सेवा केन्द्रों से अवैतनिक निदेशकों और समन्वयकों के लखनऊ और मुजफ्फर नगर में हुए दो क्षेत्रीय सम्मेलनों के विचार-विमर्श में मार्ग दर्शन किया। इन सम्मेलनों में केन्द्रों के अनेक प्रशासकीय और शैक्षिकीय समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श हुआ।

क्षेत्र सलाहकार (पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़) ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलनों में शैक्षणिक मार्ग दर्शन की व्यवस्था की। शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, निदेशक लोक शिक्षण/शिक्षा निदेशक, संयुक्त निदेशक, लोक शिक्षण/संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, प्रशिक्षण महाविद्यालय, निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान,

प्रधानाध्यापक, अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय और राज्य मूल्यांकन और मार्ग दर्शन ब्यूरो के सभी प्रधानों ने इन सम्मेलनों में भाग लिया। इन राज्य स्तरीय सम्मेलनों में समस्त राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार कार्य को ध्यान में रखते हुए समस्त भाग लेने वालों के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इन सम्मेलनों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् और शिक्षा के राज्य विभागों के आपसी सम्बन्धों पर भी विचार-विमर्श किया गया। क्षेत्र सलाहकार ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में विस्तार सेवा-केन्द्रों के अवैतनिक निदेशकों और समन्वयकों का सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में 20 अवैतनिक निदेशकों और समन्वयकों ने भाग लिया। सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :—

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए कार्य की समीक्षा;

(ख) विस्तार कार्य को क्रियात्मक बनाने तथा उन्हें कक्षा की आवश्यकताओं के अनुकूल करने की दृष्टि से अगले वर्ष के लिए कार्य की योजना तैयार करना;

(ग) राज्य के विभिन्न विस्तार अभिकरणों के मध्य समन्वय का अध्ययन;

(घ) केन्द्रों के सामने आई कुछ प्रशासनिक और वित्तीय समस्याओं का अध्ययन;

(ङ) विभिन्न राज्यों में शिक्षा की प्रवृत्तियों पर विचार-विमर्श; और

(च) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से विभिन्न विस्तार सेवा केन्द्रों की सम्भावनाओं को सुनिश्चित करना।

क्षेत्र सलाहकार (पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़) ने, क्षेत्र सलाहकार (दिल्ली और उत्तर प्रदेश) के सहयोग से 13 से 22 मार्च, 1972 तक दिल्ली में प्राथमिक और माध्यमिक विस्तार केन्द्रों के अवैतनिक निदेशकों और समन्वयकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली और चंडीगढ़ के अवैतनिक निदेशकों और समन्वयकों ने पाठ्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, इस में भाग लेने वालों को सेवारत शिक्षा की विकासशील भावना, पद्धति और शैली तथा क्षेत्र और कौशल से परिचित कराना था। भाग लेने वालों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अंशकृत-एककों में आयोजित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, अनुसंधानों और अध्ययनों के बारे में तथा विभिन्न विस्तार केन्द्रों में किए जा रहे प्रसारण कार्यों के विशिष्ट पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी गई।

क्षेत्र सलाहकार (पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश

श्रौर चंडीगढ़) ने दिल्ली में अश्रेणीकृत पद्धति के बारे में एक कार्य शिविर आयोजित किया। भाग लेने वालों ने अवशिष्ट और स्थिरता को कम करने के लिए और विद्यार्थियों को उनके अपनी गति से पठन का अवसर प्रदान करने के लिए नए तकनीक के रूप में अश्रेणीकृत पद्धति को प्रयोग करने के बारे में विचार-विमर्श किया। भाग लेने वालों ने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक पद्धति का विकास किया। उन्होंने अश्रेणीकृत पाठशाला की विचारधारा को स्पष्ट किया और पाठ्यक्रम, कक्षा स्थितियों का संगठन और प्रशासन, परीक्षा और मूल्यांकन पद्धतियों, अध्यापन के तरीके, क्रमिक कार्यों की तैयारी, विद्यार्थी अध्यापक और निरीक्षकों के लिए प्रशासनिक निहितार्थों और स्वाध्याय सामग्री की तैयारी में उसके निहितार्थों की जाँच की। भाग लेने वालों ने भाषा, गणित और विज्ञान में आदर्श एककों को भी विकसित किया। यह प्रस्तावित किया जाता है कि इन एककों को पुनरीक्षित किया जाए और आगे के विकास के लिए प्रयुक्त किया जाए। विचार-विमर्श के दौरान अश्रेणीकृत पद्धति के एक तृतीय पहलू की ओर भी भाग लेने वालों का ध्यान केन्द्रित हुआ। यह प्राथमिक अवस्था में शिक्षा के सर्वसामान्यीकरण के लक्ष्य को अभिप्राप्त करने में सहायता देने में इसकी दक्षता के सम्बन्ध में है।

क्षेत्र सलाहकार भुवनेश्वर ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के विद्यालयों में कक्षाओं में दिए जाने वाले अनुदेशों में सुधार के लिए दो कार्यक्रम आयोजित किए। उसने 13 से 15 जुलाई, 1971 और 27 जुलाई, 1971 को क्रमशः पटना और कलकत्ता में हुए दो सम्मेलनों में, जिनमें बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से विस्तार सेवा केन्द्रों (प्राथमिक और माध्यमिक दोनों) के अवैतनिक निदेशक और समन्वयकों ने भाग लिया, विचार-विमर्शों का मार्गदर्शन किया। क्षेत्र सलाहकार ने भाग लेने वालों को 1972-73 के लिए उनके केन्द्रों के बारे में कार्यक्रम बनाने में सहायता प्रदान की।

क्षेत्र सलाहकार, भोपाल ने महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों को विस्तार सेवा केन्द्रों के यथोचित प्रबन्ध ग्रहण में सहायता प्रदान की। उसने महाराष्ट्र सरकार से यह आग्रह किया कि वह राज्य के प्रत्येक जिले में प्रसारण केन्द्र प्रारम्भ करे। उसने उस समिति को भी सहायता प्रदान की जो गुजरात सरकार द्वारा राज्य में विस्तार केन्द्रों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित की गई थी।

2. विचार गोष्ठी पठन

1971-72 के दौरान, 17 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों से विचार गोष्ठी पठन कार्यक्रम की नवीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 154 पत्रक प्राप्त हुए थे। इनमें से प्रारम्भिक मूल्यांकन के आधार पर, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के दो जाँच कर्ताओं द्वारा प्रत्येक पत्रक की स्वतंत्र रूप से जाँच की गई थी, 65 पत्रक अंतिम जाँच-पड़ताल के लिए छाँटे गए। इन 65 पत्रकों की पुनः दो जाँच कर्ताओं द्वारा अंतिम रूप से जाँच की गई। पूर्णतः योग्यता

के आधार पर, 30 पत्रक राष्ट्रीय स्तर पर छाँटे गए। राष्ट्रीय आपात स्थिति के कारण, पारितोषिक लेने वालों का वार्षिक राष्ट्रीय समारोह नहीं मनाया जा सका और प्रत्येक को प्रशस्ति पत्र तथा 500/- रु० का नकद पारितोषिक डाक द्वारा भेजा गया। पारितोषिक के लिए चुने गए 30 पत्रकों का विषय-वार विवरण निम्नलिखित था :—

(i)	विज्ञान, आधुनिक गणित, अंग्रेजी और हिन्दी जैसे विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों के अध्यापन में सुधार	 14
(ii)	कक्षा स्थितियों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का संपरीक्षण	 9
(iii)	शिक्षा में सामाजिक अवयव	 2
(iv)	शिक्षा प्रशासन	 1
(v)	जाँच और परीक्षाएँ	 2
(vi)	पाठ्यक्रम-बाह्य-कार्यकलाप	 1
(vii)	पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण	 1
	योग	30

3. विचार गोष्ठियाँ, कार्यशिविर, सभाएँ, सम्मेलन आदि

1971-72 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विचार गोष्ठियाँ, कार्यशिविर, सभाएँ, सम्मेलन आदि आयोजित किए गए थे जिनका संक्षेप में विवरण नीचे दिया जाता है :—

(i) राज्य शिक्षा संस्थानों के कार्मिकों के लिए 13 से 25 सितम्बर, 1971 तक दिल्ली में तृतीय विचारगोष्ठी-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य प्रयोजन पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री और पद्धति, मूल्यांकन, अध्यापन-साधन आदि के क्षेत्र में नए विचारों और नूतन विषयों के बारे में विचार-विमर्श करना था। "सटेलाइट्स कम्यूनिकेशन एण्ड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर एजूकेशन एट दि प्राइमरी एण्ड सेकेण्डरी स्टेजेज" (प्राथमिक और माध्यमिक अवस्थाओं में शिक्षा के लिए उपांश संचार और उसकी विवक्षाएँ) के बारे में श्री रमेश चन्द्र, इंचार्ज दूरदर्शन (उपांश), आकाशवाणी द्वारा वार्ता, इस कार्यक्रम का एक अंग बनी। लगभग समस्त राज्य शिक्षा संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 24 व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने अपने संस्थानों के बारे में महत्वपूर्ण कार्य-क्रमों पर भी विचार-विमर्श किया।

(ii) परिषद् द्वारा अध्यापक शिक्षा के लिए राज्य बोर्ड, गुजरात के सहयोग से 31-5-1971 से 5-6-1971 तक गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में गुजरात राज्य के स्नातक आधारित प्रशिक्षण केन्द्रों (ग्रेज्युएट बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर्स) के प्रधानाध्यापकों, प्राध्यापकों के लिए विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। 6 स्नातक आधारित प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 26 व्यक्तियों ने इस विचार गोष्ठी में भाग लिया। इन केन्द्रों के लिए विकसित संशोधित पाठ्यक्रम और उसके कार्यान्वयन के विवरणों के बारे में भी भाग लेने वालों द्वारा विचार-विमर्श किया गया।

(iii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा अध्यापक शिक्षा के बारे में राज्य बोर्ड, गुजरात के सम्मिलित तत्वावधान में, गुजरात में बी० एड० की शिक्षा के महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए 1 से 4 जून, 1971 तक गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण, मूल्यांकन पद्धतियों का सुधार और अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्य पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ।

(iv) बी० एड० पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए शिक्षा विभाग, गौहाटी विश्वविद्यालय में 2 जुलाई, 1971 से 8 जुलाई, 1971 तक कार्यशिविर आयोजित किया गया था। इस कार्यशिविर में गौहाटी और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालयों से 20 अध्यापक शिक्षकों ने भाग लिया। इन दो विश्वविद्यालयों में जनवरी, 1972 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षा-सत्र से अपनाए जाने और कार्यान्वित किए जाने वाले बी० एड० पाठ्यक्रम के अधिकतर भाग को अंतिम रूप दिया गया था।

(v) विज्ञान के अध्यापक शिक्षकों के अनुस्थापन के लिए राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, चंडीगढ़ में 4 से 16 अक्तूबर, 1971 तक विचार गोष्ठी सह-कार्यशिविर का आयोजन किया गया था। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के शिक्षा महाविद्यालय के विज्ञान के प्राध्यापकों ने इस कार्यशिविर में भाग लिया। "साधारण विज्ञान का अध्यापन" के पाठ्यक्रम को 9 एककों में विभाजित किया गया और प्रत्येक एकक के लिए अध्यापक-मार्गदर्शन तैयार किया गया।

(vi) क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान, चंडीगढ़ के सहयोग से 27 सितम्बर, से 9 अक्तूबर, 1971 तक अंग्रेजी के अध्यापन के बारे में विचार गोष्ठी-सह-कार्यशिविर का आयोजन किया गया था। पंजाब, गुरुनानक, कुरुक्षेत्र और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों में बी० एड० के महाविद्यालयों में अंग्रेजी के 27 कार्यरत प्राध्यापकों ने विचार गोष्ठी में भाग लिया। विचार गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य अध्यापक शिक्षकों को सुपद्धतियों और शैलियों के नए पाठ्यक्रम के अध्यापन में स्थिति ज्ञान कराना था। भाग लेने वालों ने यह सिफारिश की कि अंग्रेजी के अध्यापन में आधुनिक शैलियों के मूल्यांकन को बी०एड० के कार्यक्रम में भी चालू किया जाना चाहिए।

(vii) गणित के अध्यापन के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अध्यापक शिक्षा विभाग और विज्ञान शिक्षा विभाग ने सम्मिलित रूप से दिल्ली में 13 से 25 मार्च, 1972 तक विचार गोष्ठी-सह-कार्यशिविर का आयोजन किया। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से गणित के 15 अध्यापक शिक्षकों ने इस कार्यशिविर में भाग लिया।

विचार गोष्ठी में नए गणित के संदर्भ में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :—

(क) संख्या पद्धति

(ख) संबंध और कृत्य

(ग) सैट

(घ) आधार पद्धति

(ङ) प्रतीकात्मक तर्क

(च) प्रमाण की प्रकृति

(छ) ज्यामिति सिद्धान्त और अज्यामिति-सैद्धान्तिक रेखागणित

(ज) बीजगणितीय पद्धति

(झ) संगणक गणित

(ञ) गणित पाठ्यक्रम

(ट) गणित मूल्यांकन।

(viii) माध्यमिक पाठशालाओं में प्रायोगिक परियोजनाओं का मार्गदर्शन करने के लिए साधन-स्रोत कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु 15 से 20 सितम्बर, 1971 तक क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर में कार्यशिविर का आयोजन किया गया। कार्यशिविर में विभिन्न राज्यों के 18 व्यक्तियों ने भाग लिया।

(ix) पाठशाला के अध्यापकों में सुधारीकृत अध्यापन साधनों को तैयार करने और उनके प्रयोग में जागरूकता का सर्जन करने और जागृति का बोध कराने के लिए प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु 1970-71 में एक प्रायोजना आरंभ की गई थी। रिपोर्टाधीन कालावधि के दौरान प्रायोजना को दैनिक अंग्रेजी समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया गया और प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गईं। लगभग 300 विवरणात्मक रूपरेखाएँ प्राप्त की गई थीं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने सात साधनों की, प्रत्येक को 250 रुपये के मूल्य के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए, अंतिम रूप से सिफारिश की।

(x) प्राइवेट उत्पादकों को देश की पाठशालाओं द्वारा अपेक्षित मानक श्रव्य-दृश्य साधनों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय पुरस्कार

देने की एक और प्रायोजना विगत वर्ष में बनाई गई है। 1971-72 वर्ष के दौरान इस परियोजना को 10 दैनिक अंग्रेजी समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया गया था। परिषद् द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने 500 रुपए प्रति प्रथम पुरस्कार हेतु दो अनुदानों और 250 रुपए प्रति द्वितीय पुरस्कार हेतु सात अनुदानों की सिफारिश की।

(xi) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् के केन्द्रीय फिल्म फिल्मालय में 134 फिल्में सम्मिलित की गईं जिससे फिल्मालय में उपलब्ध फिल्मों की कुल संख्या 7,098 हो गई। वर्ष के दौरान फिल्मालय ने अपने सदस्य संस्थानों को 10843 फिल्म और 141 फिल्म स्ट्रिपों को जारी किया।

(xii) केन्द्रीय कस्टम विभाग ने बिना किसी लागत के परिषद् को अनेक जब्त की हुई फिल्में प्रदान कीं। इन फिल्मों की जाँच करवाई जा चुकी है और केन्द्रीय फिल्मालय के माध्यम से परिचालित की जा रही हैं।

(xiii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने भारतीय मानक संस्था के सहयोग से फिल्म स्ट्रिप-कम-स्लाइड-प्रोजेक्टर के निर्माण लिए मानक को अंतिम रूप दिया है। इस मानक को विस्तृत रूप से परिचालित किया गया था ताकि विनिर्माता स्वदेशीय सामान से इसका उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर सकें।

(xiv) भाषा के बारे में मौलिक अनुसंधान पर द्वितीय राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी में मार्च, 1972 को हुई थी। दर्शन, व्याकरण और कविता के संबंध में भारतीय विचारधाराओं के विभिन्न शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 25 साहित्य कर्मज्ञों ने विचार गोष्ठी में भाग लिया। भाग लेने वाले लोगों द्वारा विचार गोष्ठी में अभिव्यक्त किए गए विचारों का संकलन किया जा रहा है और उनको पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

(xv) अक्तूबर, 1971 में दिल्ली में जनसंख्या शिक्षा के बारे में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में निदेशक, लोक शिक्षण शिक्षा निदेशक और विभिन्न राज्यों संघ राज्यों के शिक्षा संस्थानों, के निदेशकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य प्रयोजन सम्मेलन में भाग लेने वालों को परिषद् द्वारा जनसंख्या शिक्षा के बारे में तैयार किया गया पाठ्यक्रम और अन्य सामग्री से अवगत कराना था। सम्मेलन ने विद्यालयों और अध्यापक-शिक्षण संस्थानों में जनसंख्या शिक्षा के अध्यापन के लिए उपयोगी सिफारिश की। सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की है कि विद्यालयों में अध्ययन न करने वाले व्यक्तियों को जनसंख्या शिक्षा के बारे में अनुदेश देने के लिए कार्यक्रम को विकसित किया जाए। सम्मेलन की रिपोर्ट अब मुद्रित हो चुकी है।

(xvi) वर्ष के दौरान, सेवापूर्व और सेवा में प्रशिक्षण पा रहे अध्यापकों

के लिए जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम के विकास हेतु कार्यशिबिर आयोजित किया गया था।

(xvii) ग्रामीण बालवाड़ी की विचारधारा और लक्ष्यों को विकसित करने के लिए और कुछेक महत्वपूर्ण कार्यकलापों/कार्यक्रम जो इसके द्वारा किए जाने चाहिए, का सुझाव देने के लिए अखिल भारतीय कार्यशिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्य शिविर के परिणामस्वरूप "बालवाड़ी अध्यापकों के लिए पुस्तिका" लिखी गई थी। इस पुस्तिका के प्रारूप को कार्यकारी दल द्वारा अंतिम रूप दिया गया और मुद्रण के लिए भेजा गया।

(xviii) शिक्षा की प्रारम्भिक अवस्था के लिए न्यूनतम पाठ्यक्रम मानक को विकसित करने के लिए अखिल भारतीय कार्यशिविर को आयोजित किया गया था जिसमें राज्य शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा संस्थान और प्राथमिक शिक्षा में गैर-सरकारी विशेषज्ञों आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशिविर में दस दिन तक विचार-विमर्श जारी रहा और उसकी परिणति प्रारम्भिक अवस्था में अध्यापन कार्य के सिद्धान्तों में हुई। यह प्रस्तावित किया गया है कि इस पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए आगे जाँच की जाए।

(xix) प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त मापदण्ड विकसित करने के लिए वर्ष के दौरान अखिल भारतीय कार्यशिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्यशिविर में साधारण मापदण्ड बनाए गए और विभिन्न पाठ्यक्रमों में उसके प्रभाव के बारे में भी रूपरेखा बनाई गई। मापदण्ड के प्रयोग के लिए एक प्रारूप निर्देशिका भी तैयार की गई थी।

(xx) लोनी खण्ड (मेरठ जिला) में अश्रेणीकृत विद्यालय पद्धति के बारे में प्रायोगिक परियोजना के संबंध में 1971-72 के दौरान निम्नलिखित कार्यशिविर/विचारगोष्टियाँ आयोजित की गई थीं :—

(क) साधारण विज्ञान, कला और दस्तकारी में अध्यापन एककों को तैयार करने के लिए कार्यशिविर।

(ख) अश्रेणीकृत विद्यालय पद्धति के बारे में विचार गोष्ठी।

(ग) गणित में अध्यापन एककों को तैयार करने के लिए कार्यशिविर।

(घ) हिन्दी में अध्यापन एककों को तैयार करने के लिए कार्यशिविर।

उत्तर प्रदेश में तीसरी से पाँचवीं कक्षाओं के लिए विषय विवरण को ध्यान में रखते हुए इन कार्यशिविरों में विभिन्न विषयों में अध्यापक एकक तैयार किए गए थे।

(xxi) वर्ष के दौरान पिछड़े लोगों की प्राथमिक, माध्यमिक और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

(xxii) प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए शब्दावली बनाने के लिए साधनों को विकसित करने के लिए कार्यशिविर का आयोजन किया गया। कार्यशिविर में चार प्रकार की शब्दावली, अर्थात् सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए साधन विकसित किए गए थे। बोली हुई और लिखी हुई शब्दावली के लिए साधनों को कुछ विद्यालयों में किए गए प्रयोग को ध्यान में रखकर संशोधित किया गया था।

(xxiii) 1971-72 के दौरान प्राथमिक स्तर पर बरबादी और स्थिरता को कम करने के लिए कार्य में परिणत किए जाने वाले कार्यक्रमों पर अखिल भारतीय कार्यशिविर आयोजित किया गया। राज्य शिक्षा विभाग, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, जिला शिक्षा समिति, नगर निगमों और समितियों इत्यादि के प्रतिनिधियों ने इस कार्यशिविर में भाग लिया।

(xxiv) कन्या शिक्षा के प्रकार और प्रमात्रा पहलुओं को सुधारने के लिए विभिन्न राज्यों में दस राज्यस्तरीय विचार गोष्ठियाँ आयोजित की गईं। इन विचार गोष्ठियों की सिफारिशें संबंधित राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

(xxv) प्राथमिक शिक्षा पर 10वीं राष्ट्रीय विचार गोष्ठी की सिफारिशों के अनुसरण में, 1971-72 में विभिन्न राज्यों में 12 राज्यस्तरीय विचार गोष्ठियाँ आयोजित की गईं। इन विचार गोष्ठियों की सिफारिशों पर, प्राथमिक शिक्षा पर अप्रैल, 1972 में होने वाली 11वीं राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में विचार विमर्श किया जाएगा। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, 11वीं राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में प्रयोग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य की प्रगति के कार्यशील पेपरों, आधारभूत सामग्री और समाकलित रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया।

(xxvi) पश्चिम बंगाल और बिहार के कृषि अध्यापकों के लिए क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर में फार्म युवकों के लिए 22-10-1971 से 27-10-1971 तक व्यावसायिक कार्य अनुभव पर कार्यशिविर आयोजित किया गया।

(xxvii) पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित केन्द्रीय विद्यालयों के सामाजिक ज्ञान के अध्यापकों के लिए श्रव्य-दृश्य शिक्षा पर कार्यशिविर आयोजित किया गया। भाग लेने वाले आठ व्यक्ति 7 दिनों के लिए कार्यशिविर में उपस्थित रहे और सामाजिक ज्ञान के अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न साधन बनाए। बच्चों में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए परिषद् द्वारा तैयार किए गए महात्मा गांधी इत्यादि पर विशेष किट का भी कार्यशिविर में प्रयोग किया गया।

(xxviii) संस्थागत योजना के बारे में, पूर्वी क्षेत्र के स्कूलों के मुख्याध्यापकों और शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के लिए, एक कार्यशिविर आयोजित किया

गया। लगभग 15 व्यक्तियों ने 5 दिन के लिए कार्यशिविर में भाग लिया और गुणात्मक सुधार को केन्द्रीभूत करते हुए उचित संस्थागत योजनाएँ तैयार कीं।

(xxix) माध्यमिक स्कूलों में कार्य अनुभव प्रारम्भ किए जाने की सम्भावनाओं को समन्वेपित करने के लिए, उड़ीसा-स्कूलों के मुख्याध्यापकों और अध्यापकों के लिए कार्य-अनुभव के बारे में चार दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्य-अनुभव की धारणा और उन तरीकों पर, जिनसे इसे स्कूलों में कार्यान्वित किया जा सके है, कार्य शिविर में विचार विमर्श किया गया।

(xxx) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने पूर्वी क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारियों/स्कूल-निरीक्षकों और राज्य शिक्षा संस्थानों के निदेशकों का, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के सहयोग से, 29 अक्तूबर, से 1 नवम्बर, 1971 तक क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर में एक सम्मेलन आयोजित किया। बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और नागालैण्ड से 38 व्यक्तियों ने सम्मेलन में भाग लिया। केन्द्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एशियाई शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के प्रतिनिधियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का प्रयोजन, इसमें भाग लेने वालों को स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नए विचारों और परिवर्तनों के अनुकूल बनाना था।

(xxxi) सहकारी स्कूलों के प्राचार्यों/मुख्याध्यापकों और विषय अध्यापकों का एक सम्मेलन नवम्बर, 1971 में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। पूर्वी क्षेत्र में स्कूलों के 30 प्राचार्यों/मुख्याध्यापकों और विषय-अध्यापकों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का प्रयोजन, उसमें भाग लेने वालों को पर्यवेक्षण और विद्यार्थी-अध्यापकों की पारस्परिकता के मूल्यांकन के अनुकूल बनाना था।

(xxxii) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रमों के पर्यवेक्षकों के लिए, नागपुर, पूना, बड़ोदा, ग्वालियर और इन्दौर में, सम्मेलन आयोजित किया गया।

(xxxiii) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा सहकारी विद्यालयों के मुख्याध्यापकों और अध्यापकों के लिए 24 से 26 अक्तूबर, 1971 तक एक सम्मेलन आयोजित किया गया।

(xxxiv) शिक्षा और विज्ञान संकायों के अध्यक्षों तथा पश्चिमी क्षेत्र के विज्ञान पद्धति आचार्यों का, 4 से 6 नवम्बर, 1971 तक, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल में सम्मेलन हुआ।

(xxxv) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा, 13 से 15 मार्च,

1972 तक राज्य शिक्षा संस्थान, पूना में परिषद् के क्षेत्रीय सलाहकार (भोपाल) के सहयोग से निम्नलिखित सम्मेलन/सभाएं आयोजित की गईं :—

(क) पाठ्य पुस्तक निगमों के अध्यक्षों का क्षेत्रीय सम्मेलन,

(ख) राज्य शिक्षा संस्थानों के निदेशकों का क्षेत्रीय सम्मेलन,

(ग) श्रव्य-दृश्य शिक्षा के बारे में क्षेत्रीय सम्मेलन,

(घ) अध्यापक-शिक्षा के राज्य बोर्डों के सचिवों की क्षेत्रीय सभाएँ, और

(ङ) लोक शिक्षण के निदेशकों/शिक्षा निदेशकों की क्षेत्रीय सभा।

(xxxvi) परिषद् ने पाठ्यपुस्तक उत्पादन और मूल्यांकन के बारे में सामग्री के विकास और प्रचार के अपने कार्यक्रम के अधीन रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सामान्य विज्ञान, समाजशास्त्र और द्वितीय भाषा की पुस्तकों के निर्माण और मूल्यांकन के सिद्धान्त और पद्धतियों पर ब्रोशर तैयार किए। इनके अतिरिक्त अनुपूरक पठन मूल्यांकन तंत्र भी, अपनी निर्देशिका (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में) के साथ, मुद्रित किया गया। निम्नलिखित अन्य सामग्री भी साइक्लोस्टाइल्ड कर, देश में सम्बन्धित अभिकरणों को परिचालित की गई :—

(क) पुस्तक उत्पादन में आधुनिक प्रबन्ध तकनीक के बारे में तीन प्रलेख,

(ख) पाठ्यपुस्तकों के बारे में पठनीय सामग्री से सम्बन्धित आठ प्रलेख, और

(ग) पाठ्य सामग्री के माध्यम से कुछेक अध्यापन एकक।

(xxxvii) पाठ्यपुस्तक अभिकरणों से, विभिन्न स्कूल-विषयों के पाठ्य-पुस्तक लेखकों और समीक्षकों के बारे में, सूचना एकत्र करने के लिए कदम उठाए गए। इस प्रकार प्राप्त सामग्री के आधार पर एक निर्देशिका संग्रहीत की जा रही है। समय समय पर, राज्य अभिकरणों और केन्द्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को इस संग्रह में से सम्बन्धित जानकारी की आपूर्ति द्वारा सहायता की गई।

(xxxviii) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् द्वारा गठित पाठ्य सामग्री का राष्ट्रीय केन्द्र ने देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों से पाठ्यपुस्तकें और पाठ्य सामग्री प्राप्त करने का कार्य जारी रखा। प्राप्त की गई पाठ्य पुस्तकों तथा सामग्री की सूची तैयार कर उसे केन्द्र के स्टाक में जोड़ दिया गया। केन्द्र को विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाया गया, जैसे पुस्तक-प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना, लेखकों द्वारा परामर्श किया जाना और समीक्षा के प्रयोजनों के लिए पुस्तकों की आपूर्ति करना।

(xxxix) उत्तर क्षेत्र के अध्यापक शिक्षकों और पार्षदों के लिए कक्षा में

समाजमिति के बारे में, अक्टूबर 1971 में श्रीनगर में एक कार्यशिविर आयोजित किया गया। जम्मू और कश्मीर, हरयाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों के 22 व्यक्तियों ने कार्यशिविर में भाग लिया।

(xl) राज्य मार्गदर्शन ब्यूरो के प्रधानों की सिफारिश के अनुसरण में, 1971-72 में मार्गदर्शन किट के मूलादर्श के विकास हेतु एक पाँच-दिवसीय कार्य-शिविर आयोजित किया गया। इसमें 12 राज्यों के प्रतिनिधियों और दिल्ली के 7 मार्गदर्शक कार्मकारों ने भाग लिया। कार्यशिविर की रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसमें मार्गदर्शन किट की अन्तर्वस्तु का विस्तृत विवरण होगा।

(xli) रोजगार और शिक्षा, महानिदेशालय, नई दिल्ली के सहयोग से 2 और 3 जून, 1979 को दिल्ली में व्यावसायिक मार्गदर्शन और अभिरुचि परीक्षण पर एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में इन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया:— (i) व्यावसायिक मार्गदर्शन करने से संबंधित विभिन्न अभिकरणों में सहयोग और (ii) अभिरुचि परीक्षणों के विकास के लिए विभिन्न अभिकरणों में सहयोग, प्रमुखतः अमरीकी नियोजन सेवा की परीक्षण-माला की साधारण अभिरुचि को भारतीय वातावरण में अंगीकार करना। विभिन्न राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के लोकशिक्षण निदेशालयों राज्य शिक्षा निदेशालयों के प्रतिनिधियों, नियोजन निदेशकों, शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के राज्य ब्यूरो के प्रधानों, नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधिकारियों, योजना आयोग, केन्द्रीय शिक्षा और समाज सेवा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सम्मेलन में भाग लिया।

(xlii) पत्राचार के माध्यम से परिषद् की मार्गदर्शन प्रयोगशाला ने बड़ी संख्या में व्यक्तियों को व्यावसायिक और शैक्षिक जानकारी दी।

(xliii) 'विज्ञान अध्यापन के लिए नए अधिगम, पर एक द्विदिवसीय विचार-गोष्ठी 20 और 21 अगस्त, 1971 को आयोजित की गई। विचारगोष्ठी में मैसूर के हाई स्कूलों के 22 विज्ञान-अध्यापकों ने भाग लिया। विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शन पाठ दिए गए जिनके पश्चात् भाग लेने वालों में विचार-विमर्श हुआ। कार्यक्रम का दूसरा पहलू विज्ञान अध्यापन के लिए सुधरे उपकरणों का प्रयोग करना था।

(xliv) पाठ-आयोजना में मैसूर शहर के प्राथमिक अध्यापक शिक्षकों को अनुस्थान हेतु सरकारी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर में एक कार्यशिविर आयोजित किया गया। कार्यशिविर में 72 अध्यापक शिक्षकों ने भाग लिया। पाठ रेखांकनों में आचरणात्मक निष्कर्षों के बारे में उद्देश्यों और विनिर्दिष्टाओं का वर्णन किया गया था जिन्हें अंग्रेजी, कन्नड़, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित में भाग लेने वालों ने तैयार किया था।

(xlv) कोयम्बटूर के हाई स्कूलों के कुछ प्रधानों के अनुरोध पर, कोयम्बटूर के अध्यापकों के लिए 26 से 28 अक्टूबर 1971 तक अन्वेषण द्वारा जीव-विज्ञान पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। विचार गोष्ठी में 18 अध्यापकों ने भाग लिया।

(xlvi) तुमकूर के स्कूल प्राधिकारियों के अनुरोध पर, तुमकूर के अध्यापकों के लिए 4 से 9 नवम्बर, 1971 तक जीव-विज्ञान का अध्यापन पर एक त्रि-दिवसीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई। विचार गोष्ठी में 15 अध्यापकों ने भाग लिया।

(xlvii) सालेम के स्कूल प्राधिकारियों के अनुरोध पर सालेम के अध्यापकों के लिए 9 से 11 दिसम्वर, 1971 तक जीव विज्ञान का अध्यापन पर एक विचार-गोष्ठी आयोजित की गई। विचार गोष्ठी में 43 अध्यापकों ने भाग लिया।

(xlviii) मसूर शहर के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए, संरचनात्मक अधिगम और व्याकरण अध्यापन पर विशिष्ट जोर देते हुए 'अंग्रेजी अध्यापन की आधुनिक पद्धतियां' पर पाँच-दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में 18 अध्यापकों ने भाग लिया।

(xlix) विज्ञान शिक्षा के राज्य संस्थानों के निदेशकों/सम्पर्क अधिकारियों का, बिभिन्न राज्यों में विज्ञान-शिक्षण के लिए प्रायोगिक परियोजना के, जिसमें यूनीसेफ ने सहायता प्रदान की है, कार्यान्वयन के बारे में की गई प्रगति पर विचार-विमर्श करने तथा भावी कार्यक्रम के विकास के लिए, 20 और 21 जुलाई, 1971 को, दो-दिवसीय सम्मेलन हुआ।

परिशिष्ट 18

राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के साथ सहयोग
(1971-72)

1971-72 के दौरान राज्य सरकारों तथा परिषद् के बीच सहयोग के सूचना कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

(1) विज्ञान की शिक्षा में सुधार

सभी विज्ञान-विषयों में प्राथमिक और मिडिल स्कूल के स्तर पर पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सामग्री, प्राथमिक विज्ञान एवं माध्यमिक स्कूल किट सप्लाई करने और राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को प्रयोगात्मक स्कूलों के शिक्षकों के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में सहायता देने के लिए आधार कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के रूप में सहयोग प्रदान किया गया। सभी अहिन्दी भाषी राज्यों को उनके द्वारा तैयार किए गए भाषा रूपांतरों में प्रयोग के लिए विज्ञान पाठ्यपुस्तकों के लिए चित्र भी प्रदान किए गए। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली के प्रदेशों/संघ राज्यक्षेत्रों को पाठ्यपुस्तकों के हिन्दी भाषान्तर प्रदान किए गए। वर्ष के दौरान कुल 96,5000 (प्राथमिक 16950 और माध्यमिक 79550) पाठ्यपुस्तकें प्रदान की गईं। इसके अलावा राज्यों के अनुरोध पर उन्हें अंग्रेजी में अध्यापक दर्शिकाएँ भी प्रदान की गईं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 3435 प्राइमरी विज्ञान तथा मिडिल स्कूल स्तर के लिए किट भी प्रदान किए गए। यूनीसेफ से प्राप्त आवरण और भीतर के कागज को भी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वितरित किया गया। प्रयोगशाला उपकरण राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य शिक्षा संस्थान, अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों और अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों को दिए गए। शैक्षणिक सामग्री, कागज, प्रयोगशाला उपकरण इत्यादि के वितरण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्निका (अनुबंध) में दिया हुआ है।

(2) सामाजिक विज्ञान तथा मान विकी की शिक्षा में सुधार

2.01 साधन व्यक्तियों को राज्य शैक्षिक पद्धति में पाठ्यक्रम विकास और सामाजिक तथा मानव विज्ञानों में सुधार के संबंध में प्रशिक्षित करने के लिए तीन कर्मशालाओं का—हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केरल प्रत्येक में एक-एक—आयोजन किया गया। 150 व्यक्तियों ने कर्मशालाओं में भाग लिया। हरियाणा में साधन

व्यक्तियों को मिडिल स्कूल स्तर के लिए हिन्दी, नागरिक शास्त्र, भूगोल और इतिहास पाठ्यक्रमों को सुधारने और संशोधित करने में प्रशिक्षित किया गया, हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षण प्राथमिक स्कूल स्तर के हिन्दी और सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रमों को सुधारने से संबंधित था; और केरल में हाई स्कूल स्तर के हिन्दी, संस्कृत, मलयालम, इतिहास, भूगोल नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र पाठ्यक्रमों को सुधारने के लिए प्रशिक्षण दिया गया।

2.02. परिषद् ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मिडिल स्कूल स्तर के अध्यापकों के लिए सामाजिक विज्ञान में ग्रीष्मकालीन संस्थान आयोजित करने में सहायता दी। अध्यापकों को परिषद् द्वारा प्रस्तुत सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, और नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करने में अनुस्थापित किया गया।

परिषद् की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करने के लिए दिल्ली नगर निगम के हैडमास्टरों और पर्यवेक्षक स्टाफ के लिए अभिविन्यास में उसकी सहायता की गई।

2.03. प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापक प्रशिक्षकों और राज्य शिक्षा संस्थानों के अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम के आयोजन में राज्य शिक्षा विभागों की सहायता की गई। अभिविन्यास कार्यक्रम राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, हैदराबाद में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य भाग लेने वालों को परिषद् द्वारा सामाजिक विज्ञान में विकसित सेवा-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम से अवगत कराना था ताकि राज्यों में सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में अध्यापक शिक्षा में सुधार किया जा सके।

2.04. संघ राज्यक्षेत्र नेफा के अध्यापक प्रशिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया।

(3) स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा को लागू करना

बहुत से राज्यों ने जनसंख्या शिक्षा को अपने स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की रजामन्दी भेजी है। प्रतिवेदन वर्ष में परिषद् ने हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, बिहार और राजस्थान राज्य शिक्षा विभागों को जनसंख्या शिक्षा के विचारों को वर्तमान स्कूल पाठ्यक्रमों में शामिल करने में सहायता की है।

(4) परीक्षा सुधार

परिषद् ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा साधन व्यक्तियों को विभिन्न विषयों में मूल्यांकन के लिए तैयार करने के लिए आयोजित कार्मशाला में सहयोग दिया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान को आंतरिक निर्धारण कार्यक्रम के आयोजन में भी सहायता दी गई। परिषद् ने मैसूर

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्रश्न-पत्र निर्माताओं के लिए एक कर्मशाला के आयोजन में सहायता दी। गोवा, दमन और दीव सरकार के अनुरोध पर पानाजी में अक्तूबर, 1971 में संघीय प्रशासन के शिक्षा अधिकारियों के लिए एक मूल्यांकन कर्मशाला का आयोजन किया गया। परिषद् ने विभिन्न राज्यों के मूल्यांकन कार्यक्रमों के अधिकारियों के लिए अप्रैल, 1971 में एक सेमिनार का आयोजन किया जिसमें 16 अधिकारियों ने भाग लिया।

(5) राज्यों से प्राप्त पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन

राज्य पाठ्यपुस्तक ऐजेंसियों और राज्य शिक्षा विभागों से प्राप्त पाठ्यपुस्तकों की पांडुलिपियों की परिषद् ने समीक्षा की। समीक्षा रिपोर्ट संबंधित ऐजेंसियों को भेज दी गई।

(6) पाठ्यपुस्तक निर्माण के बारे में सामग्री बाँटना

परिषद् द्वारा सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र और दूसरी भाषा की पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण और मूल्यांकन संबंधी आधारभूत सिद्धांतों और प्रक्रियाओं पर तैयार किए गए साहित्य को प्रतिवेदन वर्ष में राज्य पाठ्यपुस्तक ऐजेंसियों को भेजा गया। इसके अलावा एस० आर० ई० टी० (पूरक-पठन मूल्यांकन उपकरण) और इसकी हस्तपुस्तिका के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण छापे गए और विभिन्न राज्यों की पाठ्यपुस्तक ऐजेंसियों को बाँटे गए। निम्नलिखित सामग्रियों की प्रतिलिपियाँ तैयार की गईं और उन्हें देश की संबंधित ऐजेंसियों को भेजा गया :

(1) पुस्तक निर्माण में आधुनिक प्रबंध तकनीकों पर तीन प्रलेख,

(2) पाठ्यपुस्तक पर पठन सामग्री—आठ प्रलेख,

(3) पाठ्य सामग्री की भाँति कुछ शिक्षण इकाइयाँ।

(7) पाठ्यपुस्तक निर्माण और मूल्यांकन पर प्रशिक्षण, विस्तार और परामर्शीय सेवाएँ

मैसूर सरकार के पाठ्यपुस्तक निदेशालय को भूगोल, इतिहास और नागरिक-शास्त्र पाठ्यपुस्तकों के लेखकों तथा मूल्यांककों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम के आयोजन में परिषद् ने सहायता की। इसके अलावा पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान कर रही बहुत सी ऐजेंसियों की विचारों और सामग्रियों द्वारा सहायता की।

(8) विज्ञान क्लबों के आयोजन में अध्यापकों का अभिविन्यास

दिल्ली नगर निगम के अनुरोध पर नगर निगम के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को विज्ञान क्लबों के आयोजन में अनुस्थापित करने के लिए दो एक-एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। 77 अध्यापकों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

(9) असम के सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों के शैक्षणिक विकास के लिए उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण

लोक शिक्षा असम के निदेशालय के दो अफसरों को असम के सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों के शैक्षणिक विकास के लिए उपलब्ध सुविधाओं का एक सर्वेक्षण करने में सहायता और मार्गदर्शन किया गया।

(10) स्त्री शिक्षा में सुधार

स्त्री शिक्षा के परिमाणात्मक और गुणात्मक पहलुओं के सुधार करने के लिए प्रतिवेदन वर्ष में परिषद् ने राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों की 10 राज्य स्तरीय सेमिनारों के आयोजन में सहायता की। सेमिनारों की सिफारिशों को संबंधित राज्य कार्यान्वित कर रहे हैं।

(11) प्राथमिक स्कूलों में बरबादी और अवरोध को कम करने के लिए क्रिया कार्यक्रम विकसित करने के लिए कर्मशाला का आयोजन

दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के अनुरोध पर नगर निगम के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए प्राथमिक स्कूलों में बरबादी और अवरोध को कम करने के लिए उपयुक्त क्रिया कार्यक्रमों को विकसित करने में दिशा-निदेशन कार्यक्रम का आयोजन एक तीन-दिवसीय कर्मशाला में किया गया।

(12) स्कूल पूर्व अध्यापकों का सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण

महाराष्ट्र और गुजरात के अध्यापक शिक्षा बोर्डों को परिषद् द्वारा विकसित स्कूल-पूर्व अध्यापकों के सेवा-पूर्व और सेवा कालीन प्रशिक्षण की सामग्री को प्रयोग करने में सहायता दी गई।

(13) कार्य-अनुभव पर विकास कार्यक्रम

वर्ष 1971-72 में परिषद् ने केन्द्रीय विद्यालयों में कार्य-अनुभव कार्यक्रमों को विकसित और कार्यान्वित करने में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सहयोग दिया।

(14) अश्रेणीय शिक्षण कार्यक्रम का विकास

अहमदाबाद नगर निगम के चुने हुए अध्यापकों और पर्यवेक्षकों को चुने हुए 50 प्राथमिक स्कूलों में अश्रेणीय शिक्षण कार्यक्रम का विकास करने में मार्ग दर्शन और परामर्शीय सेवाएँ प्रदान की गई।

(15) व्यावसायिक परामर्शदाताओं का अभिविन्यास

परिषद् ने दिल्ली प्रशासन को व्यावसायिक परामर्शदाताओं के लिए 200 अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजन करने में सहायता की।

(16) पर्यवेक्षकों का कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों में प्रशिक्षण

उड़ीसा के राज्य शिक्षा विभाग के अनुरोध पर परिषद् ने जून, 1971 में पर्यवेक्षकों के लिए कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया। उड़ीसा के कृषि प्रधान विकसित जिलों से अनेक लोगों ने और बिहार के एक प्रतिनिधि ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

(17) उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना

उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशक के अनुरोध पर राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया और राज्य सरकार को पेश किया गया।

(18) मैसूर राज्य के हाई स्कूलों के स्नातक अध्यापकों के लिए उद्यान-कृषि में सेवा कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मैसूर सरकार के लोक-शिक्षा विभाग के सुझाव पर मैसूर राज्य के हाई स्कूलों के स्नातक अध्यापकों के लिए उद्यान-कृषि में दो महीने की अवधि के तीन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। सब मिलाकर 79 अध्यापकों ने इन पाठ्यक्रमों में भाग लिया। फल तथा सब्जी की बागबानी, अलंकारिक बागबानी और पात्र-कृषि में व्यावहारिक प्रशिक्षण इन पाठ्यक्रमों में दिया गया।

(19) मैसूर राज्य के प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के कला के अध्यापकों के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

मैसूर सरकार के लोक-शिक्षा विभाग के अनुरोध पर मैसूर राज्य के प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के कला के अध्यापकों के लिए दो सप्ताह के सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 21 अक्तूबर से 3 नवम्बर 1971 तक किया गया। 24 अध्यापक प्रशिक्षकों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। कला और चित्रकारी के साथ-साथ विभिन्न माध्यमों जैसे मिट्टी का काम, प्लास्टर आफ पैरिस, वैक्स इत्यादि में भी प्रशिक्षण दिया गया।

(20) मैसूर राज्य के प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए कार्य-अनुभव में सेवा कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मैसूर सरकार के लोक-शिक्षा विभाग के अनुरोध पर मैसूर राज्य के प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए दो थोड़ी अवधि के कार्य-अनुभव प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन 25 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक और 8 से 17 दिसम्बर 1971, तक किया गया। पहले और दूसरे पाठ्यक्रमों में क्रमशः 46 और 34 अध्यापक प्रशिक्षकों ने भाग लिया। भाग लेने वालों को उद्यान-कृषि कला के अंतर्गत फल तथा सब्जी की बागबानी, अलंकारिक बागबानी और पात्र-कृषि में और तकनीकी कला

के अंतर्गत लकड़ी के कार्य में धातु की चादरों के कार्य में प्रशिक्षण दिया गया ।

(21) भौतिकी में माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम का प्रारूपण

महाराष्ट्र राज्य के अध्यापक प्रशिक्षण को भौतिकी में माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम के प्रारूपण के संबंध में दसदिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने में पूना के राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान को सहायता दी गई ।

(22) कार्यक्षेत्रीय संबंधों द्वारा राज्यों के बीच सम्पर्क

राज्यों में परिषद् के कार्यक्षेत्रीय सलाहकारों ने प्रतिवेदन वर्ष के दौरान अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जितने भी अधिक से अधिक विस्तार सेवा-केन्द्रों का निरीक्षण वे कर सकते थे उतनों का किया और उनकी प्रशासनिक तथा अकादमिक समस्यों के हल के लिए अपेक्षित सहायता दी । कार्यक्षेत्रीय सलाहकारों ने राज्य अधिकारियों को परिषद् के एन० आई० ई० के विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में चालू कार्यक्रमों से अवगत कराया । विशेष रूप से उन्होंने विज्ञान शिक्षण की यूनेस्को-यूनीसेफ सहायता प्राप्त मार्गदर्शी परियोजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की सहायता की ।

प्रतिवेदन वर्ष की मुख्य समस्या राज्य सरकारों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों द्वारा विस्तार सेवा केन्द्रों का कार्यभार संभालना था । परिषद् के कार्यक्षेत्रीय सलाहकारों ने संबंधित राज्यों के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अपने निजी संबंधों के आधार पर समस्याओं को सुलझाने का भरसक प्रयत्न किया ।

इस संपर्क के मुख्य कार्यकलाप में परिषद् के कार्यक्षेत्रीय सलाहकारों द्वारा राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन था । पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और चंडीगढ़ के कार्यक्षेत्रीय सलाहकारों ने ऐसे सम्मेलनों का आयोजन किया । इन सम्मेलनों में शिक्षा मन्त्रियों, शिक्षा सचिवों, लोक-शिक्षा निदेशकों/शिक्षा निदेशकों, प्रशिक्षण कालेजों के प्रिन्सिपलों, राज्य शिक्षा संस्थानों के निदेशकों, राज्य विज्ञान शिक्षा के निदेशकों, अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों के प्रिन्सिपलों और राज्य मूल्यांकन एककों और मार्गदर्शी ब्यूरो के अध्यक्षों ने भाग लिया । ये सम्मेलन बहुत लाभदायक सिद्ध हुए और इन्होंने राज्य शिक्षा अधिकारियों को विस्तार कार्य को राज्यीय स्तर पर फिर से समझने और एन० सी० ई० आर० टी० से कार्य-संपर्क रखने में सहायता की । कार्यक्षेत्रीय सलाहकार (त्रिवेंद्रम) ने राज्य स्तरीय सम्मेलन में केरल के माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, विद्यालयों के पर्यवेक्षकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियों और कक्षाओं में उपस्थित होने वाली समस्याओं के बारे में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की भूमिका के बारे में अवगत कराया । इसके अलावा विस्तार सेवा-केन्द्रों के अवैतनिक निदेशकों और समन्वय-अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलनों का आयोजन कार्यक्षेत्रीय सलाहकारों ने अपने संबंधित राज्यों में किया ।

अनुबंध

विज्ञान शिक्षण की यूनेस्को-यूनीसेफ सहायता प्राप्त मार्गदर्शी परियोजना के अंतर्गत प्राथमिक विज्ञान और मिडिल स्कूल स्तर के किटों, पुस्तकों, कागज और प्रयोगशाला उपकरण का राज्यवार वितरण (1971-72)

क्र० सं०	राज्य	स्कूलों की संख्या		दिए गए किटों की संख्या						कुल जोड़	दी गई पुस्तकें		दिया गया कागज (रिमों में)	प्रशिक्षण संस्थाओं को दिए गए प्रयोगशाला उपकरण			
		प्रा०	मि०	प्रा०	भौ०	भौ०	जीव०	जीव०	रसा०		प्रा०	मि०		राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	राज्य शिक्षा संस्थान	अध्यापक प्रशिक्षण कालेज	अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	आंध्र प्रदेश	50	30	51	35	31	33	31	31	212	—	—	—	1	1	7	91

2.	असम	50	30	—	—	1	—	1	1	3	—	—	—	—	1	6	21
3.	बिहार	50	30	51	35	31	35	31	31	214	—	6,000	—	1	1	6	27
4.	गुजरात	50	30	50	31	31	30	31	31	204	—	—	6,748	1	1	24	63
5.	हरियाणा	50	30	51	31	31	31	31	31	206	1,500	4,200	—	1	1	5	8
6.	हिमाचल प्रदेश	25	10	26	11	12	11	12	12	84	1,500	850	—	—	—	2	2
7.	जम्मू और कश्मीर	40	30	40	40	1	40	1	1	123	—	—	—	1	1	1	6
8.	केरल	50	30	51	30	31	32	31	31	205	—	—	25,510	1	1	10	26
9.	मध्य प्रदेश	50	30	51	31	31	31	31	31	206	3,000	28,300	17,496	1	1	5	8
10.	महाराष्ट्र	45	30	46	47	45	46	45	45	274	—	—	13,898	1	1	7	19
11.	मणिपुर	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
12.	मैसूर	50	30	50	30	31	31	31	31	204	—	—	—	1	1	3	11
13.	नागालैंड	30	30	31	31	31*	31	31*	31*	186	1,650*	10,200*	—	—	—	—	3
14.	उड़ीसा	50	30	51	31	1	31	1	1	116	—	—	17,204	—	1	4	21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
15.	पंजाब	50	30	52	32	31	32	31	31	209	—	—	2,200	1	1	11	8
16.	राजस्थान	50	30	51	33	31	31	31	31	208	4,500	17,500	—	1	1	3	9
17.	तमिल नाडु	50	30	51	31	32	31	32	32	210	—	—	3,720	1	1	10	39
18.	त्रिपुरा	20	10	20	10	1	10	1	1	43	—	—	606	—	—	1	1
19.	उत्तर प्रदेश	50	30	51	32	31	31	31	31	207	2,800	12,500	14,000	1	1	9	54
20.	पश्चिमी बंगाल	—	—	51	31	1	31	1	1	116	—	—	—	1	1	1	1
21.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	20	10	1	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
22.	नेफा	13	13	13	13	—	13	—	—	39	—	—	—	—	—	—	1
23.	दिल्ली	50	सब	50	—	—	—	—	—	50	1,700	—	4,600	1	1	3	1
24.	गोवा, दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

25.	लक्कादीव	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1
26.	पाँडेचेरी	50	30	50	30	30	—	—	—	110	300	—	—	=	—	—	1
27.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	मीजोराम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*सप्लाई की जाने वाली संख्या सम्मिलित है ।

संक्षेपण :— प्रा० —प्राथमिक भौ०—भौतिकी जीव०—जीव विज्ञान

मि० —मिडिल रसा०—रसायन विज्ञान

परिशिष्ट 19

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के साथ सहयोग

(1971-72)

प्रतिवेदन वर्ष में परिषद्, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के काम से सक्रिय रूप से संबद्ध रही। ऐसे सभी कार्यों में परिषद् के योगदान की संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी जा रही है।

1. राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोर्ड

पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन और उनमें सुधार करने के लिए राष्ट्रीय और राज्यस्तर के संगठनों के कार्यों में समन्वय करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1968 में राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक बोर्ड की स्थापना की थी। प्रतिवेदन वर्ष में परिषद् के पाठ्यपुस्तक विभाग ने जिसकी रचना जून 1969 में की गई थी, इस राष्ट्रीय बोर्ड के अकादमिक सचिवालय के रूप में सेवा जारी रखी। अप्रैल 1969 और मई 1970 में क्रमशः हुई बोर्ड की पहली और दूसरी बैठकों की सिफारिशों पर अमल करने का कार्य 1971-72 में किया गया। प्रतिवेदन वर्ष में बोर्ड की कोई बैठक न हो सकी।

2. शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय से मिली पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय से मिली बहुत-सी पाठ्यपुस्तकों की, परिषद् के अधिकारियों ने विवादास्पद विषय वस्तु के संदर्भ में जाँच की। इन पुस्तकों से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्टें मंत्रालय को भेज दी गईं।

3. व्यापक शैक्षिक जिला विकास परियोजना (आई० ई० डी० डी० पी०)

परिषद् ने अभियान परियोजनाओं के ब्यौरे तैयार करने, अध्ययन तथा सर्वेक्षणों के अभिकल्प तैयार करने, जिला परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और जिला परियोजना स्टाफ को प्रशिक्षण देने में शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की तकनीकी सहायता की।

4. पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन का प्रचंड कार्यक्रम

1970-71 में शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने परिषद को यह

जिम्मेदारी सौंपी कि वह राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री का पता लगाने की दृष्टि से स्कूल पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने का एक प्रचंड कार्यक्रम चलाए। प्रतिवेदन वर्ष में निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के स्कूलों में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन किया गया :

(1) बिहार
(2) उड़ीसा
(3) पंजाब
(4) पश्चिम बंगाल
(5) दिल्ली
(6) आंध्र प्रदेश
(7) मध्य प्रदेश

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा विचार करने के लिए भेज दिया गया।

5. जिला शिक्षा अधिकारियों इत्यादि के लिए दिशा-निदेशन सम्मेलन

परिषद् ने शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के सहयोग से पूर्वी क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारियों/स्कूल निरीक्षकों और राज्य शिक्षा संस्थानों के निदेशकों के लिए एक दिशा-निदेशन सम्मेलन 29 अक्तूबर से 1 नवम्बर 1971 तक भुवनेश्वर क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित किया। बिहार, उड़ीसा, नागालैंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से 38 अधिकारियों ने भाग लिए। सम्मेलन में शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, एन० सी० ई० आर० टी०, ऐशियन इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इंडियन नेशनल साइंस एकाडमी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में परीक्षित की जा रही नूतन पद्धतियों के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान करना और इन पद्धतियों को संबंधित राज्यों में स्वीकृति/अनुकूलता के लिए ठोस कार्यक्रम सुझाना था।

6. बाल साहित्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता

बाल साहित्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता जो पहले शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती थी, वर्ष 1970-71 से कार्यान्वयन के लिए परिषद् को सौंप दी गई। 1971-72 में परिषद् द्वारा 16वीं राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए कार्यवाही की गई। इस प्रतियोगिता के लिए सब मिलाकर 225 रचनाएँ विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त हुई जिनमें से 13 को पुरस्कार के लिए चुना गया। इनमें से दो हिन्दी, एक-एक कन्नड़, बंगला, असमिया, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल, सिंधी, उड़िया, तेलुगू और मलयालम भाषाओं में थीं। प्रतिवेदन वर्ष में 17वीं प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए कार्यवाही की गई और देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर प्रतियोगिता के लिए रचनाएँ आमंत्रित की गईं। इसके अलावा बाल साहित्य के

उत्पादन की मात्रा और श्रेष्ठता पर पड़े इस योजना के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए अध्ययन किया गया। इस अध्ययन की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर इस योजना को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इसे संशोधित करने का प्रस्ताव है।

7. ग्राम प्रतिभा खोज कार्यक्रम

परिषद् ने शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय को सेकेंड्री स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशील बच्चों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना को कार्यान्वित करने में सहयोग दिया। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कक्षा 7 या 8 में से प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड से दो बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य दिन के छात्रों के लिए 500 रुपए प्रति वर्ष और मान्य होस्टलों या चुने हुए विशेष परिवारों के साथ रहने वाले छात्रों के लिए 1000 रुपए प्रति वर्ष है। छात्र द्वारा संतोषजनक उन्नति करने पर यह छात्रवृत्ति सेकेंड्री स्तर तक दो से चार वर्ष तक चालू रहेगी। इस योजना का प्रशासकीय दायित्व शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय पर है। मंत्रालय इस योजना को राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित करेगा। परिषद् को राज्यों को अकादमिक मार्गदर्शन उपलब्ध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए परिषद् में एक विशेष एकक की स्थापना का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित एकक की स्थापना होने तक परिषद् ने प्रतिवेदन वर्ष में तदर्थ प्रबंध से राज्यों का मार्गदर्शन किया। परिषद् के परीक्षा सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर तदर्थ प्रबंध किया गया था।

8. राष्ट्रीय एकता परियोजना

1970-71 में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने परिषद् को, विद्यार्थियों और अध्यापकों तथा केवल अध्यापकों के अंतर-राज्य शिविरों के आयोजन, कुछ चुने हुए स्कूलों में "हमारा भारत परियोजना" चलाने, तथा विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए विषयानुकूल उपयुक्त सामग्री तैयार करके उसका उत्पादन करने के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता पैदा करने का काम सौंपा। इस परियोजना के अधीन 1971-72 में किए गए कार्य की रिपोर्ट परिशिष्ट 7 में दी जा चुकी है।

9. जनसंख्या शिक्षा

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के कहने पर 1970-71 में परिषद् के सामाजिक विज्ञान और मानविकी विभाग में एक विशेष यूनिट स्थापित की गई थी। इस यूनिट को जनसंख्या शिक्षा पर उपयुक्त कार्यक्रम बना कर उसे स्कूल स्तर पर कार्यान्वित करने का कार्यभार सौंपा गया। यूनिट द्वारा वर्ष 1971-72 के दौरान किए गए कार्य का उल्लेख मुख्य रिपोर्ट में किया जा चुका है।

10. यूनेस्को रजत जयन्ती समारोह

नवम्बर 1971 में परिषद् ने इंडियन नेशनल कमीशन फार कोआप्रेशन विद यूनेस्को को यूनेस्को रजत जयन्ती समारोह कार्यक्रम आयोजित करने में सहयोग दिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रदर्शिनियाँ लगाना, प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा यूनेस्को के योगदान पर व्याख्यान, फिल्में दिखाना, निबंध तथा वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन, सिम्पोजियम इत्यादि कार्यक्रम शामिल थे।

परिशिष्ट 20

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (1971-72)

प्रतिवेदन वर्ष में परिषद् को 'यूनेस्को' 'यूनीसेफ' और यू० एन० डी० पी० जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सहायता मिलती रही। 'ब्रिटिश काउंसिल', 'यूसेड' जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य से भी सहायता प्राप्त हुई। परिषद् के बहुत से कर्मचारी प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य के रूप में अथवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए अथवा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए विदेश गए। बहुत से विदेशी विशेषज्ञों द्वारा परिषद् तथा इसकी संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इनमें से कुछ ने परिषद् में परामर्शदाताओं के रूप में कार्य किया जबकि शेष ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस क्षेत्र में 1971-72 में हुए क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण नीचे दिए पैराग्राफों में दिया गया है।

1. विदेशों से प्राप्त उपकरण और विशेषज्ञता

1·01. यूनेस्को-सहायता प्राप्त माध्यमिक विज्ञान शिक्षण परियोजना के अंतर्गत, 7 यूनेस्को विशेषज्ञों ने परिषद् की अनुदेशन सामग्री, उपकरण और गणित और विज्ञान में श्रव्य-दृश्य साधनों को विकसित करने में सहायता करने का कार्य जारी रखा।

1·02 यूनीसेफ-सहायता प्राप्त 'स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण' में सुधार की मार्गदर्शी परियोजना के अंतर्गत, एक यूनेस्को विशेषज्ञ ने प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रमी सामग्री विकसित करने में परिषद की सहायता करने का कार्य लगभग पूरे वर्ष जारी रखा।

1·03. कोलम्बो सहायता निधि के अंतर्गत, इंगलैंड से विज्ञान संबंधी 10 फिल्में प्राप्त की गई। इन फिल्मों की समालोचना के बाद राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अध्यापन सहायता विभाग की केन्द्रीय फिल्म लाइब्रेरी के द्वारा इनको परिचालित किया जाएगा।

2. अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाओं में परिषद् का सहयोग

परिषद् ने शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अनुसंधान परियोजना में 1971-72 में सहयोग जारी रखा। भारत सहित 20 देश

इस परियोजना में भाग ले रहे हैं । इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निवेश संबंधी विविधताओं जैसे विद्यालय का संगठन तथा ढाँचा और उसकी भौतिक सुविधाएँ, शिक्षकों की योग्यताएँ, अनुभव, अभिप्रेरणा और आचार, और विद्यार्थियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का संबन्ध तथा विद्यालय के कुछ विषयों में उनकी उपलब्धि से स्थापित करना है । प्रतिवेदन वर्ष के प्रथम अर्ध में इस परियोजना की तथ्य-सामग्री एकत्र की गई, छिद्रित की गई और अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र को भेजी गई । वर्ष के द्वितीय अर्ध में कम्प्यूटरों द्वारा तैयार आँकड़े जो अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा प्राप्त हुए, उनका अध्ययन किया गया और स्टाकहोम से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर भेजे गए ।

3. विदेशी प्रशिक्षकों के लिए परिषद् के प्रशिक्षण कार्यक्रम

3·01. यूसेड थर्ड कंट्री प्रोग्राम के अंतर्गत जो तीन अफगानी 4 महीने की अवधि के लिए परिषद् के अध्यापन सहायता विभाग में श्रव्य-दृश्य शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त करने आए थे उनका कार्यक्रम 30 जून 1971 को समाप्त हो गया। इस कार्यक्रम में फोटोग्राफी, श्रव्य-दृश्य उपकरण और ग्राफिक्स पर प्रशिक्षण दिया गया ।

3·02. यूसेड कार्यक्रम के अंतर्गत आए एक अफगानी अध्यापक प्रशिक्षक को एक महीने की अवधि के लिए जून-जुलाई 1971 में शैक्षिक फिल्म स्ट्रिपों और स्लाइडों को तैयार करने की तकनीक के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया ।

3·03. डब्लू० एच० ओ० शिक्षावृत्ति के अंतर्गत जुलाई 1971 में एक सप्ताह का अध्यापन सहायक उपकरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक इंडोनेशियाई के लिए प्रबंध किया गया । इस प्रशिक्षण में सस्ते अध्यापन सहायक उपकरण जैसे सिल्क स्क्रीन छपाई, चार्ट्स, पोस्टर्स आदि को तैयार करना भी सिखाया गया ।

3·04. प्रतिवेदन वर्ष में जो दो अफगानी सर्वश्री एम० आई० शफीक और सय्यद मुहम्मद जहीर खुशबीन, यूनेस्को शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत भारत आए, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्न विभागों, और अजमेर तथा भुवनेश्वर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

4. परिवार और शिशु कल्याण परियोजनाओं के लिए खेल उपकरणों को अंतिम रूप देने के लिए यूनीसेफ को दी गई सहायता

यूनीसेफ को परिवार और शिशु कल्याण परियोजनाओं के लिए खेल उपकरणों को अंतिम रूप देने के लिए सहायता दी गई । यह परियोजनाएँ भारत सरकार द्वारा यूनीसेफ की सहायता से चलाई जा रही हैं ।

5. यूनेस्को/यूनीसेफ को सामग्री संपूर्ति

5.01. भारत में व्यावसायिक मार्गदर्शन की पुस्तकों की विषय-सूचियाँ तैयार की गईं और यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो को भेजी गईं ।

5.02. यूनीसेफ आजकल इस खोज में लगी है कि वह सरकारी तथा गैर सरकारी ऐजेन्सियों के वर्तमान कार्यक्रमों को देखते हुए भारत में बच्चों की पूर्व-स्कूल स्थिति को सुधारने में किस प्रकार से योगदान कर सकती है। इस संबंध में यूनीसेफ के अनुरोध पर परिषद् के दो अधिकारियों ने जो स्थिति-प्रबन्ध तैयार किए वह हैं : "वालेंट्री आरगेनाइजेशंस व्हिच सर्व प्री-स्कूल चिलड्रेन इन इंडिया" और "ए क्रिटिकल रिव्यू आफ एक्जिस्टिंग फैसेलिटीज इन प्री-स्कूल टीचर ट्रेनिंग इन इंडिया"।

6. शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों तथा उच्च प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए परिषद् के अधिकारियों का विदेश गमन

6.01. डा० (श्रीमती) पैरिन एच० मेहता, अध्यक्ष, शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा आधार विभाग को 25 से 29 अक्तूबर 1971 तक एम्स्टर्डम में शैक्षिक और मूल्यांकन उपलब्धियों के लिए हुई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बैठक में भाग लेने भेजा गया।

6.02. श्री एस०एल० अहलुवालिया, अध्यक्ष, अध्यापन सहायता विभाग को 14 मई से 11 जून, 1971 तक जापान के राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान द्वारा एशिया में श्रव्य-दृश्य शिक्षण पर आयोजित शैक्षणिक कर्मशाला में भाग लेने भेजा गया।

6.03. श्री टी०एस० मेहता, इंचार्ज, सामाजिक विज्ञान तथा मानविका विभाग ने कोलम्बो योजना ब्यूरो के अन्तर्गत लंका सरकार द्वारा 21 से 30 जून, 1971 तक जनसंख्या शिक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया।

6.04. प्रो०सी०एच०के० मिश्र, रीडर, शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा आधार विभाग, (जो इस समय केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में विदेश-सेवा पर हैं) एशिया में प्रयोगात्मक परियोजना और योजनाबद्ध अनुदेशन के कार्यक्रम की मार्गदर्शी कमेटी की बैंकाक में 4 से 8 अक्तूबर 1971 तक हुई बैठक में भाग लेने भेजे गए।

6.05. प्रो०पी०के० राय, प्रिंसिपल, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली, ने यूनेस्को प्रवर्तित एशियाई अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, मनीला (फिलिपाइन्स) द्वारा बुलाई गई अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी दल की बैठक में 11 जनवरी से 20 जनवरी, 1972 तक भाग लिया।

6.06. परिषद् के निम्नलिखित अधिकारियों को ग्रैना (स्वेडन) में आई० ई०ए० द्वारा 4 जुलाई से 14 अगस्त 1971 तक पाठ्यक्रम विकास और नूतन पद्धति में उच्च प्रशिक्षण के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने भेजा गया :

(1) डा० आर० सी० दास, प्रिंसिपल, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर।

(2) श्री एन० के० सान्याल, कार्यक्षेत्रीय सलाहकार, विज्ञान शिक्षा विभाग।

(3) श्रीमती आदर्श खन्ना, रीडर, पाठ्यपुस्तक विभाग।

(4) श्री अनिल विद्यालंकार, रीडर, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग।

(5) डा० जी० एन० कौल, कार्य क्षेत्रीय सलाहकार, राष्ट्रीय शै० अ० और प्र० परिषद्।

(6) श्री एच० एस० श्रीवास्तव, रीडर, पाठ्यपुस्तक विभाग। डा० आर० एच० दवे०, अध्यक्ष, पाठ्यपुस्तक विभाग और डा० एम० सी० पंत, अध्यक्ष, विज्ञान शिक्षा विभाग ने विद्या-शाखा के सदस्य के रूप में सेमिनार में कार्य किया।

6.07. परिषद् के निम्नलिखित अधिकारी राष्ट्रमंडल अध्यापक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति के अंतर्गत उच्च अध्ययन के लिए गए :

(1) श्री आर० एन० कर्णावत, विज्ञान प्राध्यापक, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर, 20-10-1971 से 19-9-72 तक (देय छुट्टी दी गई)

(2) श्री आर० एस० कोठारी, गणित प्राध्यापक, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर, 16-9-1971 से 15-8-1972 तक (देय छुट्टी दी गई)

(3) श्री सी० एल० आनन्द, शिक्षा प्राध्यापक, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर, 17-9-1971 से अक्तूबर 1972 तक (विशेष छुट्टी दी गई)

6.08. यूनेस्को सहायता प्राप्त माध्यमिक विज्ञान शिक्षण परियोजना के अंतर्गत विज्ञान शिक्षा विभाग के सर्वश्री छोटन सिंह और पी० के० भट्टाचार्य को विदेशों में प्रशिक्षण को भेजा गया।

6.09. डा० श्रीमती बी० एस० आनन्द, प्राध्यापक, पाठ्यपुस्तक विभाग जो ब्रिटेन सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रमंडल अध्यापक प्रशिक्षण छात्रवृत्ति के अंतर्गत 1-10-1970 को उच्च अध्ययन के लिए गई थीं उन्होंने 4-7-1971 को अध्ययन पूरा कर लिया।

(7) परिषद् के वे अधिकारी जो विशेष कार्य पर विदेश गए

7.01. परिषद् में कार्यक्षेत्रीय सलाहकार डा० ए० रऊफ यूनेस्को में विदेश-सेवा पर रहे और काबुल की अध्यापक शिक्षा अकादमी में शिक्षण के नियमों के विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते रहे।

7.02. केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली में प्राध्यापक श्री एस०एस० शर्मा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विशेष निधि उपादान के अंतर्गत अफगानिस्तान में अध्यापक प्रशिक्षण में विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते हुए यूनेस्को में विदेश-सेवा पर रहे।

7.03. डा० (श्रीमती) बी० राजू, रीडर, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली, यूनेस्को में शैक्षिक योजना और प्रशासन के वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में विश्वविद्यालय कालेज, नौरोबी (कीन्या) में प्रतिनियुक्ति पर बनी रहीं।

7.04. पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अनुसंधान सहायक श्री एन० के जंगीरा सिक्किम सरकार के पैलिंग (ग्यालशिंग) के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिन्सिपल के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते रहे।

7.05. मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से संबद्ध निदर्शन बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के अध्यापक श्री सी०जी० नागराज को 5-8-1971 से एक वर्ष के लिए अध्यापक विनियम कार्यक्रम के अंतर्गत न्यू जर्सी (यू०एस०ए०) के ईस्ट आरेंज के ईस्ट आरेंज हाई स्कूल में अध्यापक कार्य के लिए देय छुट्टी दी गई।

(8) विदेशी विशेषज्ञ व सम्मानीय व्यक्ति जो परिषद् में पधारे

बहुत से विदेशी विशेषज्ञों और सम्मानीय व्यक्तियों ने 1971-72 के दौरान परिषद् का निरीक्षण किया। इन विशिष्ट व्यक्तियों के निरीक्षणों का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:

8.01. अप्रैल 1971 में इंडोनेशिया के सात प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों के एक दल ने जिनके साथ फोर्ड फाउन्डेशन स्टाफ के दो सदस्य भी थे, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अध्यापक शिक्षा विभाग का निरीक्षण किया। दर्शकों से जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया वह थे बहुद्देशीय स्कूल, निदर्शन स्कूल, और अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि।

8.02. यूनेस्को के उप-महानिदेशक श्री जान ई० फोब्स के नेतृत्व में एक यूनेस्को प्रतिनिधिमण्डल ने 17-8-1971 को परिषद् का निरीक्षण किया। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने विज्ञान शिक्षा विभाग और केन्द्रीय विज्ञान वर्कशाप का भी निरीक्षण किया। उन्होंने परिषद् द्वारा तैयार किए गए विज्ञान अध्ययन किटों और अनुदेशीय सामग्री में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने परिषद् के निदेशक, संस्थान के विभागाध्यक्षों और परिषद् में यूनेस्को सहायता प्राप्त विज्ञान शिक्षण परियोजना पर कार्य कर रहे यूनेस्को विशेषज्ञों से और एक ओर परिषद् और केन्द्रीय शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और दूसरी ओर परिषद् और राज्य सरकारों के संबंधों पर विचार-विमर्श किया।

8.03. श्री ओडुरो क्वारटेन, घाना समाचार ऐजेंसी के डायरेक्टरों के बोर्ड के अध्यक्ष, श्री डब्लू० लाइटफूट, न्यूयार्क में यूनेस्को-यूनीसेफ विशेषज्ञ और श्री फिलिप

आर० थामफोर्ड, यूनीसेफ संपर्क अधिकारी, एफ०ए०ओ०, रोम, ने जून 1971 में विज्ञान शिक्षा विभाग का निरीक्षण किया और उनको स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण की यूनीसेफ सहायता प्राप्त मार्गदर्शी परियोजना के अंतर्गत विकसित सामग्री दिखाई गई।

8.04. श्री मुहम्मद अयूब, प्रिन्सिपल, उच्चतर अध्यापक कालेज, काबुल ने जून, 1971 में परिषद् का निरीक्षण किया और विज्ञान शिक्षा विभाग और अध्यापक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया।

8.05. काबुल के प्रदेश निदेशक श्री गुल रहमान हकीम ने जून, 1971 में परिषद् द्वारा स्कूलों में परीक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए परिषद् का दौरा किया।

8.06. डा० जे० एल० हेन्डरसन, लंदन विश्वविद्यालय में इतिहास और अंतराष्ट्रीय मामलों के वरिष्ठ प्राध्यापक, ने केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, देहली का 29 जुलाई, 1971 को निरीक्षण किया और "छात्र और समाज" पर व्याख्यान दिया।

8.07. डा० होमेन्ड मी फिल्ट्स, स्वास्थ्य शिक्षा के डब्ल्यू० एच० ओ० परामर्शदाता, एन०सी० केन्द्रीय विश्वविद्यालय, डरहम, ने विज्ञान शिक्षा विभाग का 2-8-1971 को निरीक्षण किया और वे केन्द्रीय विज्ञान वर्कशाप देखने भी गए। उनकी विशेष रुचि यह जानने में थी कि स्वास्थ शिक्षा के किन संघटक भागों को परिषद् के विज्ञान कार्यक्रमों में रखा गया है।

8.08. श्री वाई के० लूले, लंदन में मित्रराष्ट्रमण्डल के सचिवालय में शिक्षा के सहायक महासचिव, परिषद् में 19 अगस्त को आए। उनको केन्द्रीय विज्ञान वर्कशाप भी दिखाई गई। उन्होंने परिषद् के निदेशक और संस्थान के विभागाध्यक्षों से विचार-विमर्श किया।

8.09. स्वेडन की संसद के दो सदस्य श्री स्टिग्लेमीर और श्रीमती सेसिलिया मेट्लीब्रांड ने परिषद् का 8 सितम्बर 1971 को निरीक्षण किया। उनको विज्ञान शिक्षा विभाग और केन्द्रीय विज्ञान वर्कशाप में भी घुमाया गया। उन्होंने परिषद् के निदेशक और संस्थान के विभागाध्यक्षों से भी विचार-विमर्श किया।

8.10. न्यूयार्क के रेन्सेलायर पोलीटेकनिक इंस्टीट्यूट में भौतिकी के प्रोफेसर प्रो० हेरी एफ० मीनर्स ने 13-9-1971 को विज्ञान शिक्षा विभाग का निरीक्षण किया और विभाग के अधिकारियों से भौतिकी में नए निदर्शन उपकरण विकसित करने पर विचार-विमर्श किया।

8.11. डा० गार्थ होवेल, अध्यक्ष, विज्ञान शिक्षा अनुभाग, ब्रिटिश काउंसिल यू० के० और डा० आर० एम० ड्रिम्मीलेन, शैक्षणिक अनुसंधान में यूनेस्को के सह-

विशेषज्ञ, एशिया में शिक्षा का क्षेत्रीय दफतर, बैंकोक, मे विज्ञान शिक्षा विभाग और केन्द्रीय विज्ञान वर्कशाप का नवम्बर 1971 में निरीक्षण किया और विभाग और वर्कशाप के अधिकारियों से परिषद् के विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में विचार-विमर्श किया ।

8.12. विज्ञान उपकरण के यूनेस्को विशेषज्ञ श्री एख विज्ञान शिक्षा विभाग और केन्द्रीय विज्ञान वर्कशाप में पधारे और विज्ञान उपकरणों को उत्पादकों से थोक में खरीदने के इरादे से विज्ञान उपकरणों और किटों का वास्तविक नमूनों से विस्तार में निरीक्षण किया ।

8.13. प्राहा (चेकोस्लोवेकिया) के चार्ल्स विश्वविद्यालय के इन्डोलाजी विभाग के अध्यक्ष डा० ओडोलेन स्मेकल ने 11-1-1972 को पाठ्यपुस्तक विभाग का निरीक्षण किया । डा० स्मेकल ने चेकोस्लोवेकिया में रहने वाले प्रौढ़ों के लिए कुछ हिन्दी की पुस्तकें तैयार की थीं । उन्होंने परिषद् द्वारा तैयार की हुई पाठ्य-पुस्तकों में दिलचस्पी दिखाई । उन्होंने पाठ्यपुस्तक विभाग के अध्यक्ष और भाषा दल से परिषद् की पुस्तकों के संबंध में विचार-विमर्श किया । उन्होंने परिषद् की पुस्तकों को उपयोगी पाया और बहुत सी सामग्री नमूने के तौर पर अपने साथ ले गए ।

8.14. श्री राबर्ट मारिस, उप-महानिदेशक, सेंटर फॉर एडुकेशनल डेवलपमेंट ओवरसीज, लंदन, ने श्री स्टैनली हॉगसन, ब्रिटिश काउंसिल में भारत के प्रतिनिधि, के साथ परिषद् का 14 फरवरी 1972 को निरीक्षण किया । श्री मारिस ने शाखा सदस्यों को सम्बोधित किया । अपने अभिभाषण में उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों में सी० ई० डी० ओ० के चालू कार्यक्रमों द्वारा पाठ्यक्रम विकास से प्राप्त अनुभवों का ब्यौरा दिया । उन्होंने इंग्लैंड में इस क्षेत्र में अपनाई जाने वाली प्रथाएँ और अपने अनुभवों का भी वर्णन किया ।

8.15. यूनेस्को-नीयर मूल्यांकन मिशन के निम्नलिखित सदस्यों ने एक मार्च 1972 को परिषद् का निरीक्षण किया :

(1) डा० गोरडन अर्विडसन, यूनेस्को रीजनल आफिस फार एडुकेशन इन एशिया, बैंकॉक ।

(2) डा० किही कोयजुमी, एन० आई० ई० आर० (नीयर) जापान का प्रतिनिधि ।

(3) डा० इराज एमान, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ साइकालोजी, इरान ।

मिशन के सदस्यों ने विज्ञान शिक्षा विभाग और केन्द्रीय विज्ञान वर्कशाप का निरीक्षण किया और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभागाध्यक्षों से बैंगकॉक में स्थापित किए जाने वाले यूनेस्को के दक्षिण-पूर्व ऐशियाई केन्द्र द्वारा निकट भविष्य में ली जाने वाली अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में विचार-विमर्श किया ।

8.16. डा० नेलसन मैक्स, डायरेक्टर आफ टोपोलॉजी फिल्म्स प्रोजेक्ट एट ई० डी० सी०, ने विज्ञान शिक्षा विभाग का निरीक्षण किया और विभाग के अधिकारियों से विज्ञान क्षेत्र में कम्प्यूटर-सजीवता के प्रयोग की साध्यता के संबंध में विचार-विमर्श किया। उन्होंने गणित पर फिल्में दिखाईं जिनमें कम्प्यूटरों का प्रयोग किया गया था।

8.17. श्री ए० ए० स्मिरनाव, रूस के उपविदेश मंत्री और श्रीमती स्मिरनाव जो रूसी-भारत सांस्कृतिक समझौते के अंतर्गत दिल्ली आए थे उन्होंने परिषद् का 8 मार्च 1972 को निरीक्षण किया। उनको विज्ञान शिक्षा विभाग में और केन्द्रीय विज्ञान वर्कशाप में भी घुमाया गया। उन्होंने परिषद के निदेशक और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभागाध्यक्षों से परिषद् के कार्यक्रमों विशेषकर यूनेस्को सहायता प्राप्त माध्यमिक विज्ञान शिक्षण परियोजना पर जिसमें रूस के यूनेस्को विशेषज्ञ कार्य कर रहे थे, के संबंध में विचार-विमर्श किया।

8.18. श्री एस० मरडे, स्थाई सचिव, शिक्षा तथा सांस्कृतिक मंत्रालय, मारीशस, ने मार्च 1972 में केन्द्रीय विज्ञान वर्कशाप का निरीक्षण किया और विज्ञान पाठ्य सामग्री विशेषकर विज्ञान किटों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने अपने देश में विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों को विकसित करने में परिषद् के सहयोग की साध्यता को भी खोजा।

(9) परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर विदेशी विशेषज्ञ

9.01. जैसा कि पहले बताया जा चुका है यूनेस्को सहायता प्राप्त माध्यमिक विज्ञान शिक्षण परियोजना के अंतर्गत सात विशेषज्ञ 1971-72 में परिषद् की सहायता करते रहे। तीन विशेषज्ञ, डा० वी० एम० गलोशिन, डा० बी० आई० बाउलिन और डा० ए० डब्लू० टोरी, प्रतिवेदन वर्ष में अपना कार्य समाप्त कर लेने पर चले गए।

9.02. डा० डाइट्रिख ब्लेनडो, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के कार्यअनुभव के विशेषज्ञ ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा विभाग में कार्य किया और अजमेर, भुवनेश्वर और मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों का निरीक्षण किया और इन महाविद्यालयों के स्टाफ से अध्यापकों के लिए कार्य-अनुभव में प्रशिक्षण के साध्यों के संबंध में विचार-विमर्श किया।

(10) विदेशों को सहायता

परिषद् के अधिकारियों का एक दल भूटान सरकार की उसके स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम और अनुदेशीय सामग्री विकसित करने में सहायता करने के लिए भेजा गया। इस उद्देश्य से अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, सामची (भूटान) में 14 से 27 फरवरी 1972 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भूटान के लगभग 60 माध्यमिक स्कूल अध्यापकों में भागा। लिय

(11) अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष, 1972

यूनेस्को ने वर्ष 1972 को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष घोषित किया है। 1971-72 के दौरान संस्थान के पाठ्यपुस्तक विभाग और परिषद् के प्रकाशन एकक ने 1972 को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष मनाने के लिए बहुत से कार्यक्रमों की योजना बनाई।

परिशिष्ट 21

प्रकाशन (1971-72)

पाठ्यपुस्तकें

1. ए टैक्स्ट बुक आफ कैमिस्ट्री फार हायर सेकेंड्री स्कूल्स पार्ट-II
2. ज्यामेट्री फार मिडिल स्कूल्स पार्ट I (पुनर्मुद्रण)
3. राष्ट्र भारती भाग I (पुनर्मुद्रण)
4. इंगलिश रीडर बुक IV (स्पेशल सीरीज)
5. एकांकी संकलन (पुनर्मुद्रण)
6. भौतिकी भाग I (पुनर्मुद्रण)
7. जीव विज्ञान भाग I (पुनर्मुद्रण)
8. चलो पाठशाला चलें (पुनर्मुद्रण)
9. काव्य के अंग (पुनर्मुद्रण)
10. स्वतन्त्र भारत—नागरिक शास्त्र पाठ्यपुस्तक कक्षा 8 के लिए
11. रसायन-विज्ञान भाग I (पुनर्मुद्रण)
12. साइंस इज डूइंग फार क्लास IV
13. भारत और संसार (पुनर्मुद्रण)
14. फिजिक्स पार्ट III (पुनर्मुद्रण)
15. सामाजिक अध्ययन भाग I (पुनर्मुद्रण)
16. बायोलाजी पार्ट I (पुनर्मुद्रण)
17. फिजिक्स पार्ट I (पुनर्मुद्रण)
18. सामाजिक अध्ययन भाग 2 (पुनर्मुद्रण)
19. स्थानीय शासन (पुनर्मुद्रण)
20. इंगलिश रीडर बुक II (स्पेशल सीरीज)
21. इंगलिश रीडर बुक IV (स्पेशल सीरीज)
22. आस्ट्रेलिया औरअमेरिका (पुनर्मुद्रण)
23. साइंस इज डूइंग फार क्लास III (पुनर्मुद्रण)
24. रानी मदन अमर (पुनर्मुद्रण)
25. आओ हम पढ़ें (पुनर्मुद्रण)
26. कहानी संकलन (पुनर्मुद्रण)

27. कैमिस्ट्री पार्ट II (पुनर्मुद्रण)
28. ज्यामेट्री पार्ट III (पुनर्मुद्रण)
29. इंगलिश रीडर फार क्लास IV (स्पेशल सीरीज)
30. एरिथमेटिक-एलजबरा पार्ट II (पुनर्मुद्रण)
31. आओ पढ़ें और खोजें (पुनर्मुद्रण)
32. बायलाजी पार्ट III (पुनर्मुद्रण)
33. आओ हम पढ़ें (पुनर्मुद्रण)
34. साइंस इज डूइंग फार क्लास IV (पुनर्मुद्रण)
35. एरिथमेटिक-एलजबरा पार्ट III (पुनर्मुद्रण)
36. माडर्न इंडिया—ए टैक्स्टबुक फार सेकेंड्री स्कूल्स
37. जीव-विज्ञान भाग II (पुनर्मुद्रण)
38. संस्कृतोदय: (पुनर्मुद्रण)
39. भौतिकी भाग III (पुनर्मुद्रण)
40. यूरोप और भारत
41. कैमिस्ट्री पार्ट I (संशोधित संस्करण)
42. आधुनिक भारत
43. अंकगणित-बीजगणित-भाग II (पुनर्मुद्रण)
44. जीव-विज्ञान 4-5
45. सोशल स्टडीज फार हायर सेकेंड्री स्कूल्स-वाल्यूम I (पुनर्मुद्रण)
46. कैमिस्ट्री फार सेकेंड्री स्कूल्स पार्ट I (पुनर्मुद्रण)
47. अफ्रीका और एशिया (पुनर्मुद्रण)
48. आवर कांस्टीट्यूशन एन्ड दि गवर्नमेंट
49. रसायन-विज्ञान भाग I (संशोधित संस्करण)
50. मैडिवल इण्डिया (पुनर्मुद्रण)
51. एन्शिएन्ट इण्डिया (पुनर्मुद्रण)
52. बायोलोजी सैक्शन 6-7 (पुनर्मुद्रण)
53. राष्ट्र-भारती भाग 1 (पुनर्मुद्रण)
54. हिन्दी व्याकरण और रचना
55. इंगलिश रीडर बुकV (जनरल सीरीज)
56. हिन्दी पुस्तक—2 (पुनर्मुद्रण)
57. हिन्दी पुस्तक—3 (पुनर्मुद्रण)
58. हिन्दी पुस्तक—5 (पुनर्मुद्रण)
59. कैमिस्ट्री पार्ट II (पुनर्मुद्रण)
60. एरिथमेटिक एलजेबरा पार्ट I (पुनर्मुद्रण)
61. आओ पढ़ें और सीखें (पुनर्मुद्रण)
62. प्रेक्टीकल ज्याग्राफी (पुनर्मुद्रण)
63. ज्यामेट्री पार्ट II (पुनर्मुद्रण)

64. बायलोजी फार सेकेंड्री स्कूल्स-सैक्शन 2 (पुनर्मुद्रण)
65. बायोलोजी फार सेकेण्ड्री स्कूल्स-सैक्शन 3 (पुनर्मुद्रण)
66. प्राचीन भारत (पुनर्मुद्रण)
67. भौतिकी भाग II (पुनर्मुद्रण)

अध्यापक दर्शिकाएँ और अभ्यास पुस्तकें

68. टीचर्स गाइड फार ज्यामेट्री टैक्स्ट बुक 2 फार क्लास 6 (स्टडी ग्रुप)
69. टीचर्स गाइड फार इन्साइट इनटू मैथमेटिक्स
70. टीचर्स मैन्यूल फार फिजिक्स पार्ट II
71. अभ्यास पुस्तिका हिन्दी प्राइमर (पुनर्मुद्रण)
72. अभ्यास पुस्तिका हिन्दी रीडर I (पुनर्मुद्रण)
73. वर्कबुक टू इंगलिश रीडर फार क्लास 6
74. विज्ञान आओ करके सीखें अध्यापक दर्शिक क्लास 4
75. टीचर्स गाइड फार इंगलिश रीडर फार क्लास 9 (स्पेशल सीरीज) पुनर्मुद्रण)
76. वर्कबुक फार इंगलिश रीडर बुक 2 (स्पेशल सीरीज)
77. टीचर्स गाइड फार साइंस इज डूइंग फार क्लास 4
78. सामान्य विज्ञान भाग II—अध्यापकों के लिए प्रयोग पुस्तिका
79. टीचर्स गाइड फार आवर कन्ट्री इण्डिया पार्ट I
80. टीचर्स गाइड फार आवर कन्ट्री इण्डिया पार्ट II
81. अध्यापक दर्शिका हमारा देश भारत भाग II
82. वर्कबुक फार लेट्स लर्न इंगलिश बुक 1 (स्पेशल सीरीज) (पुनर्मुद्रण)
83. हिन्दी रीडर 2 कक्षा 2 के लिए अभ्यास पुस्तिका

पूरक पठन सामग्री

84. संत तुकाराम (हिन्दी)
85. स्वामी दयानन्द सरस्वती
86. बैंकिंग की मनोहारिता
87. भारत की कथाएँ (पुनर्मुद्रण)
88. बहुरूपी गाँधी (हिन्दी)
89. दि रोमान्स आफ ट्राँसपोर्ट
90. दि कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया फार दि यंग रीडर्स
91. आवर एग्रीकल्चर
92. महाकवि कालिदास (हिन्दी)
93. श्री अरविन्द (हिन्दी)
94. लखनऊ रेजीडेन्सी का घेरा
95. ईश्वर चन्द्र विद्यासागर (इंगलिश)
96. लाल बहादुर शास्त्री (हिन्दी)

97. गौतम बुद्ध (हिन्दी)
98. अन्तरिक्ष में हमारी पृथ्वी

अन्य प्रकाशन

99. वेस्टेज एन्ड स्टेगनेशन एट दि प्राइमरी लेविल—ए हैण्डबुक फार सुपरवाइजर्स
100. सप्लीमेंट्री रीडर्स इवेलुएशन टूल (हिन्दी)
101. सप्लीमेंट्री रीडर्स इवेलुएशन टूल
102. मैनुअल आफ इंसट्रक्शन्स फार सप्लीमेंट्री रीडर्स इवेलुएशन टूल
103. मैनुअल आफ इंस्ट्रक्शंस फार सप्लीमेंट्री रीडर्स इवेलुएशन टूल (हिन्दी)
104. रूल्स आफ दि एन० सी० ई० आर० टी०
105. रिपोर्ट आफ दि कमेटी टू इवाल्व माडेल सिलेबाइ फार एलीमेंट्री टीचर एजुकेशन
106. रिपोर्ट आफ दि एजुकेशन कमीशन-वाल्यूम 4
107. दि टीचर स्पीक्स-वाल्यूम 7
108. कैटालाग आफ फिल्म्स इन्डैक्स-वाल्यूम 1
109. एन एक्सपेरीमेंट इन कान्स्टीट्यूशन एजुकेशन फार स्कूल लीवर्स आफ्टर दि कम्पलसरी एडुकेशन एज लिमिट आफ एलेवन
110. स्कूल सिचुएशनल विहेवियर्स एन्ड रेटिंग स्केल्स फार एससिंग परसनालिटी ट्रेट्स आफ प्राइमरी स्कूल प्यूपिल्स
111. सिलेबस फार इंगलिश रीडर्स (स्पेशल सीरीज) पुनर्मुद्रण)
112. सिलेबस फार इंगलिश रीडर्स (जनरल सीरीज) (पुनर्मुद्रण)
113. आइडेन्टीफिकेशन आफ एजुकेशनल प्राबलम्स आफ सौरा आफ उड़ीसा
114. डेवलपमेंटल नीड्स आफ दि ट्राइबल पीपिल
115. करैन्ट प्राबलम्स इन एजुकेशन—यूथ सर्विसेज
116. करैन्ट प्राबलम्स इन एजुकेशन—ए स्कूल साइंस प्रोजेक्ट आफ इण्डिया
117. करैन्ट प्राबलम्स इन एजुकेशन—पापुलेशन एजुकेशन
118. पापुलेशन एजुकेशन—ए ड्राफ्ट सिलेबस
119. एन इन्टेग्रेटड एण्ड कम्परेटिव स्टडी आफ ए सलैक्टेड ट्राइब
120. कम्युनिटी लिविंग इन कंटीगुअस एरियाज
121. प्लग प्वाइंट्स फार पापुलेशन एजुकेशन इन स्कूल करीकुलम
122. यूनेस्को इन ट्वन्टीफाइव इयर्स
123. केटेलाग आफ एन० सी० ई० आर० टी० टैक्स्टबुक्स
124. ए चिलड्रेंस साइंस इनजेक्शन प्रोग्राम
125. मैगनीट्यूड आफ इलिट्रेसी
126. सिम्बल्स आफ यूनिटी एण्ड फ्रीडम
127. स्टूडेंट्स होम एट काम्पटी

128. व्हाई इंडिया लिव्स
129. रिटायरमेंट बैनेफिट्स फार दि एम्प्लाईज ऑफ दि एन० सी० ई० आर० टी०
130. सर्वे आफ स्कूल टैक्स्टबुक्स इन इंडिया
131. एजुकेशनल इवेलुएशन एण्ड एसेस्मेंट
132. एजुकेशन एण्ड एकोनामिक कंडीशन एण्ड एम्पलायमेंट पोजीशन आफ एटीन ट्राइब्स
133. टीचिंग यूनिट्स फॉर मिडिल स्कूल्स इन ज्याग्रफी-वाल्यूम 3
134. मेजरमेंट आफ एजुकेशनल वेस्टेज
135. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की नियमावली
136. ए स्कूल साइंस प्रोजेक्ट आफ इंडिया
137. टीचिंग यूनिट्स इन सिविक्स फॉर मिडिल स्टेज वाल्यूम I
138. टीचिंग यूनिट्स इन सिविक्स फॉर मिडिल स्टेज वाल्यूम II
139. फोल्डर आन सेमिनार रीडिंग्स
140. टैक्नोलाजी फॉर एजुकेशन (हिन्दी)
141. फोल्डर आन एक्सपेरीमेंटल प्रोजैक्ट्स
142. रूल्स एण्ड रेगुलेशन आफ दि एन० सी० ई० आर० टी०
143. रिपोर्ट आफ दि एजुकेशन कमीशन-आम्नीबस वाल्यूम
144. आड्यो-विजुअल ट्रेनिंग मटेरियल्स—ए सोर्स गाइड
145. रिपोर्ट आफ दि कमेटी आन एक्जामिनेशंस
146. मैमोरेंडम आफ एसोसिएशन आफ एन० सी० ई० आर० टी० (पुनर्मुद्रण)
147. ए बिब्लियूग्राफी आन पापुलेशन एजुकेशन
148. हमारा जिस्म (उर्दू)
149. एन० सी० ई० आर० टी० रिसर्च ग्रांट स्कीम्स
150. करैंट प्राब्लम्स इन एजुकेशन सीरीज—यूथ सर्विसेस (पुनर्मुद्रण)
151. एन० सी० ई० आर० टी० इन दि सर्विस आफ नेशंस चिल्ड्रेन
152. दि क्राइसिस आफ 1971
153. करैंट प्राबलम्स इन एजुकेशन सीरीज—प्री-स्कूल एजुकेशन
154. करैंट प्राब्लम्स इन एजुकेशन सीरीज—ए स्कूल साइंस प्रोजेक्ट फॉर इण्डिया (पुनर्मुद्रण)
155. करैंट प्राब्लम्स इन एजुकेशन सीरीज—टेक्नोलाजी फार एजुकेशन (पुनर्मुद्रण)
156. एन० सी० ई० आर० टी० पब्लीसिटी फोल्डर्स
157. नेशनल इमरजेंसी एण्ड स्कूल प्रोग्राम्स
158. वेस्टेज एण्ड स्टेगनेशन इन प्राइमरी एण्ड मिडिल स्कूल्स (पुनर्मुद्रण)

159. लोकतन्त्र और स्वाधीनता की रक्षा

160. देश भक्त तेरे रूप अनेक

पत्र-पत्रिकाएँ

1. एन० आई० ई० जर्नल—जनवरी, मार्च, मई, जुलाई 1971
2. स्कूल साइंस—दिसम्बर, 1970, मार्च 1971
3. एन० आई० ई० न्युजलेटर—मार्च, जून 1971
4. इंडियन एजुकेशनल रिव्यू—जुलाई 1971

अनुबंध

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिन्होंने परिषद् की पाठ्यपुस्तकों की सिफारिश की है या उन्हें निर्धारित किया है।

क्र.सं.	शीर्षक	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिन्होंने सिफारिश की है	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिन्होंने निर्धारित की है
1	2	3	4

पाठ्यपुस्तकें (अंग्रेजी संस्करण)

	सामान्य विज्ञान		
1.	जनरल साइंस फॉर यू : ए टैक्स्टबुक फॉर सेकेंड्री स्कूल्स		पुस्तक राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को उनके अनुमोदन/टिप्पणी के लिए भेज दी गई है।
2.	साइंस इज डूइंग—ए टैक्स्टबुक फॉर क्लास 4		केन्द्रीय विद्यालय संगठन
3.	साइंज इज डुइंग : ए टैक्स्ट-बुक फार क्लास 4		—यथोपरि—
	जीव-विज्ञान		
4.	बायलोजी: साइंस फार मिडिल स्कूल्स पार्ट I फार क्लास 4	आंध्र प्रदेश, गुजरात	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मणिपुर (मणिपुरी भाषा में अनुवाद हो रहा है), जम्मू और कश्मीर (भाग 1 उर्दू में अनूदित)
5.	बायलोजी: साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट II फॉर क्लास 7		
6.	बायलोजी: साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट III फॉर क्लास 8		केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मणिपुर (मणिपुरी भाषा में अनुवाद हो रहा है)

1	2	3	4
	7. बायलोजी: ए टैक्स्टबुक फॉर हायर सैकेण्ड्री स्कूल्स सैक्शन 1	आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, नागालैंड, पंजाब, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गोवा, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा, केन्द्रीय विद्यालय संगठन
	8. बायलोजी: ए टैक्स्टबुक फॉर हायर सैकेंड्री स्कूल्स सैक्शन 2 9. बायलोजी: ए टैक्स्टबुक फॉर हायर सैकेंड्री स्कूल्स सैक्शन 3 10. बायलोजी: ए टैक्स्टबुक फॉर हायर सैकेंड्री स्कूल्स सैक्शन 4-5 11. बायलोजी: ए टैक्स्टबुक फॉर हायर सैकेंड्री स्कूल्स सैक्शन 6-7	आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश	
	रसायन-विज्ञान		
	12. कैमिस्ट्री: साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट 1 फॉर क्लास 7 13. कैमिस्ट्री: साइंस फॉर मिडिल स्कूल्स पार्ट 2 फॉर क्लास 8	आंध्र प्रदेश, (अनूकूलित तथा तेलुगु में अनूदित) गुजरात	मणिपुर (मणिपुरी भाषा में अनुवाद हो रहा है), केन्द्रीय विद्यालय संगठन
	14. कैमिस्ट्री: साइंस फॉर सैकेंड्री स्कूल्स पार्ट 1		पुस्तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अनुमोदन/टिप्पणी के लिए भेजी गई है

1	2	3	4
	भौतिकी		
15.	फिजिक्स: साइंस फार मिडिल स्कूल्स पार्ट1 फार क्लास 6	आंध्र प्रदेश, गुजरात	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मणिपुर (मणिपुरी भाषा में अनुवाद हो रहा है) जम्मू और कश्मीर (उर्दू में अनूदित)
16.	फिजिक्स: साइंस फार मिडिल स्कूल्स पार्ट2 फार क्लास 7	आंध्र प्रदेश, गुजरात	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मणिपुर (मणिपुरी भाषा में अनुवाद हो रहा है)
17.	फिजिक्स: साइंस फार मिडिल स्कूल्स पार्ट 3 फार क्लास 8		—यथोपरि—
18.	फिजिक्स: साइंस टैक्स्टबुक फार हायर सैकेंडी स्कूल्स पार्ट 1	मैसूर, लक्कादीव, केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, राजस्थान	
	मैथेमेटिक्स		
19.	अरिथमेटिक-अल्जबरा: मैथेमेटिक्स फार मिडिल स्कूल्स पार्ट 1 फार क्लास 6	आंध्र प्रदेश	केन्द्रीय विद्यालय संगठन
20.	अरिथमैटिक-एल्जबरा: मैथेमेटिक्स फार मिडिल स्कूल्स पार्ट 2 फार क्लास 7	—	—यथोपरि—
21.	अरिथमैटिक-अल्जबरा: मैथेमेटिक्स फार मिडिल स्कूल्स पार्ट 3 फार क्लास 8		केन्द्रीय विद्यालय संगठन
22.	ज्योमेट्री: मैथेमेटिक्स फार मिडिल स्कूल्स पार्ट 1 फार क्लास 6	आंध्र प्रदेश	—यथोपरि—

1	2	3	4
23.	ज्योमेट्री: मैथेमेटिक्स फार मिडिल स्कूल्स पार्ट 2 फार क्लास 7	—	—यथोपरि—
24.	ज्योमेट्री: मैथेमेटिक्स फार मिडिल स्कूल्स पार्ट 3 फार क्लास 8	आंध्र प्रदेश	केन्द्रीय विद्यालय संगठन
25.	अलजबरा: ए टैक्स्टबुक फार सेकेंड्री स्कूल्स पार्ट 1	केरल, आंध्र प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, तमिलनाडु, राजस्थान	नागालैंड, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मणिपुर, केन्द्रीय विद्यालय संगठन
26.	अलजबरा: ए टैक्स्टबुक फार सेकेंड्री स्कूल्स पार्ट 2		
27.	एलीमेंट्स आफ प्राबेब्लिटी —ए टैक्स्टबुक फार सेकेंडरी स्कूल्स	केरल, मैसूर, गोवा, दमन और दीव, राजस्थान, पांडीचेरी	
28.	इनसाइट इंटू मैथेमेटिक्स बुक 1 फार क्लास 1		बिहार (हिन्दी अनुवाद), जम्मू और कश्मीर (उर्दू अनुवाद), केन्द्रीय विद्यालय संगठन
29.	इनसाइट इंटू मैथेमेटिक्स बुक 2 फार क्लास 2		केन्द्रीय विद्यालय संगठन
	टैकनालोजी		
30.	इंजीनियरिंग ड्राइंग: ए टैक्स्टबुक फार टैक्नीकल स्कूल्स	तमिलनाडु, केरल (मलयालम भाषा में अनुवाद हो रहा है) मैसूर, पांडीचेरी, उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर

1	2	3	4
31.	एलीमैंट्स ग्राफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग : ए टैक्स्टबुक फार टैक्नीकल स्कूल्स	गुजरात, ग्रांध्र प्रदेश, दादरा ग्रौर नगर हवेली, मैसूर, तमिल नाडु, केरल (मलयालय भाषा में ग्रनुवाद हो रहा है)	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश
32.	एलीमैंट्स ग्राफ मकैनीकल इंजीनियरिंग : ए टैक्स्टबुक फार टैक्नीकल स्कूल्स	ग्रांध्र प्रदेश, मैसूर, केरल तमिलनाडु	
33.	वर्कशाप प्रेक्टिस: ए टैक्स्टबुक फार टैक्नीकल स्कूल्स पार्ट 1	ग्रांध्र प्रदेश, मैसूर, गुजरात, केरल तमिलनाडु	
34.	वर्कशाप प्रेक्टिस: ए टैक्स्टबुक फार टैक्नीकल स्कूल्स पार्ट 2	गोवा, दमन और दीव, पांडीचेरी, चंडीगढ़, दादरा ग्रौर नगर हवेली, पंजाब	
35.	रीडिंग ब्लू प्रिंट्स एंड स्केचिंग: ए टैक्स्टबुक फार टैक्नीकल एंड वोकेशनल स्कूल्स	पुस्तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके ग्रनुमोदन टिप्पणी के लिए भेज दी गई है	
	सामाजिक ग्रध्ययन		
36.	ग्रवर कंट्री इंडिया : बुक 1 फार क्लास 3	जम्मू ग्रौर कश्मीर, मध्य प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मैसूर, ग्रांध्र प्रदेश ।	मणिपुर (मणिपुरी भाषा में ग्रनुवाद हो रहा है), केन्द्रीय विद्यालय संगठन
37.	ग्रवर कंट्री इंडिया: बुक 2 फार क्लास 4	महाराष्ट्र, गोवा, दमन ग्रौर दीव, त्रिपुरा, मैसूर केरल, जम्मू ग्रौर कश्मीर, मध्यप्रदेश, ग्रांध्र प्रदेश	मणिपुर (मणिपुरी भाषा में ग्रनुवाद हो रहा है), केन्द्रीय विद्यालय संगठन
38.	इंडिया एंड दि वर्ल्ड: बुक 3 फार क्लास 4		

1	2	3	4
39.	लोकल गवर्नमैंट: ए टैक्स्टबुक फार सिविक्स फार मिडिल स्कूल फार क्लास 4	पुस्तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनके अनुमोदन/टिप्पणी के लिए भेजी जा रही है	
40.	आवर कांस्टीट्यूशन एंड दि गवर्नमैंट फार क्लास 7		
41.	सोशल स्टडीज: ए टैक्स्ट-बुक फार हायर सैकेंडरी स्कूल-वाल्यूम 1		केन्द्रीय विद्यालय संगठन
	भूगोल		
42.	प्रैक्टीकल ज्योग्रफी: ए टैक्स्टबुक फार सैकेंडरी स्कूल	मैसूर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, पांडीचेरी, गुजरात दादरा और नगर हवेली	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मणिपुर, मद्रास यूनीवर्सिटी (फार पी० यू० सी०) केरल (मलयालय में अनुवाद हो रहा है) हिमाचल प्रदेश, केन्द्रीय विद्यालय संगठन
43.	एकोनामिक ज्योग्रफी: ए टैक्स्टबुक फार सैकेंड्री स्कूल्स	मैसूर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडीचेरी, राजस्थान, लक्कादीव	केन्द्रीय विद्यालय संगठन मणिपुर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल (मलयालम भाषा में अनुवाद हो रहा है) अंडमान निकोबार द्वीपसमूह
44.	फिजीकल ज्योग्रफी: ए टैक्स्टबुक फार सैकेंड्री स्कूल	तमिलनाडु, गोआ, दमन और दीव, केरल	मैसूर विश्वविद्यालय (कन्नड़ में अनुवाद हो रहा है), केरल (मलयालम भाषा में अनुवाद हो रहा है), केन्द्रीय विद्यालय संगठन

1	2	3	4
45.	अफ्रीका एंड एशिया: ए ज्योग्रफी टैक्स्टबुक फार मिडिल स्कूल्स पार्ट 1 फार क्लास 6	आंध्र प्रदेश	
46.	आस्ट्रेलिया एंड एमेरिकाज: ए टैक्स्टबुक फार मिडिल स्कूल्स फार क्लास 7	यह पुस्तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को उनके अनुमोदन/टिप्पणी के लिए भेज दी गई है	
	हिस्ट्री		
47.	एन्शिएंट इंडिया: ए टैक्स्टबुक आफ हिस्ट्री फार मिडिल स्कूल्स फार क्लास 4	मैसूर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु	मणिपुर (मणिपुरी में अनुवाद हो रहा है), लक्कादीव
48.	मैडिवल इंडिया: ए टैक्स्टबुक आफ हिस्ट्री फार मिडिल स्कूल्स फार क्लास 7	आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, केरल	मणिपुर (मणिपुरी में अनुवाद हो रहा है)
	कामर्स		
49.	एलीमैंट्स आफ बुक कीपिंग एंड अकाउन्टैंसी: ए टैक्स्टबुक क्लासेज 9-11		केन्द्रीय विद्यालय संगठन, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
50.	कामर्शल एंड एकोनामिक ज्योग्रफी: ए टैक्स्टबुक फार सैकेंड्री स्कूल्स	आंध्र प्रदेश, केरल	
	इंगलिश (स्पेशल सीरीज)		
51.	लैट्स लर्न इंगलिश बुक 1 फार क्लास 3		अरुणाचल प्रदेश, केन्द्रीय विद्यालय संगठन

1	2	3	4
52.	लैट्स लर्न इंगलिश बुक 2 फार क्लास 4		केन्द्रीय विद्यालय संगठन
53.	इंगलिश रीडर बुक 1 फार क्लास 4		—यथोपरि—
54.	इंगलिश रीडर बुक 2 फार क्लास 4		—यथोपरि—
55.	इंगलिश रीडर बुक 4 फार क्लास 9		—यथोपरि—
56.	इंगलिश रीडर बुक 4 फार क्लास 9		—यथोपरि—
	(जनरल सीरीज)		
57.	इंगलिश रीडर बुक 1 फार क्लास 6		बिहार, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र बोर्ड
58.	इंगलिश रीडर बुक 4 फार क्लास 9		महाराष्ट्र बोर्ड, पंजाब बोर्ड, अरुणाचल प्रदेश
59.	इंगलिश रीडर बुक 5 फार क्लास 10		गुरु नानक यूनीवर्सिटी फार पी०यू० सी०
	पाठ्यपुस्तकें (हिन्दी संस्करण)		
	जीव-विज्ञान		
60.	जीव-विज्ञान : मिडिल स्कूलों के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भाग 1 कक्षा 6 के लिए	आंध्र प्रदेश, गुजरात	दिल्ली प्रशासन
61.	जीव-विज्ञान : मिडिल स्कूलों के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भाग 2 कक्षा 7 के लिए		—यथोपरि—

1	2	3	4
62.	जीव-विज्ञान : मिडिल स्कूलों के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भाग 3 कक्षा 8 के लिए		—यथोपरि—
63.	जीव-विज्ञान : माध्यमिक स्कूलों के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भाग 1	आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, पंजाब, गोवा, दमन, दीव, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश
64.	जीव-विज्ञान : माध्यमिक स्कूलों के लिए विज्ञान की एक पाठ्य-पुस्तक भाग 2	—यथोपरि—	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश
65.	जीव-विज्ञान : मिडिल स्कूलों के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भाग 3		केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
66.	जीव-विज्ञान : माध्यमिक स्कूलों के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भाग 4-5		—यथोपरि—
	रसायन-विज्ञान		
67.	रसायन-विज्ञान : माध्यमिक स्कूलों के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भाग 1 कक्षा 7 के लिए	गुजरात, आंध्र प्रदेश (तेलुगु में अनूदित तथा अनुकूलित)	दिल्ली प्रशासन
68.	रसायन-विज्ञान : मिडिल स्कूलों के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भाग 2 कक्षा 8 के लिए		दिल्ली प्रशासन

1	2	3	4
69.	भौतिकी : मिडिल स्कूलों के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भाग 1 कक्षा 6 के लिए	आंध्र प्रदेश	दिल्ली प्रशासन
70.	भौतिकी : मिडिल स्कूलों के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भाग 2 कक्षा 7 के लिए	आंध्र प्रदेश, गुजरात	दिल्ली प्रशासन
71.	भौतिकी : मिडिल स्कूलों के लिए विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भाग 3 कक्षा 8 के लिए		दिल्ली प्रशासन
	गणित		
72.	अंकगणित-बीजगणित : मिडिल स्कूलों के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक भाग 1 कक्षा 6 के लिए	आंध्र प्रदेश	दिल्ली प्रशासन
73.	अंकगणित-बीजगणित : गणित की पाठ्यपुस्तक भाग 2 कक्षा 7 के लिए		दिल्ली प्रशासन
74.	अंकगणित-बीजगणित : मिडिल स्कूलों के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक भाग 3 कक्षा 8 के लिए		दिल्ली प्रशासन
75.	रेखागणित : मिडिल स्कूलों के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक भाग 1 कक्षा 6 के लिए	आंध्र प्रदेश	दिल्ली प्रशासन

1	2	3	4
76.	रेखागणित : मिडिल स्कूलों के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक भाग 2 कक्षा 7 के लिए		दिल्ली प्रशासन
77.	रेखागणित : मिडिल स्कूलों के लिए गणित की पाठ्य-पुस्तक भाग 3 कक्षा 8 के लिए		दिल्ली प्रशासन
	सामाजिक अध्ययन		
78.	हमारी दिल्ली कक्षा 3 के लिए	जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश	दिल्ली प्रशासन, बिहार, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह
79.	हमारा देश भारत कक्षा 4 के लिए	—यथोपरि—	दिल्ली प्रशासन, बिहार, हरियाणा, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
80.	भारत और संसार कक्षा 5 के लिए		केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली प्रशासन,
81.	सामाजिक अध्ययन भाग 1 कक्षा 4 के लिए		बिहार, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह केन्द्रीय विद्यालय संगठन
82.	सामाजिक अध्ययन भाग 2 कक्षा 5 के लिए		केन्द्रीय विद्यालय संगठन
83.	स्थानीय शासन : मिडिल स्कूलों के लिए नागरिक-		बिहार, दिल्ली प्रशासन, केन्द्रीय विद्यालय संगठन

1	2	3	4
	शास्त्र की पाठ्य-पुस्तक कक्षा 6 के लिए		
84.	शासन और संविधान : मिडिल स्कूलों के लिए नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक कक्षा 7 के लिए		दिल्ली प्रशासन, केन्द्रीय विद्यालय संगठन
85.	स्वतंत्र भारत : मिडिल स्कूलों के लिए नागरिक शास्त्र की पाठ्य-पुस्तक कक्षा 8 के लिए		—यथोपरि—
	भूगोल		
86.	अफ्रीका और एशिया : मिडिल स्कूलों के लिए भूगोल की पाठ्य-पुस्तक कक्षा 6 के लिए		—यथोपरि—
87.	आस्ट्रेलिया व उत्तर दक्षिण अमरीका : मिडिल स्कूलों के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक कक्षा 7 के लिए		दिल्ली प्रशासन, केन्द्रीय विद्यालय संगठन
88.	यूरोप और भारत : मिडिल स्कूलों के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक कक्षा 8		—यथोपरि—

1	2	3	4
	के लिए		
	इतिहास		
89.	प्राचीन भारत : मिडिल स्कूलों के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 के लिए	मैसूर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु	दिल्ली प्रशासन, बिहार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन
90.	मध्यकालीन भारत : मिडिल स्कूलों के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक कक्षा 7 के लिए		—यथोपरि—
91.	आधुनिक भारत : मिडिल स्कूलों के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक कक्षा 8 के लिए		—यथोपरि—
	हिन्दी		
92.	रानी मदन अमर : हिन्दी प्रवेशिका	मैसूर	बिहार, दिल्ली प्रशासन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्कादीव, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, अरूणाचल प्रदेश (कक्षा 3 के लिए)
93.	चलो पाठशाला चलें: हिन्दी रीडर कक्षा 1 के लिए	मैसूर	दिल्ली प्रशासन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरूणाचल प्रदेश (कक्षा 4 के लिए)
94.	आओ हम पढ़ें : हिन्दी रीडर कक्षा 2 के लिए	आंध्र प्रदेश, मैसूर	दिल्ली प्रशासन, बिहार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, अरूणा-

1	2	3	4
			चल प्रदेश (कक्षा 5 के लिए)
95.	आओ पढ़ें और समझें: हिन्दी रीडर कक्षा 3 के लिए	आंध्र प्रदेश, मैसूर, गोवा, दमन एवं दीव	दिल्ली प्रशासन, बिहार, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, अरुणाचल प्रदेश (कक्षा 6 के लिए)
96.	आओ पढ़ें और सीखें : हिन्दी रीडर कक्षा 4 के लिए	मैसूर, जम्मू तथा कश्मीर	दिल्ली प्रशासन, बिहार अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, अरुणाचल प्रदेश (कक्षा 7 के लिए)
97.	आओ पढ़ें और खोजें: हिन्दी रीडर कक्षा 5 के लिए	केरल, मैसूर	दिल्ली प्रशासन, बिहार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश (कक्षा 8 के लिए)
98.	राष्ट्र भारती भाग 1 : हिन्दी रीडर कक्षा 6 के लिए	आंध्र प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, गुजरात	दिल्ली प्रशासन, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, बिहार
99.	राष्ट्र भारती भाग 2 : हिन्दी रीडर कक्षा 7 के लिए	मैसूर, गोवा, दमन और दीव	दिल्ली प्रशासन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह बिहार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन
100.	राष्ट्र भारती भाग 3 : हिन्दी रीडर कक्षा 8 के लिए	मैसूर	दिल्ली प्रशासन, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन
101.	काव्य संकलन : माध्यमिक स्कूलों के लिए एक पाठ्य-	पंजाब	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आंध्र प्रदेश,

1	2	3	4
	पुस्तक		पश्चिम बंगाल, केन्द्रीय विद्यालय संगठन
102.	गद्य-संकलन: माध्यमिक स्कूलों के लिए एक पाठ्यपुस्तक	पंजाब	आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल, पंजाब विश्वविद्यालय (चार निबंध अपनी प्रकाशित पुस्तक के भी शामिल कर लिए हैं) केन्द्रीय विद्यालय संगठन
103.	एकांकी संकलन : माध्यमिक स्कूलों के लिए एक पाठ्यपुस्तक	पंजाब	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश
104.	काव्य के अंग : माध्यमिक स्कूलों के लिए एक पाठ्यपुस्तक		मध्य प्रदेश, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन
105.	जीवनी संकलन : माध्यमिक स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तक		हरियाणा, हिमाचल प्रदेश
106.	हिन्दी साहित्य का इतिहास: माध्यमिक स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तक		पंजाब बोर्ड
107.	कहानी-संकलन : माध्यमिक स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तक		हरियाणा, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन
108.	काव्य-संकलन गद्य-संकलन	संयुक्त संस्करण	बड़ौदा विश्वविद्यालय

109.	हिन्दी व्याकरण और रचना		यह पुस्तक राज्य/संघ क्षेत्रों को उनकी टिप्पणी/अनुमोदनार्थ भेजी जा रही है ।
110.	संस्कृतोदय : माध्य-मिक स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तक	केरल, तमिलनाडु, महा-राष्ट्र, गोवा, दमन और दीव	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मणिपुर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर (पूर्व-विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए), केन्द्रीय विद्यालय संगठन